39वीं वार्षिक रिपोर्ट

2014–15

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट

31 मार्च, 2014–31 मार्च, 2015

मुद्रक एवं प्रकाशक :

सचिव
राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के
अंतर्गत एवं स्वायत्त शासी अनुसंधान संस्थान

18/2, सत्संग विहार मार्ग, स्पेशल इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र
नई दिल्ली–110067
फोन : 26569303, 26963421 फैक्स : 26852548
ईमेल : nipfp@nipfp.org.in वेबसाइट : www.nipfp.org.in

संयोजक एवं संपादक : समरीन बद्र
प्रिंटेड : रचित प्रिन्टर्स
ईमेल : rachitprinter.2005@gmail.com

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली
1976 से नीति संबंधी सूचना उपलब्ध करा रहा है।

विषय–वस्तु

पृष्ठ संख्या

1.	संस्थान का परिचय	1
2.	अनुसंधान कार्यकलाप	9
	केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के राजकोषीय/कराधान से संबंधित अध्ययन	9
	मेक्रो आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र नीति अध्ययन	10
	राज्य विकास अध्ययन	13
	अन्य अध्ययन	15
	शुरू की गई नई परियोजनाएं	17
3.	कार्यशालाएं, सेमिनार, बैठकें और सम्मेलन	18
4.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	22
5.	एनआईपीएफपी प्रकाशन (2014–15)	23
6.	पुस्तकालय और सूचना केंद्र	24
7.	कंप्यूटर/आईटी यूनिट	27
8.	मुख्य–मुख्य संकाय कार्यकलाप	28

संलग्नक

I.	अध्ययनों की सूची 2014–15	63
II.	एनआईपीएफपी आधार पत्र श्रृंखला	67
III.	आंतरिक सेमिनार श्रृंखला	68
IV.	31.03.2015 को शासी निकाय के सदस्यों की सूची	69
V.	समूल्य प्रकाशनों की सूची	72
VI.	एनआईपीएफपी संकाय की प्रकाशित सामग्री	77
VII.	31.03.2015 को स्टाफ सदस्यों की सूची	83
VIII.	31.03.2015 को प्रायोजक, कारपोरेट, स्थायी और साधारण सदस्यों की सूची	90
IX.	वित्त एवं लेखें	91

संस्थान के विषय में

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली की 39वीं वार्षिक रिपोर्ट, वित्त वर्ष के दौरान संस्थान के कार्य को एवं शासी निकाय और जनता उत्तरदायित्व के प्रति दायित्व को परिलक्षित करती है। नीचे, वर्ष 2014–15 के दौरान एनआईपीएफपी के कार्यकलापों की एक समीक्षा प्रस्तुत की गई है।

वार्षिक रिपोर्ट की एक डिजिटल प्रतिलिपि संस्थान के सरकारी वेबसाइट http:www.nipfp.org.in publicationsannual-reports से प्राप्त की जा सकती हैं।

शासी बोर्ड

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के शासी बोर्ड ने 3 अप्रैल 2012 को आयोजित अपनी बैठक में शासी निकाय का चार वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् 5 अप्रैल, 2012 से 4 अप्रैल, 2016 के लिए पुनर्गठन किया।

डा. विजय केल्कर, अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के शासी निकाय के प्रधान है। वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व श्री हंसमुख अधिया, राजस्व सचिव; श्री शक्तिकांत दास, सचिव, आर्थिक कार्य श्री अरविंद सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने किया। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व श्रीमती बलबीर कौर, सलाहकार, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा किया गया। श्री विवेक देवराय, सदस्य ने नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया। प्रायोजक राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं : डा. जे.एन. सिंह, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, गुजरात, श्री के. शनमुगम, आईएएस, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, तमिलनाडु ; और श्री के. उपेन्द्र नाथ बेहड़ा, आईएएस, अपर मुख्य सचिव (वित्त), ओडिशा सरकार, भुवनेश्वर; श्री राकेश झा, आईसीआईसीआई बैंक; श्री राणा कपूर, प्रधान, भारतीय एसोसिएटिड वाणिज्य और उद्योग चैम्बर और डॉ. ज्योत्सना सूरी, प्रधान, फिक्की, संस्थानों द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। शासी निकाय में तीन प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं : प्रोफेसर पुलिन बी. नायक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल, डॉ. डी.के. श्रीवास्तव, मुख्य नीति सलाहकार, "अर्नस्ट और यंग" और डॉ. सुदीप्तो मंडल, एमेरिटस प्रोफेसर, एनआईपीएफपी। सहयोगी संस्थानों से प्रतिनिधि थे : डॉ. शेखर शाह, महानिदेशक, एनसीएईआर, डॉ. रवि कांत, महानिदेशक, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज; और डॉ. प्रताप भानु मेहता, प्रधान और मुख्य कार्यकारी, नीति अनुसंधान केंद्र, श्री मनोज फड़नीस, प्रधान, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान, शासी निकाय में एक सहयोजित सदस्य हैं।

डॉ. रथिन रॉय, निदेशक, पदेन सदस्य–सचिव हैं ; और डॉ. आर. कविता राव, प्रोफेसर, अपनी बारी से एनआईपीएफपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान, शासी निकाय के लिए विशेष आमंत्रित थे : अध्यक्ष, सीबीडीटी, वित्त मंत्रालय और अध्यक्ष, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय।

(विवरण के लिए कृपया संलग्नक–IV देखें)

संपूरित और चल रही परियोजनाएं

आलोच्य वर्ष के दौरान, हमारे अनुसंधान लक्ष्य पांच प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत टीमों के माध्यम से प्राप्त हुए : कराधान और राजस्व, सार्वजनिक व्यय और राजकोषीय प्रबंधन, मेक्रोआर्थिक पहलू, अन्तर–सरकारी राजकोष संबंध एवं राज्य योजना और विकास।

चल रही अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत व्यय प्रबंधन के लिए समर्थन पर बल दिया जाता है तथा राजकोषीय,

वित्तीय और मौद्रिक नीति संबंधी समस्याओं पर विचार किया जाता है। संस्थान, सिफारिशों और रिपोर्टों के रूप में निरंतर रूप से नीतिगत सहायता प्रदान करता है ताकि वित्त मंत्रालय के विभागों को पेश आने वाली उभरती चुनौतियों का समाधान किया जा सके और राज्य की कर–योग्य क्षमता और संसाधन आबंटन के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के अनुसंधान कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे अध्ययनों को शामिल किया गया है जो नीतिगत सुधार और केंद्र में व साथ ही राज्यों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। व्यय प्रबंधन, मेक्रो आर्थिक नीति, मॉडलिंग और कर–नीति के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत की गई। लघु और मध्यम उद्योगों पर एक 'क्रॉस–कन्ट्री' अध्ययन के रूप में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नेटवर्क इंटरनेशनल, इस्लामाबाद द्वारा प्रायोजित केंद्रीय और राज्य सरकारों का राजकोषीय और कराधान सम्बद्ध अध्ययन पूरा किया गया जिससे यह भी पता चला कि कर प्रणाली में बने रहने के लिए लागत का अनुपालन सम्भवतः अर्थव्यवस्था के इस संघटक में विकास के लिए सम्भवतः एक बड़ी बाधा है।

संस्थान ने, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर कोर्ड बोर्ड के लिए भारत में वैयक्तिक आय–कर के तहत कर की अदायगी करने वालों की संख्या का पता लगाने और उन करदाताओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जो पद्धति के अंतर्गत बने रहने चाहिए, एक विश्लेषण उपलब्ध कराने के लिए एक प्रयास के रूप में करदाता आधार को विस्तृत बनाने के लिए एक विश्लेषणात्मक मॉडल के विकास के संबंध में कार्य किया।

संस्थान ने, जीएसटी सुधारों में अन्तर्निहित समस्याओं को उजागर करने के लिए जीएसटी के लिए राजस्व निष्प्रभावी दरों (आरएनआर) का अनुमान लगाने और वर्ष 2013–14 के लिए संख्या का निर्धारण करने का प्रयास किया।

यूआईडीएआई, योजना आयोग, भारत सरकार के अनुरोध पर, एनआईपीएफपी ने आधार–समर्थित सेवाओं की लागत वसूलने के लिए एक कार्यनीति की सिफारिश करने के लिए कीमत पद्धति और प्राधिकरण व ईकेवाईसी सेवाओं के संबंध में एक अध्ययन आयोजित किया। यूआईडीएआई के साथ एक सहयोग परामर्श परियोजना के अंतर्गत संस्थान ने यूआईडीएआई द्वारा प्रस्तावित निरन्तर नामांकन, अद्यतन बनाने और अन्य सेवाओं के संबंध में व्यवसाय योजना के मॉडलों का विकास किया और कार्यान्वयन हेतु सर्वोत्तम मॉडल की सिफारिश करते हुए विकसित प्रत्येक मॉडल के गुणावगुणों का उल्लेख किया।

मेक्रो आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रक नीति अध्ययनों के अंतर्गत, जैसे कि बहुपक्षीय संबंध प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आयोजित जी–20 प्रोजेक्ट वित्त पोषण अवस्थापना के विभिन्न स्रोतों और अवस्थापना निवेशों की मांग के विभिन्न पहलुओं की जांच की गई तथा भारत में अवस्थापना वित्तपोषण के लिए निधियों की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन पर प्रकाश डाला गया।

एक टीम में, चौदहवें वित्त आयोग के लिए 2015–19 की चौदहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान मेक्रो–फिस्कल कड़ी की समीक्षा करने के लिए मेक्रो–आर्थिक नीति प्रोत्साहन तैयार किए। मेक्रो–आर्थिक नीति मॉडलिंग रिपोर्टें, जिनमें इस बात की जांच की गई कि क्या अवधि 2010–15 के संबंध में चालू खाता शेष और जीडीपी वृद्धि के बीच कोई संतुलन है, योजना आयोग को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में 12वीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न बाह्य दबावों के प्रभाव का भी मूल्यांकन किया गया।

इसी बीच, एनआईपीएफपी मेक्रो–आर्थिक नीति प्रोत्साहन मॉडल को सतत रूप से अद्यतन बनाया गया और

उभरती स्थितियों व नीतिगत प्रश्नों के प्रत्युत्तर में आशोधित किया गया।

हमारी अनुसंधान टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुटों से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से **एनआईपीएफपी–डीईए रीसर्च** प्रोग्राम की कार्यावधि का विस्तार किया गया। अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत न केवल, एक खुली अर्थव्यवस्था पद्धति में राजकोषीय, वित्तीय और मौद्रिक नीति के बड़े प्रश्नों पर और आगे विचार किया जाएगा बल्कि अनिवार्य के रूप में परिकल्पित, मंत्रालय के लिए चिंता के सामयिक मुद्दों के संबंध में एक अनुसंधान–उन्मुख नीतिगत सहायता फ्रेमवर्क भी, एफएसएलआरसी सिफारिशों सहित, उपलब्ध कराया जाएगा।

अपने अनुसंधान आधार का विस्तार करने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए एनआईपीएफपी ने भारत में व्यवसाय चक्र लक्षणों के संबंध में अनुसंधान कार्य शुरू किया।

फर्म वित्त पोषण और उधार निर्णयों के संबंध में शैक्षिक साहित्य में योगदान करने और भारत में औद्योगिक गतिकी समझने के लिए संस्थान द्वारा भारतीय फर्मों द्वारा बाह्य उधार लेने की पद्धति का विश्लेषण करने के लिए संस्थान ने एक अध्ययन आयोजित किया।

एक स्पष्ट–परिभाषित और पारदर्शी संकेतकों के आधार पर शासन–निष्पादन की उद्देश्यपरक रेटिंग, राज्यों के बीच शासन प्रतिस्पर्धा की उभरती प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण के लिए एक उपयोगी साधन सिद्ध होगी। इन निष्कर्षों का, सेवा वितरण के रूप में शासन के संबंध में भारतीय राज्यों के निष्पादन का मूल्यांकन करके, एक टीम द्वारा और आगे अध्ययन किया गया।

संस्थान द्वारा शुरू किए गए, भारत में सब्सिडियों के स्तर और संरचना का अनुमान लगाने के लिए एक विस्तृत अध्ययन से, जहां कहीं उपयुक्त हों, वैचारिक परिशुद्धियां शामिल करते हुए 1987–88 से वर्तमान तक सब्सिडियों का एक अद्यतन और विस्तृत पुनर्अनुमान उपलब्ध होगा।

संस्थान द्वारा शुरू किए गए राज्य विकास अध्ययनों में, एफआरबीएम अधिनियम, 2012–13 के संबंध में ओडिशा सरकार के अनुपालन की समीक्षा पूरी की गई – जो प्रावधानों के अनुपालन की सीमा के बारे में विधानमंडल और सामान्य जनता को जानकारी प्रदान करने की सांविधिक प्रक्रिया का एक भाग है।

राज्य और जिला स्तर पर – एमडीजी संकेतकों के विरूद्ध मध्य प्रदेश की उपलब्धियों का एक समेकित पुनर्विलोकन उपलब्ध कराने के लिए, यूनिसेफ, भोपाल द्वारा प्रायोजित अध्ययन से, मार्जिनकृत और बहिष्कृत समूहों की वंचनाओं और भेद्यताओं को समझने के लिए साम्यता पैमाने का इस्तेमाल करते हुए, मध्य प्रदेश के विकास परिणामों (एमडीजी फ्रेमवर्क के विरूद्ध) को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा उपलब्ध होगी।

गोआ सरकार के अनुरोध पर, आगामी बजट वर्ष के प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्यों और दो विगत वर्षों में राजकोषीय नीति उद्देश्य, राजस्व सुदृढ़ीकरण उपायों, व्यय पुनर्गठन और पूर्वानुमानित राजकोषीय लक्ष्यों की व्यवस्था करते हुए वर्ष 2015–16 के लिए गोआ की मध्यावधिक राजकोषीय नीति के संबंध में एक रिपोर्ट प्रगति पर है।

उपरोक्त के अनुसार, एफआरबीएम अधिनियम–2012–13 के संबंध में सिक्किम सरकार की अनुपालन रिपोर्ट पर समीक्षा की सिक्किम सरकार प्रायोजित रिपोर्ट के अंतर्गत राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन किया जाएगा। एफआरबीएम अधिनियम, सिक्किम 2015–16 के अंतर्गत मध्यावधि राजकोषीय योजना में राजकोषीय नीति उद्देश्य

और आगामी बजट वर्ष में प्रस्तावित राजकीय लक्ष्यों और विगत दो वर्षों के संबंध में विचार किया जाएगा।

भारतीय राज्यों के बीच शासन की कोटि को समझने और कुछेक राज्य सरकारों द्वारा किए गए राजकोषीय चुनावों की प्रणाली को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना आलोच्य वर्ष के दौरान शुरू की गई है। इस अध्ययन से भारत में शासन और सार्वजनिक नीति के बीच संबंधों का अध्ययन करने में योगदान मिलेगा।

बिहार राज्य की कराधान क्षमता, सार्वजनिक व्यय मुद्दों, केंद्र–राज्य मुद्दों, राजकोषीय असंतुलनों और समायोजनों तथा राजकोषीय देनदारी और संधारणीयता का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, बिहार राज्य वित्त–कर युक्तिकरण के लिए नीतिगत विकल्पों और राजस्व जुटाने के संबंध में विश्लेषण करने के उद्देश्य से, संस्थान में एक अध्ययन आयोजित किया गया है।

समावेशी विकास की समस्या का समाधान करने के लिए संस्थान ने, नए राज्यों के सृजन के साथ समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अध्ययन करने के वास्ते एक परियोजना शुरू की है। इस अध्ययन के अंतर्गत, यह अनुमान लगाने के लिए कि क्या राज्य सृजन के फलस्वरूप एक विशिष्ट राजकोषीय एजेंसी का, विशेष रूप से सार्वजनिक खर्च की पद्ध ति और कराधान प्रणाली में परिवर्तनों के माध्यम से अभिव्यक्त झारखण्ड और छत्तीसगढ़ की एक तुलना की गई है। भारत में नव सृजित राज्यों का और आगे अध्ययन करने के लिए, दोनों राज्यों में खनन में राजकोषीय अनुसंधान इस वर्ष संस्थान के कार्य में एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। माइक्रो–आर्थिक नीति की दृष्टि से और फर्म–स्तर प्रतिस्पर्धात्मकता पर इसके प्रभाव का अलग–अलग अनुसंधान परियोजना के रूप में भारत के खनन क्षेत्रक का अध्ययन किया गया है।

व्यय को नियंत्रित करने के लिए केंद्र के लिए नीतिगत सिफारिशें उपलब्ध कराने के संस्थान के प्रयास स्वरूप, राजस्व और व्यय आबंटनों की पद्धति तथा पांच उभरती बाजार–अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील, चीन, इण्डोनेशिया, रूस और दक्षिण अफ्रीका में अंतर–सरकारी राजकोषीय संबंधों के साथ डील करने वाली परंपराओं की समीक्षार्थ 14वें वित्त आयोग के लिए एक अध्ययन आयोजित किया गया।

एक अनुसंधान टीम ने, उच्च खर्च न हुए शेषों को समझने और एमजीएनआरईजीएस जैसे बड़े ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में धनराशि प्रवाह पद्धति को समझने की दिशा में कार्य किया। इस परियोजना के अंतर्गत एक पुस्तक प्रकाशित की गई।

देश के भिन्न–भिन्न वित्तीय क्षेत्रों के संबंध में अनुसंधान कार्य के साथ–साथ संस्थान ने हवाई अड्डा क्षेत्र में जोखिम का आकलन करने और इक्विटी पर प्रतिफल की उचित दर का अनुमान लगाने के लिए एक परियोजना शुरू की है।

बहुपक्षीय मंचों, जैसे कि जी–20, ''ब्रिक्स'' व अन्य पर उठने वाले विभिन्न आयामों को बेहतर ढंग से समझने के प्रयासस्वरूप संस्थान एक नीतिगत परिप्रेक्ष्य की और आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार में अनुसंधान और क्षमता विकास को सुदृढ़ करने के लिए उपायों की सिफारिश करेगा।

संस्थान द्वारा शुरू की गई ''जेण्डर बजटिंग'' पर आईएमएफ ग्लोबल प्रोजेक्ट के अंतर्गत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 25 देशों के लैंगिक बजट अनुभवों का अध्ययन किया जाएगा।

संस्थान ने, व्यय प्रबंधन आयोग, वित्त मंत्रालय के प्रयोजन के तहत एक नया नीति अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है।

जैव–विविधता वित्त अंतर के मात्राकरण और संसाधन जुटाव कार्यनीतियां विकसित करने के लिए संस्थान द्वारा ''भारत में जैव–विविधता वित्त पहल'' प्रोजेक्ट शुरू की गई है।

एसएचए 2011 के अनुसार, भारत के ''राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखों'' के संबंध में सार्वजनिक व्यय के श्रेणीकरण को सतत रूप से अद्यतन बनाने के लिए संस्थान ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य पद्धति संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से रखरखाव किया गया है (सभी परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्नक–। में दिया गया है)।

संकाय की मुख्य–मुख्य बातें

भारत सरकार के नीति निर्माण निकायों में एनआईपीएफपी के सदस्य सक्रिय रूप से भाग लेते हैं जो केंद्र और राज्यों की आर्थिक नीति को साकार रूप देते हैं।

डॉ. विजय केलकर, अध्यक्ष, एनआईपीएफपी, ''पद्म विभूषण'', पूर्व अध्यक्ष, तेरहवां वित्त आयोग, पूर्व पेट्रोलियम सचिव, भारत, पूर्व वित्त सचिव, भारत और पूर्व भारतीय कार्यकारी निदेशक, आईएमएफ ने 1 नवंबर, 2014 को कार्यभार संभाला। डॉ. केलकर, वर्ष 2030 तक आयात निर्भरता में संधारणीय कटौति के साथ तेल और गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक सड़क नक्शा तैयार करने के वास्ते भारत सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष हैं। डॉ. केलकर, अवस्थापना विकास के पीपीपी मॉडल पर पुनर्विचार और आशोधन करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा गठित समिति के भी अध्यक्ष हैं।

डॉ. रथिन रॉय, निदेशक, ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समितियों में अपनी सदस्यता स्थिति बनाए रखी – सातवां केंद्रीय वेतन आयोग, भारत सरकार, भारत में निर्धनता का अनुमान लगाने के संबंध में प्रधानमंत्री का कार्य दल, नेशनल इंस्टीट्यूशन फार ट्रांसफोर्मिंग इण्डिया (''नीति'' आयोग) ; ''यूनेस्को'' के लिए विशेषज्ञ समूह ; एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण तथा विभाजन के पश्चात् आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य के लिए नई राजधानी के संबंध में विभिन्न विकल्पों का अध्ययन करने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत गठित समिति। वह, जी–20 मुद्दों पर वित्त मंत्री के सलाहकार समूह का एक सदस्य, आईएएस अधिकारियों के लिए तृतीय तीन वर्षीय साइकिल आफ मिड–कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम (एनसीटीपी) के लिए (2013–14, 2014–15 और 2015–16) प्रोजेक्ट प्रबंधन समिति (पीएमसी) के एक सदस्य बने रहें।

डॉ. राय, नीति के कार्यान्वयन के लिए समग्र दिशा निर्देश हेतु, मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन की अध्यक्षता के तहत राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद (3 सितंबर, 2013 के बाद से), चौदहवें वित्त आयोग के लिए केंद्रीय ज्ञापन तैयार करने के लिए लघु समूह, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, शासी बोर्ड, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली ; भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों के लिए चालू साधनोपाय (डब्ल्यूएमए)/ ओवरड्राफ्ट (ओडी) स्कीम सुविधा की समीक्षा करने के लिए सलाहकार समिति ; और शासी निकाय, राष्ट्रीय उत्तम शासन केंद्र (एनसीजीजी), नई दिल्ली के सदस्य हैं।

डॉ. तपस सेन, प्रोफेसर, भारत में स्कूल शिक्षा के संबंध में वित्तीय सांख्यिकी विशेषज्ञ समूह, एचआरडी मंत्रालय, भारत सरकार के एक सदस्य बन गए। वह, शैक्षिक वित्त विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए), नई दिल्ली की शैक्षिक सलाहकार समिति में भी शामिल हो गए।

डॉ. अजय शाह, प्रोफेसर, कार्य बल, रेजोल्युशन कारपोरेशन सार्वजनिक ऋण प्रबधंन एजेंसी, कार्यबल, वित्तीय अपीलीय अधिकरण, कार्यबल, वित्तीय डेटा प्रबंधन

केंद्र और पेंशन सलाहकार समिति के सितंबर 2014 में एक सदस्य बन गए। वह, जून 2014 में ''कामन क्लीयरिंग फार कामोडिटी एक्सचेंजिज संबंधी कार्यदल'' के भी एक सदस्य बन गए।

डॉ. एन.आर. भानुमूर्ति, प्रोफेसर, 14वें वित्त आयोग अवार्ड, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व घाटा अनुदान जारी करने के लिए केंद्रीय मॉनीटरिंग समिति (सीएमसी) के एक सदस्य बने रहे। वह, फोकस ग्रुप आन रेवेन्यु फोरकास्टिंग, कर प्रशासन सुधार आयोग, भारत सरकार 2014–15 के भी एक सदस्य बन गए। वह, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के एक सदस्य हैं।

डॉ. मीता चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखों संबंधी विशेषज्ञ समूह समिति के एक सदस्य के रूप में और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल संबंधी विशेषज्ञ समूह का एक सदस्य नियुक्त किया गया। इन दोनों का गठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

सरकारी संस्थानों के बीच ज्ञान आधार और क्षमता निर्माण में योगदान करने के अपने प्रयासों के क्रम में संस्थान ने, **''सार्वजनिक ऋण प्रबंधन और एफआरबीएम अधिनियम तथा इसके कार्यान्वयन के संबंध में भारतीय नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लिए एक प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रम शुरू किया है।**

राजकोषीय नीति के डिजाइन और रूपरेखा की समझबूझ में सुधार करने के लिए संस्थान ने अपने परिसर में एक पांच दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम **''भारतीय सांख्यिकीय सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षार्थियों के लिए ''राजकोषीय और मौद्रिक नीति''** पर आयोजित किया। एक पांच दिन का **''मिड कैरियर प्रोग्राम''** आन **''फिस्कल पॉलिसी एण्ड मेक्रोइकोनामिक मैनेजमेंट''**, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए (आईएएस, आईएफएस और आईपीएस)। ''भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और सहायता'' कार्यक्रम के अंतर्गत, ''एफआरबीएम अधिनियम'' और ''सार्वजनिक ऋण प्रबंधन'' पर दो दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम की संस्थान में व्यवस्था की गई। संस्थान द्वारा ''सार्वजनिक वित्त प्रशिक्षण'' का डिजाइन, आलोच्य वर्ष के भिन्न–भिन्न समयों पर पांच दिन के माड्यूलों के रूप में ''भारतीय आर्थिक सेवा परिवीक्षार्थियों (आईईएस)'', ''भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षार्थियों'' के लिए और भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस)'' के अधिकारी प्रशिक्षार्थियों के लिए किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे कि ओईसीडी, जीआईएनआई, आईआईडीएस, बीएनयू, आईपीएस, आईडीआरसी–सीआरडीआई, आईएमएफ, भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक के साथ एनआईपीएफपी की भागीदारी के परिणामस्वरूप अनेक कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रख्यात शैक्षिक संस्थानों, जैसे कि ओसाका स्कूल आफ इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी ; ड्यूक सेंटर फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट, सेंटर फार पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर), इण्डियन काउंसिल फार रीसर्च आन इंटरनेशनल इकोनामिक रीलेशंस (आईसीआरआईईआर), इण्डिया डेवलपमेंट फाउंडेशन (आईडीएफ), नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनामिक रीसर्च (एनसीएईआर), शांघाई इंस्टीट्यूट्स आफ इंटरनेशनल स्टडीज, केनेडी स्कूल आफ गवर्नमेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी,

और आईआईटी खडगपुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ एनआईपीएफपी की भागीदारी के फलस्वरूप बहुत से अन्योन्यक्रिया सेमिनार आयोजित हुए।

"एनआईपीएफपी – डीईए अनुसंधान कार्यक्रम" के अंतर्गत संस्थान ने "इण्डियाज मेक्रोइकोनोमिक फ्रेमवर्क एण्ड डेट सस्टेनेबिलिटी एनेलिसिस" पर दो दिन की एक कार्यशाला आयोजित की। नीतिगत मोर्चे पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एनआईपीएफपी ने, "टैक्स पॉलिसी एण्ड एन्टरप्राइज डिपार्टमेंट इन साउथ एशिया" पर संस्थान में एक दिन की नीतिगत कार्यशाला आयोजित करने के लिए, जीआईआई, आईआईडीएस, बीएनयू, आईपीएस और आईडीआरसी के साथ सहयोग किया।

एनआईपीएफपी, सीपीआर, आईसीआरआईईआर, आईडीएफ और एनसीएईआर द्वारा आयोजित "पांच संस्थान वार्षिक सेमिनार" में केंद्रीय बजट पर चर्चा की गई।

ओईसीडी के सहयोग से संस्थान में आयोजित एक दिन के एक सेमिनार में आर्थिक चुनौतियों के प्रति नए दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई।

संस्थान के सदस्यों ने शांघाई इंस्टीट्यूट फार इंटरनेशनल स्टडीज, चीन के प्रोफेसर लियु झोंगयी के साथ "चीन–भारत संबंध और मोदी युग में आर्थिक सहयोग" पर एक अन्योन्यक्रिया चर्चा में भाग लिया। राजनयिक मिशनों से बहुत से महानुभावों ने समारोह में भाग लिया।

वार्षिक घटना के रूप में **"पेपर्स इन पब्लिक इकोनोमिक्स एण्ड पॉलिसी" (पीपीईपी)** पर दो दिन का एक सम्मेलन एनआईपीएफपी में आयोजित किया गया। संस्थान के संस्थापक–निदेशक डॉ. राजा चेलैय्या की स्मृति में संस्थान का वार्षिक व्याख्यान डॉ. सी. रंगाराजन, पूर्व अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद और पूर्व गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने "इश्यूज इन इण्डियाज एक्सटर्नल सेक्टर" पर दिया।

शीर्ष से : इरेनेहोर्स, बेजिंग में वरिष्ठ सलाहकार, ओईसीडी; बी.आर. भट्टाचार्य, कुलपति, ज.ने.वि.; अनजेला जेन विलकिंसन, "स्ट्रेटेजिक फोरसाइट के लिए परामर्शदाता, ओईसीडी।

शीर्ष: बाएं से : प्रोफेसर इलेक, एएनयू ; डॉ. आलोक शील, अपरमुख्य सचिव और नई दिल्ली में विशेष प्रतिनिधि, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम ।

ऊपर–बाएं से: पीटर ड्रिस्डाले, पूर्व प्रोफेसर, अर्थशास्त्र और प्रधान, पूर्व एशियाई आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो और पूर्व एशियाई फोरम, क्राफोर्ड स्कूल आफ पब्लिक पॉलिसी, एएनयू ; डेविड विनेस, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ।

''इण्डिया–आस्ट्रेलिया राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस'' में जी–20 देशों पर एक चर्चा आयोजित की गई जिसका आयोजन एनआईपीएफपी, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन (इण्डिया) और आस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी (एएनयू) के ईस्ट–एशिया ब्यूरो आफ इकोनोमिक रीसर्च (ईएबीईआर) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया ।

(आंतरिक सेमिनार श्रृंखला के लिए संलग्नक–III देखें ।)

घटनाएं

संस्थान को, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा इसके प्रायोजक राज्यों से वार्षिक सहायता–अनुदान प्राप्त होता है। संस्थान के अध्यक्ष की अध्यक्षता में संस्थान के शासी निकाय की बैठक, संस्थान के शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय खोजों हेतु नीतिगत निर्देश और समर्थन प्रदान करने के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान दो बार आयोजित की गई।

पूर्व अध्यक्ष, डा. सी. रंगाराजन की कार्यावधि समाप्त होने के बाद डा. विजय केलकर ने 1 नवंबर, 2014 को अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। डा. एम. गोविन्द राव, पूर्व निदेशक को 10.11.2014 से ऐमेरिटस प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। पहले उन्हें 1.2.2013 से 31.12.2014 तक की अवधि के लिए चौदहवें वित्त आयोग का एक सदस्य नियुक्त किया गया था। डा. इला पटनायक, प्रोफेसर (आरबीआई पीठ) को, वित्त मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार के रूप में संविदात्मक कार्यभार संभालने के लिए प्रारंभ में 1 मई 2014 से दो वर्ष की अवधि के लिए वेतनरहित छुट्टी मंजूर की गई। डा. सुदीप्तो मंडल, पूर्व प्रोफेसर को 1.2.2013 से 31.12.2014 तक की अवधि के लिए चौदहवें वित्त आयोग को एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया ; और डा. पिनाकी चक्रवर्ती, 8.5.2013 से 31.12.2014 तक की अवधि के लिए एक सलाहकार के रूप में चौदहवें वित्त आयोग में प्रतिनियुक्ति पर थे।

डॉ. श्रुति त्रिपाठी को 30.4.2014 से अर्थशास्त्री के रूप में और डा. मोहम्मद आसिफ मुस्तफा खान को 31.10.2014 से वरिष्ठ पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

डी. सिमंती बंधोपाध्याय, सहायक प्रोफेसर, अजय हालेन, कनिष्क अर्थशास्त्री और रोमाशा मिश्रा, लेखा अधिकारी, संस्थान छोड़ गए।

रीता वाधवा, संपादक और श्री एस.एन. शर्मा, सहायक ने आलोच्य वर्ष के दौरान अधिवार्षिकी की आयु प्राप्तकी।

2. अनुसंधान कार्यकलाप

केंद्रीय और राज्य सरकार के राजकोषीय/ कराधान सम्बद्ध अध्ययन

सम्पूरित अध्ययन

''टैक्स पॉलिसी एण्ड इंटरप्राइज डेवलपमेंट इन साउथ एशिया'', आर. कविता राव, अमर ज्योति महन्ता, कौशिक भद्रा।

यह लघु और मंझले उद्यमों पर कर नीति के प्रभाव के संबंध में एक परस्पर देश अध्ययन है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी हो गई है तथा वर्तमान वर्ष में एक प्रसार कार्यशाला आयोजित करने का प्रस्ताव है। अध्ययन के परिणामों से पता चलता है कि यद्यपि अधिकांश एसएमई वर्तमान कर प्रणाली का भाग हैं, तथापि प्रोत्साहनों का प्राथमिकतापूर्ण रूप छूटों की तुलना में कम कर दरें प्रतीत होता है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि कर प्रणाली में बने रहने के लिए उच्च अनुपालन लागत संभवतः अर्थव्यवस्था के इस घटक में प्रगति के मार्ग में बाधक है।

चल रहे अध्ययन

''स्टडी आन डेवलपमेंट आफ एन एनेलिटिकल मॉडल फार वाइडनिंग दि टैक्सपेयर्स बेस'' आर. कविता राव, सच्चिदानन्द मुखर्जी, सुधांशु कुमार, डी.पी. सेनगुप्ता, सुरांजली टंडन, देबोऋषि ब्रह्मचारी।

इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में व्यक्तिगत आय कर के अंतर्गत कर अदा करने वाले करदाताओं की संख्या में वृद्धि का विश्लेषण करना और उन करदाताओं की संख्या का

पूर्वानुमान लगाने के लिए कि पद्धति के अंतर्गत कितने करदाता होने चाहिए, एक विश्लेषणात्मक मॉडल का विकास करना है।

एस्टीमेटिंग आरएनआर फार जीएसटी फार दि ईअर 2013–14 आर. कविता राव, पिनाकी चक्रवर्ती, कौशिक भाद्र।

इस अध्ययन के अंतर्गत जीएसटी के संबंध में राजस्व निष्प्रभावी दरों पर पुनर्विचार किया जाएगा तथा वर्ष 2013–14 के संबंध में संख्या का अंदाजा लगाया जाएगा।

मैक्रो आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र नीतिगत अध्ययन

संपूरित अध्ययन

एनआईपीएफपी–यूआईडीएआई स्टडी आन प्राइसिंग दि आथेनटीकेशन एण्ड ईकेवाईसी सर्विसिज, अजय शाह, सुयश राय, शुभो रॉय।

''भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण'' (यूआईडीएआई) ने, आधार–समर्थित सेवाओं की लागत वसूल करने के लिए एक कार्यनीति की सिफारिश करने के वास्ते एनआईपीएफपी से अनुरोध किया। यूआईडीएआई, आधार–समर्थित ई–केवाईसी तथा प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करता है। प्रमाणीकरण सेवाएं, बायोमीट्रिक सूचना (फिंगरप्रिंट और आइरिस स्केन) तथा ऑनलाइन पासवर्ड (ओटीपी) पर आधारित है। ये सेवाएं प्रदान करने की लागत है, अवस्थापना स्थापित करने की लागत और सेवाएं प्रदान की आवर्ती लागत। एनआईपीएफपी ने, विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी ही सेवाओं के लिए बाजारों से सिद्धांत और साक्ष्य के आधार पर इस मुद्दे का अध्ययन किया।

एनआईपीएफपी–यूआईडीएआई कंसल्टेशन प्रोजेक्ट फार डवलपिंग वेरियस माड्ल्स आफ बिजनिस प्लान फार कंटीन्यूयस एनरोलमेंट, अपडेट एण्ड अदर सर्विसिज आफर्ड/टूबी आफर्ड बाई यू आई डीएआई, अजय शाह, सुयश राय, शुभो रॉय, संहिता सप्तनेकर, स्मृति शर्मा।

भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एनआईपीएफपी से उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए एक उपयुक्त व्यवसाय मॉडल की सिफारिश करने के साथ अनुरोध किया। अनुमान लगाया गया था कि व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत सेवाओं के लिए कीमत पद्धति कार्यनीति सम्मिलित की जाएगी। एनआईपीएफपी टीम ने पारि–पद्धति भागीदारों के साथ, नामांकन और उसे अद्यतन बनाने के क्षेत्र में कार्यरत् के साथ भी परामर्श आयोजित किया और यूआईडीएआई की अन्योन्यक्रिया का अपने भागीदारों और उपभोक्ताओं के साथ विश्लेषण किया। एनआईपीएफपी टीम ने यूआईडीएआई द्वारा निरंतर नामांकन, उन्हें अद्यतन बनाने व प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के संबंध में व्यवसाय योजना के मॉडलों का विकास किया तथा कार्यान्वयन हेतु सर्वोत्तम मॉडल की सिफारिश करते हुए, विकसित प्रत्येक मॉडल के गुणावगुणों का उल्लेख किया। रिपोर्ट में, नामांकन को प्रोत्साहित करने और सेवाओं को अद्यतन बनाने के लिए कीमत पद्धति कार्यनीति की सिफारिश की। व्यवसाय मॉडल का विकास करते समय, टीम ने उच्च गुणवत्ता, डेटा सुरक्षा, आधार डेटाबेस की व्यापक पहुंच आदि बनाए रखने के उद्देश्यों को देखते हुए विकल्पों का मूल्यांकन किया।

फाइनेंसिंग फार इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट–जी 20 प्रोजेक्ट रामप्रसाद सेनगुप्ता, सच्चिदानन्द मुखर्जी, मनीश गुप्ता।

इस अध्ययन का उद्देश्य वित्तीय अवस्थापना के विभिन्न स्रोतों और अवस्थापना निवेशों की मांग की जांच करना है तथा भारत में अवस्थापना वित्त पोषण के लिए

धनराशि की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेलपन पर प्रकाश डाला गया है। इस असंतुलन का समाधान करने तथा भारत में अवस्थापना वित्त के पारंपरिक स्रोतों की बाधाओं को देखते हुए इस पत्र में दीर्घावधिक अवस्थापना वित्त जुटाने के वास्ते एक वैकल्पिक रूपरेखा के रूप में ''क्रेडिट संवर्धन स्कीम (सीईएस) सुझाई गई है। इसमें अवस्थापना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधिक निवेश के लिए विश्व वित्त का लाभ उठाने के वास्ते एक विकल्प के रूप में सीईएस का विस्तार करने का सुझाव दिया गया है। क्रेडिट संवर्धन की सुझाई गई स्कीम को उन स्रोतों से वित्त जुटाने के लिए जी–20 स्तर तक बढ़ाया जा सकता है, जो पहले अवस्थापना परियोजनाओं में निवेश करने से हिचकिचा रहे थे (अर्थात् पेंशन और बीमा निधि)। इसमें जी–20 स्तर पर इस स्कीम को आपरेशनल बनाने के लिए एक संभावित प्रणाली भी सुझाई गई है। प्रस्तावित स्कीम, जी–20 देशों के लिए विशिष्ट रूप से नहीं है किंतु अवस्थापना क्षेत्र के लिए दीर्घावधिक वित्त का लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग अन्य देशों द्वारा किया जा सकता है (विकासशील देशों द्वारा भी, जिनकी निम्न सोवरन रेटिंग है)।

मैक्रोइकोनोमिक पॉलिसी सिमुलेशन्स फार दि फोर्टीन्थ फाइनेंस कमीशन, एन.आर. भानुमूर्ति, सुकन्या बोस, पर्मा देवी अधिकारी।

इस परियोजना के अंतर्गत, चौदहवें वित्त आयोग की 2015–2019 अवधि के दौरान मैक्रो–राजकोषीय संयोजनों की समीक्षा करने के लिए भारत के वास्ते एक स्थायी मैक्रो आर्थिक रूपरेखा सुझाने का प्रयास किया गया है। संशोधित एनआईपीएफपी मॉडल का उपयोग नीतिगत अभिप्रेरण के लिए किया गया है जो चौदहवें वित्त आयोग की अवधि के लिए संगत है। विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत सम्मिलित हैं: (क) सातवें वेतन आयोग अवार्ड का दबाव, (ख) घाटे और ऋण को लक्षित करना, (ग) उच्च विकास का लक्ष्य निश्चित करना और (घ) बाह्य दबावों का प्रभाव।

मिड–टर्म एप्राइजल फार दि ट्वेल्थ प्लान पीरियड, एन.आर. भानुमूर्ति, सुकन्या बोस।

आलोच्य वर्ष के दौरान, इस पंचवर्षीय (2010–15) प्रोजेट के अंतर्गत संस्थान ने दो रिपोर्टें योजना आयोग को प्रस्तुत की जो 12वीं योजना की मध्यावधि के आकलन के लिए संगत थी। रिपोर्टों में इस बात की जांच की गई है कि क्या चालू खाता शेष और जीडीपी विकास के बीच कोई ट्रेड आफ है और यह भी कि 12वीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न बाह्य दबावों का भी कोई प्रभाव है।

चल रहे अध्ययन

फोर्थ एनआईपीएफपी–डीईए अनुसंधान योजना

अजय शाह, अनिरूद्ध बर्मन, अपूर्व गुप्ता, अतुल कुमार सिंह, कुशाग्र प्रियादर्शी, नीना जैकब, प्रमोद सिंहा, प्रतीक दत्ता, पुरूजारेवाल, राधिका पाण्डेय, शेखर हरी कुमार, शुभो रॉय, सुयश राय, रचना शर्मा, सहाना राय चौधरी, अरविंद हमारान, मोहित देसाई, ललित कान्ट्रेक्टर, आशीष अग्रवाल, मेहताब सिंह हंस, मयंक मिश्रा, भार्गवी झावेरी, पायल डे,

संहिता सप्तनेकर, स्मृति शर्मा, समीराज इलापावुलुरी, शेफाली मल्होत्रा।

एनआईपीएफपी–डीईए अनुसंधान योजना आयोजित करने के लिए, एनआईपीएफपी और आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय, भारत सराकर के बीच 3 अप्रैल, 2014 को हस्ताक्षरित, यह चौथा सहमति ज्ञापन है। कार्यक्रम का उद्देश्य, डीईए और वित्त मंत्रालय को पेश आने वाली अनेक नवीन चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुसंधान इनपुट उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के अंतर्गत एक खुली अर्थव्यवस्था पद्धति में राजकोष, वित्तीय तथा मौद्रिक नीति के बड़े प्रश्नों का समाधान किया जाएगा बल्कि मंत्रालय के हित से संबंधित सामयिक मुद्दों के लिए अनिवार्य के रूप में एक अनुसंधान उन्मुख नीतिगत समर्थन की भी व्यवस्था की जाएगी। उद्देश्यों की समग्र रूपरेखा के अंदर एनआईपीएफपी, एफएसएलआरसी सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यकलाप भी आयोजित करेगा।

रीसर्च ऑन बिजनिस साइकिल्स, अजय शाह, रूद्राणी भट्टाचार्य, राधिका पाण्डेय।

इस परियोजना का उद्देश्य भारत में व्यवसाय चक्र लक्षणों के संबंध में नया अनुसंधान आयोजित करना है।

फारेन बोरोइंग्स बाई इण्डियन फर्म्स : इम्प्लीकेशन्स फार ग्रोथ एण्ड मेक्रोइकोनोमिक स्टेबिलिटी, अजय शाह, अपूर्व गुप्ता।

प्रोजेक्ट से फर्म वित्त पोषण और उधार लेने के निर्णयों के संबंध में शैक्षिक साहित्य में योगदान प्राप्त होगा तथा भारत में औद्योगिक गतिकी को समझने में योगदान मिलेगा। इस परियोजना के अंतर्गत भारतीय फर्मों द्वारा विदेश से उधार लेने की पद्धति का विश्लेषण किया जाएगा। इसके अंतर्गत ऐसे उधार लेने के संभावित उत्प्रेरकों का पता चलेगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत ऐसा करने वाली फर्मों के निष्पादन पर विदेशी प्रभावों का विश्लेषण किया जाएगा तथा उनकी तुलना उन फर्मों के निष्पादन के साथ की जाएगी जो उधार नहीं लेते हैं। अंत में इसके अंतर्गत मेक्रो–आर्थिक जोखिमों का आकलन किया जाएगा जो भारतीय फर्मों द्वारा बाह्य उधारों से सम्बद्ध हैं तथा विकास बनाम मेक्रो–आर्थिक स्थिरता के अप्रत्यक्ष जोखिम–रिवार्ड ट्रेड–आफ के साथ जुड़े हैं।

लेवल एण्ड कम्पोजीशन आफ सब्सिडीज इन इण्डिया : 1987–88 टू 2011–12, सुदीप्तो मंडल, एच.के. अमरनाथ, सताद्रु सिकदर

लगभग 25 वर्ष पहले मंडल और राव ने कुल मिलाकर 1987–1988 के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए वसूल न हुई लागत के रूप में परिभाषित भारत में सब्सिडियों की मात्रा और संचरना के मूल अनुमान प्रकाशित किए थे। उसके बाद से केंद्रीय सरकार बजटों में सब्सिडियों के अनेक अनुवर्ती अनुमान लगाए गए हैं। तब से, केंद्रीय सरकार के बजटों में सब्सिडियों के संबंध में अनेक अनुमान लगाए गए हैं। वित्त मंत्रालय के श्वेत पत्र के रूप में और कुछ एनआईपीएफपी द्वारा खुद ही किए गए अध्ययनों के रूप में। तथापि, केंद्रीय और राज्य सरकारों के संबंध में कुल मिलाकर सब्सिडियों की मात्रा और संरचना के एक विस्तृत अध्ययन की पुनरावृत्ति अभी तक नहीं की गई है। ऐसा अध्ययन आयोजित करने के लिए बहुत से क्षेत्रों से अनुरोधों के बाद भी नहीं किया गया। इन अनुरोधों के प्रत्युत्तर में इस अध्ययन से 1987–88 से नवीनतम अवधि तक सब्सिडियों का एक अद्यतन और व्यापक पुनर्अनुमान प्राप्त होगा, उपयुक्त समझे जाने पर वैचारिक परिशोधन सम्मिलित किया गया है। यह एक एनआईपीएफपी–प्रायोजित अध्ययन है।

मेक्रोइकोनामिक पॉलिसी सीमुलेशन्स, सुदीप्तो मंडल, एन.आर. भानुमूर्ति, सुकन्या बोस, परमा देवी अधिकारी।

एनआईपीएफपी मेक्रो–आर्थिक नीति अभिप्रेरण मॉडल एक सतत रूप से अद्यतन व आशोधित मॉडल है जो उभरती स्थितियों और नीतिगत प्रश्नों के संदर्भ में है। वर्तमान वर्ष के दौरान, डेटाबेस में आमूल परिवर्तन किया जाएगा तथा मॉडल को नई जीडीपी डेटा श्रृंखला के आधार पर पुनः तैयार किया जाएगा। संशोधित मॉडल का उपयोग बदलती विश्व स्थितियों के निहितार्थों, ईयू से ग्रीस का बहिर्गमन अथवा नहीं, भिन्न–भिन्न तेल कीमत स्थितियों के अंतर्गत यूएस टेपरिंग आदि और सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के सुदृढ़ीकरण और उसके बगैर विकास कार्यनीति प्रेरित के निहितार्थों की भी जांच करने के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य एक "प्रमुख संकेतक" आधारित पूर्वानुमान मॉडल के साथ नीतिगत अनुकरण मॉडल को पूरक बनाना भी है जिससे बाह्य अथवा नीतिगत दबावों के बगैर "सामान्य स्थिति में व्यवसाय में संवृद्धि, मुद्रास्फीति, सीएडी आदि वार्षिक अथवा द्विवार्षिक पूर्वानुमान प्राप्त होंगे।

राज्य विकास अध्ययन

संपूरित अध्ययन

द रिव्यु आफ कम्प्लाएंस आफ द गवर्नमेंट आफ ओडिशा टू द एफआरबीएम एक्ट–2012–13, तपस सेन, प्रताप रंजन जेना

The Review of Compliance to Odisha FRBM Act – 2012-13

Pratap Ranjan Jena
Tapas Kumar Sen

National Institute of Public Finance and policy
New Delhi

ओडिशा के एफआरबीएम अधिनियम में ओडिशा सरकार के घाटा स्तरों और ऋण के संबंध में मूल प्रावधानों के अलावा अनेक सिफारिशी प्रावधान दिए गए हैं। यह समीक्षा, विधान मंडल और सामान्य जनता को प्रावधानों के अनुपालन की सीमा की जानकारी प्रदान करते हुए सांविधिक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में आयोजित की गई थी। इस समीक्षा में राज्य वित्त के संबंध में ओडिशा सरकार के विचारार्थ कुछ सामान्य सुझाव भी दिए गए हैं।

चल रहे अध्ययन

एमडीजी रिपोर्ट फार मध्य प्रदेश, एन.आर. भानुमूर्ति, एच.के. अमरनाथ, सुकन्या बोस, परमादेवी अधिकारी, अरकाज्योति जाना।

इस अध्ययन का उद्देश्य, राज्य और जिला स्तर पर एमडीजी संकेतकों की तुलना में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की एक समेकित समीक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत, मार्जिनकृत और बहिष्कृत समूहों की वंचनाओं और भेद्यताओं को समझने के लिए साम्यता नजरों का इस्तेमाल करके मध्य प्रदेश के विकासात्मक परिणामों को (एमडीजी फ्रेमवर्क के विरूद्ध) बेहतर ढंग से समझने के लिए एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा भी दी गई है।

मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी आफ गोआ फार 2015–16, प्रताप रंजन जेना और सतादु सिकदर।

रिपोर्ट में वर्ष 2015–16 के लिए गोआ सरकार के लिए मध्यावधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) प्रस्तुत की गई है। इमसें राजकोषीय नीति उद्देश्य, राजस्व संवर्धन उपाय, व्यय पुनर्गठन आने वाले बजट वर्ष में तथा दो विगत वर्षों में प्रस्तावित राजकोषीय लक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। रिपोर्टों, विद्यमान मेक्रो–राजकोषीय परिवेश के आधार

पर तथा राजकोषीय लक्ष्यों से संबंधित राज्य एफआरबीएम अधिनियम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी।

द रीव्यु आफ कम्प्लाएन्स आफ गवर्नमेंट आफ सिक्किम टू द एफआरबीएम एक्ट–2012–13, प्रताप रंजन जेना, सतादफ्र सिकदर।

रिपोर्ट में, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अधिनियम में संशोधनों के अनुसार वर्ष 2012–13 के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों पर अमल करते समय राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन किया जाएगा। समीक्षा रिपोर्ट में राज्य वित्त का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा जैसा कि वर्ष 2012–13 के लिए बजट में प्रस्तावित है तथा बजट आउटटर्न्स जैसा कि एफआरबीएम अधिनियम के राजकोषीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष के संबंध में वित्त लेखों में रिपोर्ट की गई है।

मीडियम–टर्म फिस्कल प्लान अण्डर एफआरबीएम एक्ट आफ सिक्किम–2015–16, प्रताप रंजन जेना

रिपोर्ट में वर्ष 2015–16 के लिए सिक्किम सरकार के लिए मध्यावधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) प्रस्तुत की जाएगी। एमटीएफपी 2015–16 में राजकोषीय नीति उद्देश्य और आगामी बजट वर्ष में और दो विगत वर्षों के संबंध में प्रस्तावित राजकोषीय लक्ष्य सम्मिलित किए जाएंगे। रिपोर्ट, सिक्किम में नव अधिनियमित एफआरबीएम अधिनियम की आवश्यकताओं को ध्यान मे ।रखते हुए, विद्यमान मेक्रो–राजकोषीय परिवेश के आधार पर तैयार की जाएगी। रिपोर्ट में तीन वर्षों के संबंध में, एफआरबीएम अधिनियम के निर्धारण के अनुसार बजट वर्ष का तालमेल करने सहित, राजकोषीय परिवर्तनशीलों का प्रस्ताव किया जाएगा।

व्हाट इज दि क्वालिटी आफ गवर्नेन्स अक्रास इण्डियन स्टेट्स एण्ड डज इट मैटर ?, रथिन रॉय, स्टानली एल. विनेर, जे. स्टीफन फेरिस, पिनाकी चक्रवती, भारती भूषण दाश

इस परियोजना के अंतर्गत, भारतीय राज्य चुनावों और राज्य सरकारों द्वारा की गई राजकोषीय चयन प्रणाली की प्रतिस्पर्धात्मकता के बीच संबंध की जांच की जाएगी। ऐसा करने के लिए इस परियोजना में प्रस्ताव है कि : (i) बड़े भारतीय राज्यों के संबंध में निर्वाचन क्षेत्र–स्तर निर्वाचन डेटा का पूरा रिकार्ड रखना, (ii) अनेक सूचकों का इस्तेमाल करके राज्य चुनावों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मापना, और (iii) राज्य राजकोषीय नीति विकल्पों के एक गतिशील अनुभाविक मॉडल के भाग के रूप में अन्य राजनीतिक और आर्थिक कारकों के साथ प्रतिस्पर्धात्मकता उपायों का इस्तेमाल करना। इस कार्य से भारत में शासन और सार्वजनिक नीति के बीच संबंध का अध्ययन करने में योगदान प्राप्त होगा।

स्टडी आन बिहार स्टेट फाइनेंसिज–पॉलिसी आप्शन्स फार टेक्स राशनलाइजेशन एण्ड मोबिलाइजेशन आफ रेवेन्यु, तपस सेन, आर कविता राव, सच्चिदानन्द मुखर्जी

इस अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित का विस्तृत विश्लेषण सम्मिलित होगा : (क) राज्य की कराधान क्षमता और प्रयास, (ख) सार्वजनिक व्यय मुद्दों कार्यकुशलता, प्राथमिकताकरण और क्षेत्रकीय आबंटन, (ग) केंद्र–राज्य मुद्दें, (घ) राजकोषीय असंतुलन और समायोजन, (ड.) राजकोषीय देयताएं और संधारणीयता।

हेव न्युली–क्रिएटिड इण्डियन स्टेट्स प्रोमोटिड इन्क्लुसिव डेवलपमेंट ? ए कम्पेरीजन

आफ झारखण्ड एण्ड छत्तीसगढ़, रथिन रॉय, मीता चौधरी

इस अध्ययन के अंतर्गत, निम्नलिखित व्यापक प्रश्न पर विचार किया जाएगा : क्या राज्य के सृजन से एक विशिष्ट राजकोषीय एजेंसी तैयार हुई है, विशेष रूप से जैसा कि कराधान की प्रणाली और सार्वजनिक खर्च पद्धति के परिवर्तन के माध्यम से यथा अभिव्यक्त ?

फिस्कल रिसर्च आन माइनिंग इन न्युली–क्रिएटिड स्टेट्स आफ झारखण्ड एण्ड छत्तीसगढ़ आफ इण्डिया, रथिन रॉय, लेखा चक्रवर्ती

इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में दो नव गठित राज्य, यथा झारखण्ड और छत्तीसगढ़ में, राज्य व्यवसाय संबंधों की विश्लेषणात्मक रूपरेखा के अंदर, खनन क्षेत्र से राजकोषीय राजस्व का विश्लेषण करनाहै ।

गवर्नेन्स एज़ सर्विस डेलिवरी : परफोर्मेन्स आफ इण्डियन स्टेट्स, सुदीप्तो मंडल, सताद्रु सिकदर, समित चक्रवर्ती

स्पष्टतः परिभाषित और पारदर्शी संकेतकों के आधार पर शासन निष्पादन की उद्देश्यपरक रेटिंग, राज्यों के बीच शासन प्रतिस्पर्धा की उभरती प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए एक उपयोगी साधन होगा । मंडल और एसोसिएट्स ने सेवा प्रदाय के रूप में शासन के बहु–संकेतकों के आधार पर एक शासन निष्पादन सूचक तैयार किया है जिसका उपयोग 2000–2010 अवधि के दौरान राज्य सरकारों के निष्पादन का आकलन करने के लिए किया गया है । इसे "कार्य प्रगति पर" के रूप में देखा जाना चाहिए । वर्तमान परिणामों से निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं जिनकी चल रहे अध्ययन में खोज की जा रही हैं :

i क्या हम उत्तम शासन की संकल्पना में और सुधार कर सकते हैं अथवा परिणामों के अलावा प्रोसेस संकेतकों को शामिल कर सकते हैं ?

ii डेटा बेस में कौन–सी मुख्य कमियां हैं जिन्हें ऐसे शासन रेटिंग प्रक्रिया के लिए सुदृढ़ करने की जरूरत है ?

iii अलग–अलग राज्यों में प्रमुख शासन क्षेत्र कौन–से हैं जिन पर सुदृढ़ीकरण हेतु प्राथमिकता के साथ बल दिया जाना चाहिए ?

iv सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात क्या हम उन कारकों का पता लगा सकते हैं जो राज्य सरकार के उत्तम और बुरे निष्पादन का निर्धारण कर सकते हैं ?

अन्य अध्ययन

संपूरित अध्ययन

इंटर–गवर्नमेंटल फाइनेंस इन फाइव इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिज ? तपस सेन, एच.के. अमरनाथ, मनीश गुप्ता, सुधांशु कुमार, भारती भूषण दाश

अध्ययन के अंतर्गत, राजस्व और व्यय आबंटन की पद्ध

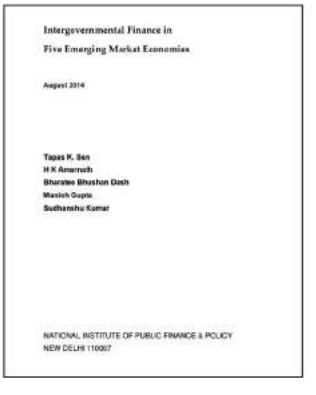
Intergovernmental Finance in
Five Emerging Market Economies

August 2014

Tapas K. Sen
H K Amarnath
Bhuvan Bhushan Dash
Manish Gupta
Sudhanshu Kumar

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE & POLICY
NEW DELHI 110067

ति की समीक्षा की गई है, प्राकृतिक स्रोतों के आबंटन सहित, नीतियां तथा दोहरे आबंटनों के कारण उत्पन्न विवादों का समाधान करने के लिए परंपराएं ; अन्तर–सरकारी अंतरण पद्धति ; वित्त पोषण अवस्थापना आवश्यकताओं की पद्धतियां, उप–राष्ट्रीय स्तरों पर उधार की पद्धति सहित तथा पांच उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, रूस

और दक्षिण अफ्रीका में अन्तर–सरकारी राजकोषीय संबंधों के साथ डील करने वाली पद्धतियां।

अण्डरस्टेंडिंग हाई अनस्पेंन्ट बेलेसिंज एण्ड फंड फ्लो मेकेनिज्म इन मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एन. आर. भानुमूर्ति, एच.के. अमरनाथ, अखिलेश वर्मा, आदर्श गुप्ता

इस परियोजना के अंतर्गत टीम ने एमजीआरईजीएस

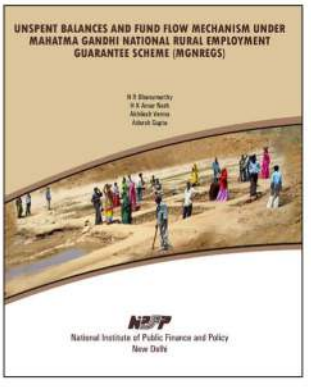

के संबंध में पहला भाग पूरा कर लिया है तथा एनआईपीएफपी द्वारा "अनस्पेंट बेलेसिंज एण्ड फण्ड फ्लो मेकेनिज्म अण्डर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस)" नामक एक पुस्तक के रूप में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। इस परियोजना के अंतर्गत, पीएमजीएसवाई, आईएवाई, एनआरएलएम और एनएसएपी कार्यक्रम प्रगति के अधीन है।

चल रहे अध्ययन

अवार्ड आफ दि असाइनमेंट परटेनिंग टू असेस्मेंट आफ दि रिस्कीनैस आफ दि एयरपोर्ट सेक्टर एण्ड एस्टिमेटिंग फेयर रेट आफ रिटर्न आन इक्विटी (आरओई), अजय शाह, सुयश राय, अपूर्व गुप्ता

परियोजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी हवाई अड्डों के संबंध में (4 प्रमुख प्राइवेट हवाई अड्डे–दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि., नई दिल्ली ; मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि., मुंबई ; बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि., बेंगलुरू ; जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि., हैदराबाद), परियोजनाओं/हवाई अड्डों के जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए, इक्विटी मूल्यांकन सम्मिलित हैं ; बेटा मूल्यों के लिए बैंचमार्क के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे विदेशी हवाई अड्डों के लिए बेटा मूल्यों का पुनः परिकलन, पूंजी की भारित औसत लागत के बुक मूल्य के उपयोग के संबंध में दृष्टिकोण की समीक्षा, "डायल" के प्रस्ताव की फलस्वरूप प्राप्त पणधारी टिप्पणियों का मूल्यांकन तथा रिटर्न इशू की उचित दर पर पणधारी टिप्पणियों के निपटान में प्राधिकरण की सहायता करना।

स्ट्रेंथनिंग रीसर्च एण्ड केपेसिटी डेवलपमेंट इन दि डिपार्टमेंट, रथिन रॉय

परियोजना के अंतर्गत उन मुद्दों का अध्ययन किया जाएगा जो जी–20, "ब्रिक्स" व अन्य ऐसे ही बहुपक्षीय मंचों पर उभरते हैं तथा मुद्दों के विभिन्न आयामों को समझने के लिए भारत सरकार की मदद करने के लिए एक चिंतन कोश स्थापित और इन मुद्दों पर एक नीतिगत परिप्रेक्ष्य तैयार किया जाएगा।

ट्रेनिंग एण्ड असिस्टेंट्स प्रोग्राम फार दि कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल (सीएजी) आफ इण्डिया आन पब्लिक डेट मेनेजमेंट एण्ड एफआरबीएम एक्ट एण्ड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, रथिन रॉय, प्रताप रंजन जेना, मनीष गुप्ता, श्रुति त्रिपाठी

कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक ऋण प्रबंधन में ज्ञान और क्षमता निर्माण में सुधार करना (पीडीएम)। राजकोषीय जिम्मेदारी तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम) और उसका कार्यान्वयन।

मेक्रोइकोनामिक पॉलिसी फार माइनिंग सेक्टर इन इण्डिया, लेखा चक्रवर्ती

इस अध्ययन के अंतर्गत, भारत में खनन क्षेत्र से सम्बद्ध मेक्रोआर्थिक नीतियों और फर्म स्तर प्रतिस्पर्धात्मकता पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया है। यह एक पृथक अनुसंधान परियोजना है।

25–कन्ट्री स्टडी आन 'जेण्डर बजटिंग' इन एशिया पेसिफिक, आईएमएफ वाशिंगटन डी.सी. प्रोजेक्ट, लेखा चक्रवर्ती

इस अध्ययन के अंतर्गत, एशिया और प्रशांत में 25 देशों के 'जेण्डर बजटिंग' पद्धति अनुभवों का विश्लेषण किया गया है तथा आर्थिक विकास के प्रति महत्वपूर्ण संयोजन कायम किया गया है। यह परियोजना लिंग बजट पद्धति पर आईएमएफ विश्व परियोजना का एक भाग है।

शुरू की गई नई परियोजनाएं

- बायोडाईवर्सिटी फाइनेंस इनीशिएटिव इन इंडिया : क्वान्टीफाइंग दि बायोडाईवर्सिटी फाइनेंस गेप एण्ड डेवलपिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजीज
- एनआईपीएफपी–ईएमसी पॉलिसी रीसर्च प्रोग्राम
- अपडेटिंग दि क्लासिफिकेशन आफ पब्लिक एक्सपेंडीचर फार इण्डियाज नेशनल हैल्थ एकाउंन्ट्स एज पर एसएचए 2011–एचएनएसआरसी–एनआईपीएफपी

3. कार्यशालाएं, सेमिनार, घटनाएं, बैठकें, सम्मेलन

- शांघाई अंतराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान, चीन से प्रोफेसर लियु झोंगयी (ऊपर) के साथ ''मोदी युग में चीन–भारत संबंध और आर्थिक सहयोग'' पर एक अन्योन्यक्रिया चर्चा, 16 जून, 2014, राजनयिक मिशनों से अनेक महानुभावों ने समारोह में भाग लिया ।

- ''भारत का मेक्रो–आर्थिक फ्रेमवर्क और ऋण संधारण ीयता विश्लेषण'' पर कार्यशाला, एनआईपीएफपी में **''एनआईपीएफपी–डीईए अनुसंधान कार्यक्रम''**, 15–16 जुलाई 2014 ।

- **यूनियन बजट सेमिनार, 2014–15,** एनआईपीएफपी, सीपीआर, आईसीआरआईईआर, आईडीएफ और एनसीएईआर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, लीला पैलेस, डिप्लोमेटिक एंकलेव, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में, 19 जुलाई, 2014 ।

- **''इण्डिया–आस्ट्रेलिया राउंडटेबल कांफ्रेंस–जी–20''**, एनआईपीएफपी, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन (इण्डिया), ईस्ट एशिया ब्यूरो आफ इकोनोमिक रीसर्च (आस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी), ताज विवान्ता, सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली, 10 सितंबर 2014 ।

- **''कर नीति और दक्षिण एशिया में उद्यम विकास''** पर एक दिन की नीति चर्चा कार्यशाला, एनआईपीएफपी, जीआईआई, आईआईडीएस, बीएनयू, आईपीएस, आईडीआरसी द्वारा एनआईपीएफपी में संयुक्त रूप से आयोजित, 15 अक्तूबर 2014 ।

- **''जेण्डर रेस्पोन्सिव बजटिंग''** पर आधे दिन की बैठक, डब्ल्यु पीसी, नई दिल्ली और अफगानिस्तान आधारित इक्विलिटी आफ पीस एण्ड डेवलपमेंट (ईपीडी) के समन्वय से वित्त मंत्रालय तथा चुनिंदा क्षेत्रकीय मंत्रालय, अफगानिस्तान सरकार के साथ सहयोग से एनआईपीएफपी में आयोजित, 28 अक्तूबर, 2014 ।

- पार्वती बाई चौवगुले कला और विज्ञान कालेज, गोवा के छात्रों के लिए ''बजट के मूलभूत'' पर आधे दिन की कार्यशाला, एनआईपीएफपी में, 18 नवंबर, 2014 ।

- **''थर्ड ओईसीडी इकोनामिक सर्वे आफ इंडिया''** की शुरूआत, ओईसीडी, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और एनआईपीएफपी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, 19 नवंबर, 2014 ।

ऊपर: दाएं से : पीटर ड्रिस्डाले, पूर्व प्रोफेसर, अर्थशास्त्र और प्रधान पूर्व एशियाई आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो और प्रधान, पूर्व एशियाई आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो और पूर्व एशियाई फोरम, क्राफोर्ड स्कूल आफ पब्लिक पॉलिसी, ए.एन.यू. ; प्रोफेसर राम प्रसाद सेन गुप्ता, ज.ने.वि, डॉ. रथिन रॉय, निदेशक, एनआईपीएफपी ।

बाएं: डेविडविनेस, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ।

- एक दिन की कार्यशाला, **''ओईसीडी–इण्डिया पॉलिसी डायलॉग''** आन न्यू अप्रोचिज टू इकोनामिक चेलेंजिज (एनएईसी), ओईसीडी और एनआईपीएफपी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, एनआईपीएफपी में, 24 फरवरी, 2015 ।

- **यूनियन बजट–2015–16: रिफोर्म एण्ड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्ज,** पांच संस्थानों यथा एनआईपीएफपी, सीपीआर, आईसीआरआईईआर, आईडीएफ और एनसीएईआर द्वारा संयुक्त रूप से ''दीवान–ए–आम'', ताज महल होटल, मानसिंह रोड, नई दिल्ली में आयोजित, 9 मार्च, 2015 ।

- ''नेक्स्ट जेनेरेशन फिस्कल रिफोर्म फ्रेमवर्क्स टू डेलिवर इफेक्टिव काउंटर–साइक्लिकल पॉलिसी : इंडियन एण्ड इंटरनेशनल एक्सपीरिएन्स'' पर दो

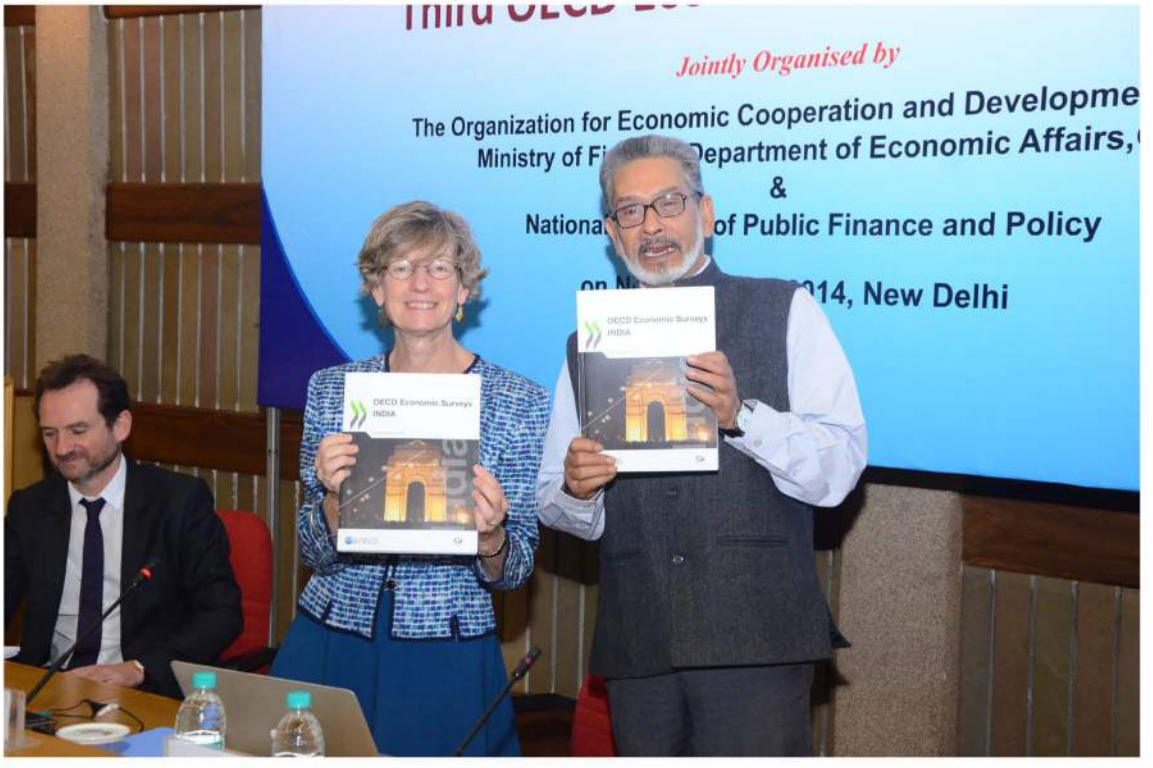

ऊपर: केथरीन एल. मन्न, ओईसीडी मुख्य अर्थशास्त्री और प्रधान, अर्थशास्त्र विभाग, प्रोनबसेन, कन्ट्री डायरेक्टर, इंटरनेशनल ग्रोथ सेन्टर्स इण्डिया सेन्ट्रल प्रोग्राम

बाएं: एनआईपीएफपी ऑडिटोरियम में एक दिन की कार्यशाला।

दाएं : डॉ. सी. रंगराजन

नीचे : बाएं से : डॉ. विजय केलकर, अध्यक्ष, एनआईपीएफपी, डॉ. रथिन रॉय, निदेशक, एनआईपीएफपी और डॉ. सी. रंगराजन, पूर्व अध्यक्ष, एनआईपीएफपी ।

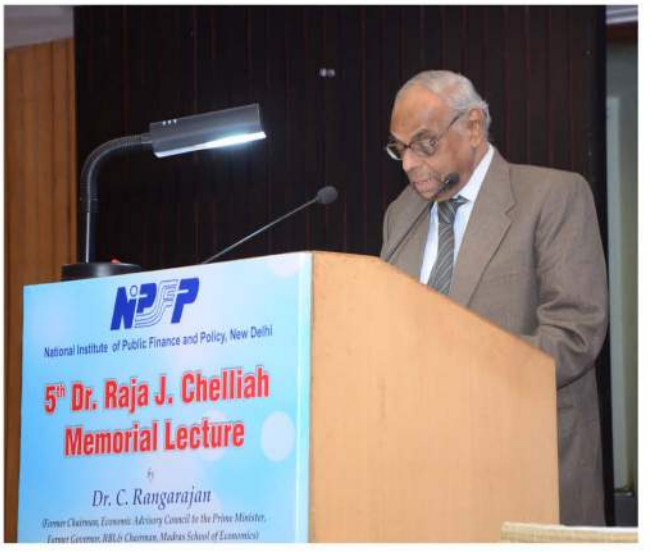

दिन का **''एनआईपीएफपी–डीईएएफआरबीएम कान्फरेंस''**, होटल सिडाडे डे गोआ, गोआ, एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित, 12–13 दिसंबर, 2014 ।

- दो दिन का सम्मेलन, **पेपर्स इन पब्लिक इकोनामिक्स एण्ड पॉलिसी (पीपीईपी),** एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में, 12–13 मार्च, 2015 ।
- **पांचवां डा. राजा जे. चेलैय्या मेमोरियल लेक्चर,** ''इश्यूज इन इण्डियाज एक्सटर्नल सेक्टर'', डा. सी. रंगाराजन, पूर्व अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद तथा पूर्व गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, आईआईसी, नई दिल्ली में, 13 मार्च, 2015 ।

(आंतरिक सेमिनार श्रृंखला के लिए देखें संलग्नक–III)

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यक्रम समन्वयकर्ता	अवधि	पाठ्यक्रम प्रतिभागी
सार्वजनिक वित्त	सी. भुजंग राव	12 से 16 मई 2014	भारतीय आर्थिक सेवा परिवीक्षार्थी
राजकोषीय और मौद्रिक नीति	सुधांशु कुमार	16 से 20 जून 2014	भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारी प्रशिक्षार्थी
राजकोषीय नीति और मेक्रोआर्थिक प्रबंधन	लेखा चक्रवर्ती	16 से 20 जून 2014	अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारी)
एफआरबीएम अधिनियम	प्रताप रंजन जैना	10 से 12 सितंबर, 2014	भारतीय नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारी (सीएजी)
सार्वजनिक ऋण प्रबंधन	मनीष गुप्ता	29 से 30 सितंबर 2014	भारतीय नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारी (सीएजी)
सार्वजनिक वित्त	श्रुति त्रिपाठी	2 से 13 फरवरी, 2015	भारतीय लेखा–परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी–प्रशिक्षार्थी
सार्वजनिक वित्त	सुकन्या बोस	23 से 27 मार्च 2015	भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी–प्रशिक्षार्थी

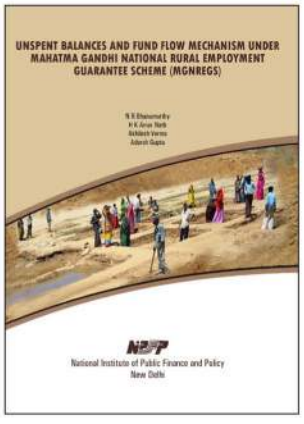

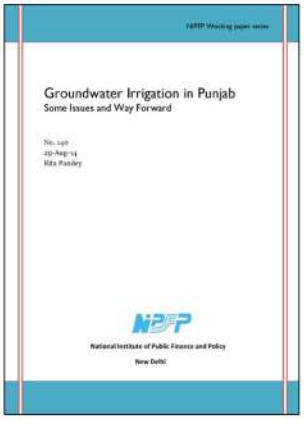

5. एनआईपीएफपी प्रकाशन (2014–15)

आलोच्य वर्ष के दौरान, एनआईपीएफपी प्रकाशन यूनिट ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के लिए एन.आर. भानुमूर्ति, एच.के. अमरनाथ, अखिलेश वर्मा और आदर्श गुप्ता द्वारा एक अध्ययन के आधार पर ''अंडरस्टेंडिंग हाई अनस्पेंट बेलेसिंज एण्ड फंड फ्लो मेकेनिज्म इन मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स'' (एमजीएनआरईजीएस) का प्रकाशन किया।

संस्थान का छमाही सूचना पत्र जुलाई 2014 और जनवरी 2015 में प्रकाशित किया गया जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत चल रही परियोजनाएं, संकाय कार्यकलाप और घटनाएं सम्मिलित की गई।

एनआईपीएफपी के अनुसंधान संकाय और उनके एसोसिएट द्वारा लिखित 11 कार्य पत्र, एनआईपीएफपी कार्य पत्र श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित किए गए।

''वन पेजर'' का प्रथम खण्ड, एनआईपीएफपी द्वारा शुरू की गई प्रकाशन की एक नई श्रृंखला नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों की सुविधा हेतु, महत्वपूर्ण अनुसंधाना कार्य सही–सही प्रस्तुत करने के लिए, मई 2014 में प्रकाशित किया गया।

(समूल्य प्रकाशनों की सूची संलग्नक–V में देखें)

6. पुस्तकालय और सूचना केंद्र

संस्थान का पुस्तकालय और सूचना केंद्र, सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक नीति के विषय क्षेत्रों के विषय में व्यापक क्षेत्र के मुद्रित और डिजिटल स्रोतों के साथ, दक्षिण एशिया में एक सर्वोत्तम केंद्र है। इमसें 62271 से अधिक प्रकाशन हैं जो राजकोषीय संघवाद, सार्वजनिक अर्थशास्त्र, कराधान और सार्वजनिक व्यय, लैंगिक अध्ययनों व अन्य सम्बद्ध अध्ययन क्षेत्रों–विषयों पर आधारित हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान, पुस्तकालय में 673 नए दस्तावेज और 125 कार्य पत्र शामिल किए गए। इसमें 29 प्रकाशन आईएमएफ जमाकर्त्ता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त हुए। इसमें 125 सीडी–आरओएम भी प्राप्त हुए जिनमें भारत की जनगणना, डेटा स्रोत आदि सम्मिलित हैं।

पुस्तकालय के सदस्य, 543 पत्र–पत्रिकाओं के चंदे का लाभ उठाते हैं (आनलाइन जरनल और डेटाबेस सहित) और उन्होंने 14 समाचार–पत्रों का लाभ उठाया। एक समर्पित समिति पुस्तकालय के संग्रह विकास और प्रबंधन कार्यकलाप आयोजित करती है।

पुस्तकालय के आपरेशन और सेवाएं, एक वेब–आधारित पुस्तकालय प्रबंधन साफ्टवेयर "लिबसिस– 7.0" का इस्तेमाल करते हुए, कम्प्यूटरीकृत की गई हैं। सूची पत्र स्टैण्डर्ड को भी एमएआरसी 21 डिजिटल फार्मेट में उन्नत किया गया है। डब्ल्यू ईबी ओपेक (आनलाइन पब्लिक एक्सेस केटेलॉग) वेब समर्थित सेवा के अंतर्गत "बूलिअन आपरेटर्स" का इस्तेमाल करके ब्राउजर–आधारित फ्री टेक्स्ट–खोज की जा सकती है।

पुस्तकालय, बृहस्पतिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस पर, सुबह 9 बजे से 5.30 बजे सायं तक खुला रहता है, जिस दिन यह सायं 8 बजे तक खुला रहता है। शनिवार वाले दिन इसका खुलने का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 4.00 बजे तक है।

पुस्तकालय में प्राप्त सभी नए दस्तावेजों को नियमित रूप से डेटाबेस में शामिल किया जाता है और निम्नलिखित बुलेटिनों के रूप में उन्हें जारी किया जाता है :

1. न्यू अराइवल्स आफ बुक्स एण्ड रिपोर्ट्स (पुस्तकों की नवीनतम अभिवृद्धियां)
2. आर्टिकिल अलर्ट सेवा (समाचार–पत्र कतरनों की नवीनतम अभिवृद्धियां)
3. करेंट कंटेन्ट्स सर्विस (पुस्तकालय में प्राप्त पत्र–पत्रिकाओं के विषय–वस्तु पृष्ठों के संबंध में एक मासिक बुलेटिन)।
4. बजट–पूर्व और पश्चात् विशेष बुलेटिन

उपरोक्त के अतिरिक्त पुस्तकालय में निम्नलिखित ई–स्रोत भी मंगाए जाते हैं :

ई–स्रोत

ई–पुस्तक डेटाबेस

	डेटाबेस का नाम	संग्रह	वेब–लिंक	अधिग्रहण की विधि
1.	अर्थशास्त्र और इकोनामीट्रिक्स पर स्प्रिंगेर ई–बुक्स विषय बंडल	2570	http:link.springer.com	आईपी आधारित

ई–जरनल डेटाबेस

	डेटाबेस का नाम	संग्रह	वेब–लिंक	अधिग्रहण की विधि
1.	ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस जरनल्स : अर्थशास्त्र विषय बंडल	47	http:oxfordjournals.org	आईपी आधारित
2.	जे–स्टोर	162	http:www.jstor.org	आईपी आधारित
3.	अलजेवियर : साइंस डायरेक्ट : अर्थशास्त्र, इकोनोमीट्रिक्स और वित्त विषय बंडल	131	http:www.sciencedirect .com	आईपी आधारित

ई–डेटाबेस

	डेटाबेस का नाम	वेब–लिंक	अधिग्रहण की विधि
1.	ओईसीडी वित्त और निवेश : पुस्तकालय	http:www.oecd-ilibrary.org	आईपी आधारित
2.	ओईसीडी कराधान पुस्तकालय	http:www.oecd-ilibrary.org	आईपी आधारित
3.	आईबीएफडी संग्रह स्थल	http:www.ibfd.org	आईपी आधारित
4.	आईबीएफडी इलेक्ट्रॉनिक आनलाइन	http:www.ibfd.org	चुनिंदा उपभोक्ताओं के लिए
5.	आईएमएफ ई–लाईब्रेरी	http:www.ilibrary.imf.org	आईपी आधारित
6.	इम्फोर्म्ड लायब्रेरियन	http:www.informedlibrarian.com	उपभोक्ता आईडी/ पासवर्ड आधारित एक्सेस

7.	स्टाटा जरनल	http:www.stata-journal.com	पीडीएफ उपलब्ध
8.	ईपीडब्ल्युआरएफ इण्डिया टाइम सीरीज	http:epwrfits.in	उपभोक्ता आईडी/ पासवर्ड आधारित एक्सेस
9.	मनुपत्र	http:www.manupatra.com	उपभोक्ता आईडी/ पासवर्ड आधारित एक्सेस
10.	सीईपीआर	http:www.cepr.org	चुनिंदा उपभोक्ताओं के लिए

कारपोरेट डेटाबेस

	डेटाबेस का नाम	वेब–लिंक	अधिग्रहण की विधि
1.	इकोनोमिक आउटलुक	http:economicoutlook.cmie.com	उपभोक्ता आईडी/ पासवर्ड आधारित एक्सेस
2.	प्रोवेस	http:prowess.cmie.com	उपभोक्ता आईडी/ पासवर्ड आधारित एक्सेस
3.	कापेक्स	http:capex.cmie.com	आईपी आधारित
4.	इकोनलिट डेटाबेस	http:web.ebscohost.com	आईपी आधारित

अन्तर पुस्तकालय ऋण और प्रलेख प्रदाय सेवाओं के माध्यम से स्रोत बांटने के संबंध में पुस्तकालय, डेवलपिंग लायब्रेरी नेटवर्क (डेलनेट), राष्ट्रीय समाज विज्ञान प्रलेखन केंद्र (नैसडॉक), केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (सीएसएल) और अमेरिकन केंद्र पुस्तकालय (एसीएल) द्वारा प्रदत्त सदस्यता का पुस्तकालय द्वारा लाभ उठाया जाता है। आलोच्य वर्ष के दौरान, पुस्तकालय ने अन्य पुस्तकालयों से 28 दस्तावेज उधार लिए और 54 दस्तावेज उधार दिए। वर्ष 2014–15 के दौरान लगभग 4772 बाह्य अनुसंधान विद्वानों और नीति निर्माताओं ने पुस्तकालय का दौरा किया।

एनआईपीएफपी कार्य पत्रों का मेटाडेटा अंतर्राष्ट्रीय विषय जमा स्थल "आरईपीईसी" (अर्थशास्त्र पर अनुसंधान पत्र) पर अपलोड किए जाते हैं।

प्रतिलेखन सेवा

पुस्तकालय, संकाय सदस्यों और आगंतुक अनुसंधान छात्रों को स्रोत सामग्री की पारंपरिक प्रतिलेखन सेवाएं प्रदान करता है। कुल मिलाकर 43714 पृष्ठों की फोटोकापी सामग्री उपभोक्ताओं को वर्ष के दौरान उनके अनुसंधान कार्य के लिए उपलब्ध कराई गई।

स्टाफ कार्यकलाप

मोहम्मद आसिफ खान, वरिष्ठ पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), नई दिल्ली में 27–29 नवंबर 2014 को "लायब्रेरीज, आर्काइव्ज एण्ड म्युजियम्स : इन्नोवेटिव आइडियाज, टेक्नोलॉजीज एण्ड सर्विसिज" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "आईसीएलएएम 2014" में "यूज आफ क्लाउड कम्प्यूटिंग टेक्नोलॉजी : एज एन एप्लीकेशन इन लायब्रेरीजः पर एक भाषण दिया। उन्होंने, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली में 23–24 जनवरी 2015 को "ट्रांसफोर्मिंग डायमेंशन आफ आईपीआर : चैलेन्जिज फार न्यू एज लायब्रेरीज" पर सम्मेलन में (पृ. 134–138) "इश्यूज आफ कापीराइट प्रोटेक्शन इन दि डिजिटल एरा" पर एक वार्ता दी। उन्हें "ट्रांसफोर्मिंग पब्लिक लायब्रेरीज इन इण्डिया : एन विजनिंग दि फ्युचर" पर "इण्डिया पब्लिक लायब्रेरीज कन्फरेंस (आईपीएलसी 2015)" में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसका आयोजन 17–18 मार्च 2015 को भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में "डेवलपिंग लायब्रेरी नेटवर्क (डेलनेट)" के सहयोग से "डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन (डीईएल), नई दिल्ली द्वारा किया गया था।

पी.सी. उपाध्याय, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी ने "नेशनल कन्फरेंस आन एमर्जिंग ट्रेण्ड्स एण्ड टेक्नीक्स फार इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट इन लायब्रेरीज : इश्यूज एण्ड चेलेन्जिज" में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राउरकेला में 13–14 फरवरी, 2015 को भाग लिया।

7. कम्प्यूटर/आईटी यूनिट

वर्ष 2014–15 के दौरान, एचपी प्रोबुक 440 जीआई श्रृंखला–12 संख्या ; डीईएलएल लेटीट्यूड ई 6540 लेपटाप–1 संख्या ; एचपी–8300 इनटेल कोर 5 डेस्कटाप के 20 यूनिट, डीईएलएल आप्टीप्लेक्स 3020 एमटी–8 संख्या ; थिंक स्टेशन लेनोवो पी–300 एसएसई कन्नावाराव–15 संख्या ; प्रिंटर एचपी एल 1 1606–7 संख्या, यूपीएसएपीसी मेक 800–वीए–20 संख्या खरीदी गई। कुल मिलाकर संस्थान में 6 सर्वर, 157 पेंटियम–IV कम्प्यूटर, 28 लेपटाप, 138 यूपीएस और 56 प्रिंटर्स हैं।

संस्थान की इंटरनेट सुविधा, नेशनल नोलिज नेटवर्क (एनकेएन), टाटा और एमटीएनएल लीज्ड लाइन द्वारा समर्थित है। आलोच्य वर्ष के दौरान, यूनिट स्टाफ ने सामग्री को संस्थान की अधिकारिक वेबसाइट http:www.nipfp.org.in पर अपलोड किया। वेबसाइट पर संस्थान के उद्देश्यों और प्रमुख कार्यकलापों पर प्रकाश डाला जाता है, एनआईपीएफपी संकाय के अनुसंधान हितों का उनके विस्तृत सीबी के साथ, उल्लेख किया जाता है तथा इन–हाउस प्रकाशनों की डाउनलोड करने योग्य फाइलों की व्यवस्था है।

यूनिट द्वारा पुस्तकालय और लेखा विभाग के लिए विशेषज्ञ साफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है। संस्थान के पुस्तकालय के लिए तकनीकी सहायता "लिबसिस" और "प्रोवेस" के माध्यम से प्रदान की जाती है, लेखा विभाग के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए ई–एक्स एकाउंन्ट्स और पेरोल साफ्टवेयर की व्यवस्था की गई है।

8. मुख्य–मुख्य संकाय कार्यकलाप

डॉ. विजय केल्कर, अध्यक्ष, एनआईपीएफपी, ''पद्म विभूषण'', पूर्व अध्यक्ष, तेरहवां वित्त आयोग, पूर्व पेट्रोलियम सचिव, भारत, पूर्व वित्त सचिव, भारत और पूर्व कार्यकारी भारतीय निदेशक, आईएमएफ ने 1 नवंबर, 2014 को कार्यभार संभाला।

वर्ष 2014–15 में डा. केल्कर को, 2030 तक आयात निर्भरता में संघारणीय कटौति के साथ घरेलू तेल और गैस उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक मार्ग नक्शा तैयार करने के लिए, भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया ।

डॉ. केलकर भारत सरकार द्वारा अवस्थापना विकास के पीपीपी मॉडल पर पुनर्विचार और पुनर्गठित करने के संबंध में गठित एक समिति के भी अध्यक्ष हैं।

डॉ. रथिन रॉय, ने आलोच्य वर्ष के दौरान, प्रशासनिक और अकादमिक दोनों मोर्चों पर कुछेक नई पहलें शुरू की। उन्होंने, एनआईपीएफपी–नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रम शुरू किया जिसका प्रायोजन और वित्त पोषण नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा किया गया था – प्रताप रंजन जेना, मनीश गुप्ता और श्रुति त्रिपाठी के साथ। उन्होंने, ''एनआईपीएफपी–ईएमसी पॉलिसी रीसर्च प्रोग्राम'' भी शुरू किया जिसका नेतृत्व एन.आर. भानुमूर्ति ने किया था तथा सुयश राय ने सहायता प्रदान की। एनएचएसआरसी–एनआईपीएफपी सहयोजित परियोजना'' अपडेटिंग दि क्लासिफिकेशन आफ पब्लिक एक्सपेंडीचर फार इण्डियाज नेशनल एकाउंट्स एज पर एसएचए 2011'की भी पहल डा. राय ने मीता चौधरी और एच.के. अमरनाथ के साथ की।

डॉ. रॉय ने अपना समय एक चल रहीं परियोजना ''व्हाट इज दि क्वालिटी आफ गवर्नेन्स अक्रास इण्डियन स्टेट्स एण्ड डज इट मैटर ?'' पर लगाया जिसका प्रायोजन समाज विज्ञान और मानविकी अनुसंधान परिषद (एसएसएचआरसी), कनाडा

द्वारा किया गया था। इस परियोजना का नेतृत्व स्टानली एल. विनेर ने और सहायता रथिन रॉय, पिनाकी चक्रवर्ती, भारतीय भूषण दाश और जे. स्टीफन फेरिस ने प्रदान की। उन्होंने, **''स्ट्रेंग्थनिंग रीसर्च एण्ड केपेसिटी डेवलपमेंट इन दि डिपार्टमेंट''** नामक परियोजना पूरी की जिसका प्रायोजन और वित्त पोषण आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार ने किया था।

आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान, डा. राय ने अनेक आमंत्रित व्याख्यान दिए। उन्होंने, भारत वाणिज्य चेम्बर्स द्वारा होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल, कोलकाता द्वारा 4 अप्रैल, 2014 को आयोजित एक विशेष सत्र में ''स्ट्रेटेजीज फार सस्टेंड इकोनामिक ग्रोथ इन इण्डिया'' पर एक व्याख्यान दिया। उन्होंने विपको लर्निंग सेंटर, बंगलौर में 3 जुलाई, 2014 को **''एडवांस्ड ग्रेजुएट समर वर्कशाप, 2014''**पर एक व्याख्यान दिया। उन्होंने, ''2014 कामन कमेन्समेंट प्रोग्राम फार सिम्बोइसिस स्कूल आफ इकोनामिक्स (एसएसई) और सीम्बोइसिस इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर स्टडीज एण्ड रीसर्च/एसआईसीएसआर)'' के अवसर पर ''इण्डियाज मेक्रो–फिस्कल बाइंड : केन कोआपरेटिव फेडरलिज्म बी दि आन्सवर ?'' पर एक व्याख्यान दिया, पुणे में 17 जुलाई, 2014 को ''सिम्बोइसिस स्कूल आफ इकोनामिक्स (एसएसई)'' पर एक व्याख्यान दिया। उन्होंने स्कूल आफ पब्लिक पॉलिसी, जिंदल स्कूल आफ गवर्नमेंट एण्ड पब्लिक पॉलिसी (जेएसजीपी), ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में शैक्षिक सत्र 2014–15 के लिए शुरूआती व्याख्यान दिया, 1 अगस्त 2014 को।

डॉ. राय ने, भारतीय राजदूतावास, रूस और इंस्टीट्यूट आफ ओरिएंटल स्टडीज, रूस विज्ञान अकादमी, मास्को द्वारा आयोजित ''इकोनामिक अपोरच्युनिटीज बिटविन इण्डिया एण्ड रूस'' पर एक गोलमेज सम्मेलन में 14–16 फरवरी 2015 को एक व्याख्यान दिया। उन्होंने ''मिंट'' सिंगापुर द्वारा आयोजित एक बजट–पश्चात् सम्मेलन में एक वक्ता के रूप में भाग लिया। विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर उन्होंने **''2015 इंटरनेशनल कन्फरेंस आन दि एमरजेंस आफ अफ्रीका''** में ''एमरजेंस एण्ड चेंजिज इन प्राडक्शन एण्ड कनजम्पशन मेथड्स ' इण्डियाज एक्सपीरिएन्स एज एमरजिंग इकोनामी'' पर एक वार्ता दी जिसका आयोजन गवर्नमेंट आफ कोटे डिवोइरे और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा आबिदजान, अफ्रीका में 18–20 मार्च, 2015 को किया गया था।

डॉ. राय ने, ''इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोआपरेशन : ट्रेण्ड्स एण्ड एमर्जिंग अपोरच्युनिटीज– पर्सपेक्टिव्ज आफ दि न्यु एक्टर्स'' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ''चेंजिंग डेवलपमेंट कोआपरेशन आर्किटेक्चर/न्यु ट्रेण्ड्स एण्ड एक्टर्स'' पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया, जिसकी सह–मेजबानी तुर्की सहयोग और समन्वयन एजेंसी (टीआईकेए), प्राइम मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस और तुर्की गणराज्य व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा 19–20 जून, 2014 को की गई। उन्होंने, ''ट्रांसफोर्मेशन इन मिडिल इंकम कंट्रीज एण्ड फ्युचर मल्टीलेट्रल डेवलपमेंट कारपोरेशन'' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी सह–मेजबानी शांघाई इंस्टीट्यूट्स फार इंटरनेशनल स्टडी (एसआईआईएस) और विश्व बैंक समूह, शंघाई (डब्ल्यूबीजी)'' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शांघाई, चीन में 27 जून 2014 को भाग लिया।

डा. रॉय ने ''एक गोलमेज, चीन–आस्ट्रेलिया क्षेत्रीय संगोष्ठी में निवेश और अवस्थापना'' पर एक सत्र में भाग लिया, जिसकी सह–मेजबानी शंघाई इंस्टीट्यूट फार इंटरनेशनल स्टडीज (एसआईआईएस) और ईस्ट एशियन

ब्यूरो आफ शंघाई, चीन ने 14–15 अप्रैल 2014 को की थी। उन्होंने **''एशिया–पेसिफिक आउटरीच मीटिंग आन सस्टेनेबिल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग''** में घरेलू संसाधन जुटाव'' पर एक सत्र में भाग लिया जिसकी सह–मेजबानी वित्त मंत्रालय, इण्डोनेशिया गणराज्य और ''एशिया तथा प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग'' द्वारा जकार्ता, इण्डोनेशिया में 10–11 जून, 2014 को की गई थी। उन्होंने, एक चर्चाकार के रूप में, **बिहार ग्रोथ कान्फरेंस 2014 में** ''राज्यों के अनुभव'' पर एक सत्र में, ''पॉलिटिकल इकोनोमी एण्ड ग्रोथ'' पर एक विशेष सत्र में 19–20 जुलाई, 2014 को पटना में भाग लिया।

डा. रॉय ने, **''मार्केट्स, लेबर एण्ड रेगुलेशन''** पर एक विश्व बैंक सम्मेलन में ''राजनीतिक अर्थव्यवस्था'' पर एक सत्र की अध्यक्षता की जिसका आयोजन नई दिल्ली में 17 दिसंबर, 2014 को किया गया था। उन्हें ''सम रीफ्लेक्शन्स आन दि साइंसिज आफ इकोनामिक्स, एज एप्लाइड टू इण्डिया'' पर एक व्याख्यान दिया, विवेकानन्द इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ), चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में 18 दिसंबर 2014 को। उन्होंने, **''टेन्थ एनुअल कन्फरेंस आन इकोनामिक ग्रोथ एण्ड डेवलपमेंट''** में ''इनइक्विलिटी इन इण्डिया'' पर एक सत्र में पैनलकार के रूप में भाग लिया, जिसका आयोजन आईएसआई, दिल्ली में 20 दिसंबर 2014 को किया गया था।

डा. रॉय ने ''एड्रेसिंग इनइक्वलिटीज इन एशिया एण्ड दि पैसिफिक'' पर एक उप–समारोह में एक पैनलकार के रूप में भाग लिया जिसकी मेजबानी ''एस्केप'' द्वारा बैंगकाक में 17–18 अगस्त 2014 को की गई थी। उन्होंने, प्रस्तावित मास्टर–प्लॉन फार स्ट्रेटेजिक रीजनल इकोनामिक डेवलपमेंट, अपडेटिंग कम्पीटिटिवनैस, रैंकिंग एण्ड एग्रीकल्चरल प्राडक्टिविटी फार 35 स्टेट्स एण्ड फेडरल टेरीटरीज आफ इण्डिया'' पर **''एशिया कम्पीटिटिवनैस इंस्टीट्यूट (एसीआई) : रीव्यू सेमिनार''** में एक चर्चाकार के रूप में भाग लिया, जिसकी मेजबानी एसीआई द्वारा ली कुआन यीव स्कूल आफ पब्लिक पॉलिसी (एलकेवाई स्कूल), नेशनल यूनिवर्सिटी आफ सिंगापुर (एनयूएस), सिंगापुर में 18–19 अगस्त 2014 को की गई थी।

डा. रॉय ने ''रीजनल इंटेग्रेशन इन साउथ एशिया'' पर **''13वां वार्षिक सम्मेलन, दक्षिण एशिया नेटवर्क आफ इकोनामिक रीसर्च इंस्टीट्यूट्स'' (एसएएनईआई)** में एक पैनलकार के रूप में भाग लिया, जिसकी सह–मेजबानी बंगलादेश विकास अध्ययन संस्थान (बीआईडीएस) द्वारा ढाका में 30–31 अगस्त 2014 को की गई थी। उन्होंने, **एनुअल श्री मोहन कुमार मंगलम मेमोरियल लेक्चर,** ''इण्डियाज मेक्रो–फिस्कल बाइंड : केन कोआपरेटिव फेडरलिज्म बी दि आन्सर'' ? पर, जिसका आयोजन भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज (एएससीआई) द्वारा एएससीआई, हैदराबाद में 16 सितंबर 2014 को किया गया था। उन्होंने, **''इंटरनेशनल ग्रोथ कान्फरेंस**, लंदन में 23–25 सितंबर 2014 को एक व्याख्यान दिया। उन्होंने ''ब्रिक्स'' पर एक सम्मेलन में व्याख्यान दिया , केम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन में 26–27 सितंबर 2014 को। उन्होंने ''टैक्स पॉलिसी एण्ड एंटरप्राइज डेवलपमेंट इन साउथ एशिया'' पर एक कार्यशाला में एक सत्र की अध्यक्षता की जिसका आयोजन संयुक्त रूप से एनआईपीएफपी, जीआईआई, आईआईडीएस, बीएनयू, आईपीएस, आईडीआरसी द्वारा संयुक्त रूप से एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में 15 अक्तूबर 2014 को किया गया था।

डा. रॉय ने, **''ओक्सफाम : ग्लोबल इनइक्विलिटी कम्पेन रिपोर्ट, लांच''** में ईविन इट

अप एण्ड एक्सट्रीम इनइक्विलिटी एट स्पेनिश कल्चरल सेंटर, नई दिल्ली में 31 अक्तूबर, 2014 को एक पैनलकार के रूप में भाग लिया। उन्होंने, **''एडीबी–एशियाई थिंक टैंक डेवलपमेंट फोरम, 2014–एक्सीलिरेटिंग इन्नोवेशन एण्ड इनक्लुजन फार ए प्रोसपरस एशिया''** में ''डायनेमिक्स आफ सस्टेनेबिल ग्रोथ'' पर एक सत्र में ''फिस्कल स्पेस फार इनक्लुजिव ग्रोथ इन एमर्जिंग मार्केट इकोनामीज'' में भाग लिया, माड्रेशन किया और वार्ता दी। इसकी मेजबानी कोरियाई विकास संस्थान (केडीआई) और एशियाई विकास बैंक द्वारा ग्राण्ड इंटर–कांटीनेंटल, सिओल, परनास, सिओल, कोरिया में 20–21 नवंबर 2014 को की गई थी।

डा. रॉय ने, ''चेनेलाइजिंग सस्टेनेबिल फाइनेंस'' पर पूर्ण अधिवेशन की सह–अध्यक्षता की और वह ''डिजाइनिंग, ए सस्टेनेबिल फाइनेंशियल सिस्टम फार इण्डिया'' पर समापन सत्र में विशिष्ट वक्ताओं के एक पैनल में भी शामिल हो गए, जिसका आयोजन संयुक्त रूप से फिक्की, नई दिल्ली में 25 नवंबर, 2014 को किया गया था। उन्होंने, ''इफेक्टिव काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी : इण्डियन एण्ड इंटरनेशनल एक्सपीरिएंसिज'' के संबंध में ''नेक्स्ट जेनेरेशन्स फिस्कल रिफार्म फ्रेमवर्क'' पर एनआईपीएफपी–डीईए : एफआरबीएम कांफ्रेंस'' पर ''एक्सपीरिएंसिज विद फिस्कल रूल्स'' पर सत्र की अध्यक्षता की जिसका आयोजन एनआईपीएफपी द्वारा होटल सिडाडे डे गोआ में 12–13 दिसंबर, 2014 को किया गया था।

डा. रॉय ने, ''फ्राम पावर्टी टू एम्पावरमेंट : दि क्रिटिकल रोल आन जाब्स एण्ड स्किल्स'' पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया, जिसका आयोजन ब्रूकिंग्स इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा 16 अप्रैल, 2014 को किया गया था। उन्होंने ''फाइनेंसिंग मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेन्ट्स इन डेवलपिंग कन्ट्रीज'' पर एक सम्मेलन में भाग लिया, जिसका आयोजन आईसीआरआईईआर द्वारा जकारन्दा हाल, आईएचसी, नई दिल्ली में 23 अप्रैल 2014 को किया गया था। उन्होंने, **''प्रोग्राम, डिजाइन फार वर्कशाप विद रेगुलेटर्स आन एफएसएलआरसी हेण्डबुक इंप्लीमेंटेशन''** में भाग लिया और व्याख्यान दिया जिसका आयोजन एनआईपीएफपी और एमओएफ द्वारा एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में 8 मई 2014 को किया गया था।

डा. रॉय ने, **''यू के –इण्डिया बिजनिस काउंसिल (यूकेआईबीसी) एण्ड असोचम गोलमेज''** मेकिंग इन इण्डिया : प्रोसपेक्ट्स एण्ड चेलेन्जिज'' में भाग लिया, जिसका आयोजन चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में 12 फरवरी, 2015 को किया गया था। उन्होंने ''वित्त पर संसदीय स्थाई समिति के समक्ष संसद भवन, नई दिल्ली में 18 फरवरी 2015 को प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने ''सस्टेनिंग डेवलपमेंट : आप्शन्स एण्ड अपोरच्युनिटीज'' पर एक चिंतन चर्चा में एक वक्ता के रूप में भाग लिया, जिसका आयोजन भारतीय कारपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा आईआईसी, नई दिल्ली में 19 फरवरी 2015 को किया गया था। उन्होंने, राज्य योजना आयोग, चेन्नई द्वारा 26 फरवरी 2015 को आयोजित ''एनवायरनमेंटल फिस्कल रिफोर्म्स एण्ड गुड्स एण्ड सर्विसिज टेक्स रेजीम'' पर एक राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला में भाग लिया।

उन्होंने, ''मैपिंग पाकिस्तान्स इंटरनल डायनेमिक्स : इम्प्लीकेशन्स फार स्टेट स्टेबिलिटी एण्ड रीजनल सिक्युरिटी'' पर एक कार्यशाला में भाग लिया, जिसका आयोजन संयुक्त रूप से नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियाई अनुसंधान (एनबीआर) और आब्जर्वर रीसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा ओबराय होटल, में 10 अगस्त 2014 को किया गया था। उन्होंने ''ब्रिक्स'' बैंक पर एफआईडीसी बैठक में भाग लिया, जिसका आयोजन विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना

पद्धति द्वारा नई दिल्ली में 3 सितंबर 2014 को किया गया था।

डा. रॉय ने, "बजट 2015 : व्हाट मैटर्स" पर उत्तर बजट पैनल चर्चा में एक पैनलकार के रूप में भाग लिया, जिसका आयोजन "कैपिटल : दि फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स क्लब" और आईआईएफटी, नई दिल्ली के छात्रों ने संयुक्त रूप से 1 मार्च 2015 को किया था। उन्होंने, सेंटर फार बजट एण्ड गवर्नेन्स एकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए) द्वारा 1 मार्च 2015 को आईआईसी, नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय बजट पर एक पैनल चर्चा में एक वक्ता के रूप में भाग लिया। उन्होंने विवेक राय द्वारा संपादित "गैटिंग इण्डिया बैक आन ट्रैक : एन एक्शन एजेंडा फार रिफोर्म" नामक पुस्तक पर एक चर्चा सत्र में एक पैनलकार के रूप में भाग लिया। पैनल चर्चा की अध्यक्षता डा. सुब्रमण्यन स्वामी ने की थी तथा अन्य चर्चाकार थे : डा. सुरजीत मित्रा, निदेशक, आईआईएफटी और श्री सुनिल जैन, प्रबंध संपादक, "फाइनेंशियल एक्सप्रैस", जिसका आयोजन 11 मार्च 2015 को आईआईसी, नई दिल्ली में किया गया था।

डा. राय ने, प्रो. लियु झोंगयी, शंघाई इंस्टीट्यूट्स फार इंटरनेशनल स्टडीज, चीन के साथ 16 जून 2014 को "चाइना–इण्डिया रीलेशंस एण्ड इकोनामिक कोआपरेशन इन मोदी एज" पर एक विचार–विमर्श चर्चा आयोजित की। उन्होंने, **"इण्डिया–आस्ट्रेलिया राउंडटेबल कान्फरेंस–जी–20"** का भी आयोजन किया, जिसका आयोजन एनआईपीएफपी, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन (इण्डिया) और ईस्ट इण्डिया ब्यूरो आफ इकोनामिक रीसर्च (ईएबीईआर), आस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी (एएनयू) द्वारा ताज विवन्ता, सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली में 10 सितंबर, 2014 को संयुक्त रूप से किया गया था।

डा. रॉय ने अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान दिए। उन्होंने, आईएएस अधिकारियों के लिए "पब्लिक फाइनेंस पर एक दिन के मॉड्यूल में (चरण–V), एलबीएसएनएए में 18 नवंबर 2014 को एक व्याख्यान दिया। उन्होंने, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के **"आईटीईसी / एससीएएपी प्रोग्राम"** के अंतर्गत "लर्निंग साउथ–साउथ कोआपरेशन" पर एक सत्र में "डेवलपमेंट फाइनेंस : एन ओवरआल पर्सपेक्टिव इन ए केपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम" पर, आरआईएस, नई दिल्ली में 24 नवंबर, 2014 को एक व्याख्यान दिया। उन्होंने, **"ट्रेनिंग प्रोग्राम आन पब्लिक फाइनेंस एण्ड बजट फार ओडिशा गवर्नमेंट आफीसर्स"** में "सम रिफ्लेक्शन्स आन दि "साइंस" आफ इकोनामिक्स एज एप्लाइड टू इंडिया" पर प्रमुख अभिभाषण दिया जिसका आयोजन ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, द्वारा 27 जनवरी 2015 को किया। उन्होंने, एक "भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) (2013 बैच) के अधिकारी प्रशिक्षार्थियों के लिए सार्वजनिक वित्त के संबंध में एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में "ट्विन–ट्विन डेफिसिट" पर एक व्याख्यान, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में 15 मई, 2014 को दिया। उन्होंने "**ट्रेनिंग एण्ड असिस्टेंस प्रोग्राम इन एफआरबीएम एक्ट फार दि आफिसर्स आफ कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया"** में "पोस्ट–क्राइसिस फिस्कल रूल्स : इश्यूज इन स्टेबिलाइजेशन" पर एक व्याख्यान एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में 12 सितंबर 2014 को दिया।

डा. रॉय का आलोच्य वर्ष के दौरान प्रकाशित कार्य था : "डिस्पेंसिंग मेक्रोइकोनामिक पॉलिसी एड्वाइस टू डवलपिंग कंट्रीज : दि आईएमएफ आर्टिकिल–IV कन्सल्टेशन्स", इयानातुल इस्लाम, इशराक अहमद और रकील रामोस के साथ, इयानातुल इस्लाम और डेविड कुसीरा (सं.) "बियोण्ड

मेक्रोइकोनामिक स्टेबिलिटी : स्ट्रक्चरल ट्रांसफोर्मेशन एण्ड इनक्लुजिव डेवलपमेंट में (आईएलओ : पालग्रेव मेकमिलन), जेनेवा, 2013 उनके अन्य प्रकाशित कार्यों में समाचार–पत्र लेख सम्मिलित हैं, जैसे कि ''इंडियाज गोल एट दि ''ब्रिक्स बैंक'', ''बजट 2014 सिगनल्स एरियाज आफ कन्टीन्युइटि एण्ड एरियाज आफ चेंज'', ''इकोनामिक डिप्लोमेसी विद चाइना एण्ड जापान'' ''मिन्ट'', 2014, ''एन अपोरच्युनिटी फार फिस्कल रिफोर्म'', बिजनेस स्टेण्डर्ड, 11 नवंबर, 2014, ''दि आर बी आई गवर्नर इज नाट ए बैटिंग मेन'', बिजनिस स्टैण्डर्ड, 10 दिसंबर, 2014, ''यस वी केन टू इकोनामिक डिप्लोमेसी'', बिजनेस स्टेण्डर्ड, 3 फरवरी 2015, ''फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट इज गेम चेंजर'', बिजनिस स्टेण्डर्ड, 28 फरवरी, 2015, ''नम्बर्स नीड टू बैक दि पॉलिटिक्स वैटर : एनहान्स्ड टेक्स डेवोल्युशन माडरेटिड टू मेनटेन रिसोर्स अलोकन फार सेंट्रल प्रायरटीज'' बिजनिस स्टेण्डर्ड, 1 मार्च 2015 । ''हाऊ फिस्कल क्रेडिबिलिटी मैटर्स'', बिजनेस स्टैण्डर्ड, 10 मार्च 2015, ''पुट इण्डिया फर्स्ट, नाट एयर इण्डिया'', बिजनिस स्टेण्डर्ड, 3 अप्रैल, 2015 ।

डा. रॉय ने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समितियों में अपनी सदस्यता जारी रखी – सातवां केंद्रीय वेतन आयोग, भारत सरकार, भारत में गरीबी के उपशमन के संबंध में प्रधानमंत्री का कार्य बल, नेशनल इंस्टीट्यूशन फार ट्रासफोर्मिंग इण्डिया (नीति आयोग), ''यूनेस्केप'' के लिए विशेषज्ञ समूह ; एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण, विभाजन के पश्चात् आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य के लिए नई राजधानी के संबंध में विभिन्न विकल्पों का अध्ययन करने के लिए आ. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत गठित समिति । वह, जी–20 मुद्दों पर वित्त मंत्री के लिए सलाहकार समूह के एक सदस्य ; आईएएस अधिकारियों के लिए तीसरे त्रिवर्षीय साइकिल आफ मिड कैरियर ट्रेनिंग (एमटीटीपी) (2013–14, 2014–15 और 2015–16), प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी (पीएमसी) के एक सदस्य बने रहे ।

डा. रॉय, मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद के एक सदस्य, नीति के कार्यान्वयन हेतु समग्र रूप से निदेश प्रदान करने के लिए (3 सितंबर 2013 और उसके बाद), चौदहवें वित्त आयोग के लिए केंद्रीय ज्ञापन तैयार करने के वास्ते, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, शासी बोर्ड, आर्थिक विकास संस्थान, राष्ट्रीय उत्तम शासन केंद्र (एनसीजीजी), नई दिल्ली और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों के लिए वर्तमान साधनोपाय (डब्ल्यूएमए)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) स्कीम सुविधा हेतु सलाहकार समिति ।

डा. रॉय ने केम्ब्रज कामनवैल्थ सोसायटी के एक फैलो के रूप में सम्मिलित हुए । वह निम्नलिखित के एक सदस्य बने रहे : रीडर्स ग्रुप, ग्लोबल ह्युमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी, बजट अध्ययनों हेतु के.एम. मणि केंद्र के लिए सलाहकार परिषद, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, भारत सलाहकार समिति, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), संधारणीय वित्तीय पद्धति की जांच ; मेटा समावेशी विकास परिषद, विश्व आर्थिक फोरम, जेनेवा और ''असोचम'' थिंक टैंक ।

डॉ. एम. गोविन्दा राव
पूर्व निदेशक

डॉ. सुदीप्तो मंडल
एमेरिटस प्रोफेसर

तपस सेन
प्रोफेसर

रीता पाण्डेय
प्रोफेसर

डॉ. आर. कविता राव
प्रोफेसर

डॉ. अजय शाह
प्रोफेसर

डॉ. एन. आर. भानुमूर्ति
प्रोफेसर

डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती
प्रोफेसर

डॉ. अंजन मुखर्जी
आननरी विजिटिंग प्रोफेसर

डॉ. प्रताप रंजन जेना
एसोसिएट प्रोफेसर

डॉ. लेखा चक्रवर्ती
एसोसिएट प्रोफेसर

डॉ. मीता चौधरी
एसोसिएट प्रोफेसर

डॉ. सच्चिदानन्द मुखर्जी
एसोसिएट प्रोफेसर

डॉ. एच. के. अमरनाथ
सहायक प्रोफेसर

डॉ. मुकेश कुमार आनन्द
सहायक प्रोफेसर

डॉ. मनीष गुप्ता
सहायक प्रोफेसर

डॉ. रूद्राणी भट्टाचार्य
सहायक प्रोफेसर

डॉ. भारती भूषण दाश
सहायक प्रोफेसर

डॉ. सुधांशू कुमार
सहायक प्रोफेसर

डॉ. सुकन्या बोस
सहायक प्रोफेसर

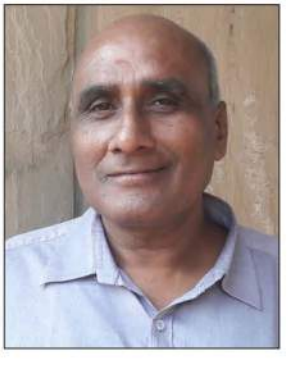

डॉ. दीवान चन्द
वरि. अनुसंधान अधिकारी

डॉ. गीता भटनागर
अनुसंधान एसोसिएट

डॉ. सताद्रु सिकदर
अनुसंधान एसोसिएट

डा. एम. गोविन्दा राव, पूर्व निदेशक, एनआईपीएफपी, को 10.11.2014 को एक एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया ; **''पार्लियामेंट्री स्टेण्डिंग कमेटी आन फाइनेंस''**, ''प्लानिंग विदआउट दि प्लानिंग कमीशन'' पर एक प्रस्तुतिकरण किया, 5 फरवरी, 2015 । आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान, उन्होंने सार्वजनिक अर्थशास्त्र से सम्बद्ध अनेक व्याख्यान दिए । उन्होंने, ''भारत में सरकारी वित्त की राजनीतिक अर्थव्यवस्था'' विषय पर **''गांधी कामराजू स्मारक व्याख्यान''** दिया, आचार्य नागाजफ्रन यूनिवर्सिटी, गुन्तुर, आ. प्रदेश, 21 दिसंबर 2014 । उन्होंने **''पीआरएस लेजिस्लेटिव ग्रुप सम्मेलन''** में ''फिस्कल फेडरलिज्म इन इण्डिया'' पर एक वार्ता दी, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली, 23 जनवरी 2015 । उन्होंने, ''रिवाइविंग दि इण्डियन इकोनामी : चेलेंजिज आफ फामफ्रलेटिंग ए रिफोर्म बजट'', पर एक वार्ता दी, दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान, नेशनल यूनिवर्सिटी आफ सिंगापुर, सिंगापुर, 3 फरवरी 2015 तथा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर, आनन्द में ''फिस्कल डेफिसिट्स, ग्रोथ एण्ड इन्फ्लेशन'' पर गुजरात आर्थिक एसोसिएशन कनफरेंस में बी. आर. शेनाय स्मारक व्याख्यान दिया, 14 फरवरी, 2014 ।

डा. राव ने, ''इंटरनेशनल कन्फरेंन्स आन इकोनामिक रिफोर्म्स इन इंण्डिया'' पर उद्घाटन भाषण ''ए न्यू इंस्टीट्यूशनल मेकेनिज्म फार फिस्कल मेनेजमेंट इन इण्डिया'' दिया, जिसका आयोजन अर्थशास्त्र विभाग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ केरल, कासरगोड द्वारा 16 फरवरी, 2015 को किया गया था । उन्होंने, जस्टिस के.एस. हेगडे स्कूल आफ मेनेजमेंट, लिट्टै, कर्नाटक में, ''रीवाइविंग दि इण्डियन इकोनामी : प्रोस्पेक्ट्स एण्ड चेलेंजिज'' पर एक व्याख्यान दिया, 17 फरवरी, 2015 । भारतीय प्रबंध संस्थान, कोज्हीकोड, कोच्ची कैम्पस में एक पैनल चर्चा में उन्होंने ''एक्सलिरेटिंग इकोनामिक रिफोर्म्स एण्ड एक्सपेक्टेशन्स फ्राम दि बजट'' पर एक वार्ता दी, 19 फरवरी 2015 । उन्होंने, भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर में ''भारत में राजकोषीय स्थिति'' पर एक व्याख्यान दिया, 25 फरवरी, 2015 ।

डा. राव ने, अपना समय एनआईपीएफपी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सेवारत अधिकारियों को शिक्षण प्रदान करने में लगाया । उन्होंने, ''भारत में सार्वजनिक वित्त : विकास, गरीबी और राजनीतिक अर्थव्यवस्था'' पर एक व्याख्यान 9 फरवरी 2015 को तथा ''ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पब्लिक फाइनेंस टू आफीसर ट्रेनीज आफ इण्डियन आडिट एण्ड एकाउंट्स सर्विस'' में ''फिस्कल फेडलरिज्म इन इण्डिया : रीसेन्ट डेवलपमेंट्स'' और ''टूवर्ड्स कोआपरेटिव फेडरलिज्म : दि रोल आफ ''नीति'' आयोग'' पर एक व्याख्यान 10 फरवरी 2015 को दिया ।

डा. राव ने, वित्त वर्ष 2014 के दौरान, एक पुस्तक और छः लेख प्रकाशित किए । उनकी पुस्तक ''स्टेट लेवल रिफोर्म्स, ग्रोथ एण्ड डेवलपमेंट इन इण्डियन स्टेट्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, न्यूयार्क, 2014 ; अरविन्द पनगढिया और पिनाकी चक्रवर्ती द्वारा सह–लिखित थी । उन्होंने, रिचर्ड बिर्ड के साथ ''गवर्नेन्स एण्ड फिस्कल फेडरेलिज्म'', ईशर जज आहलूवालिया, रवि कनबुर और पी.के. मोहंती (सं.) में लिखा, ''अर्बनाइजेशन इन इण्डिया : चेलेंजिज, अपोरच्युनिटीज एण्ड वे फार्वर्ड'', सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली । उनका पत्र ''फाइनेंसिंग अर्बन सर्विसिज : यूजर चार्जिज एण्ड लोकल टेक्सेशन'', एम. रामचन्द्रन (सं.) ''इण्डियाज अर्बन कन्फ्यूजन : चेलेंजिज एण्ड स्ट्रेटेजीज'' एण्ड ''पब्लिक फाइनेंस : डेवलपमेंट, इक्विटी एण्ड पॉलिटिकल इकोनामी'' में प्रकाशित हुआ, विमल जालान और पुलापरे बालकृष्ण (सं.) ''पालिटिक्स

इम्प्स इकोनामिक्स : एन इंटरफेस आफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनामिक्स इन कन्टेमपोरेरी इण्डिया और ''पालिटिकल इकानोमी आफ गवर्नमेंट फाइनेंस इन इण्डिया'', इण्डिया रीव्यू में। उन्होंने अपने लेख ''रोल आफ फंक्शन्स आफ ''नीति'' आयोग'', और ''फिस्कल फेडरलिज्म : अपोरच्युनिटीज एण्ड चेलेंजिज फार नेपाल''।

डा. राव ने, सदस्य, इंडीपेंडेंट कमीशन फार दि रिफोर्म आफ इंटरनेशनल कारपोरेट टेक्सेशन (आईसीआरआईसीटी), ने न्यूयार्क में पहली बैठक में भाग लिया, 18–19 मार्च 2015।

डॉ. सुदीप्तो मंडल, ने एनआईपीएफपी में दिसंबर 2014 में एक एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में अपने शैक्षिक कार्यकलाप पुनः आरंभ किए, 14वें वित्त आयोग के एक सदस्य के रूप में अपनी कार्यावधि समाप्त होने के बाद।

आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान, डा. सुदीप्तो मंडल ने अपनी अनुसंधान टीम के साथ जिसमें सताद्रु सिकदर, एनआईपीएफपी और समित चक्रवर्ती, आर्थिक विकास संस्थान, सम्मिलित थे, ''गवर्नेन्स एज सर्विस डेलीवरी : परफोर्मेन्स आफ इंडियन स्टेट्स'' नामक अपनी चालू परियोजना पर अपना कार्य जारी रखा। ''लेवल एण्ड कम्पोजीशन आफ सब्सिडीज इन इण्डिया : 1987–88 टू 2011–12'' पर उनकी अन्य परियोजना भी, एच.के. अमरनाथ और सतादफ्र सिकदर के साथ प्रगति पर है। डा. मंडल ने ''एनआईपीएफपी–मेक्रोइकोनामिक पॉलिसी सिमुलेशन मॉडल'' का और संशोधन और अनुप्रयोग, एन.आर. भानुमूर्ति, सुकन्या बोस और परमा देवी अधिकारी को मिलाकर एक टीम के साथ, चल रहे काम में अपना योगदान किया।

अनुसंधान परियोजनाओं के अलावा, डा. मंडल ने, भिन्न–भिन्न हैसियत से अनेक सेमिनारों और पैनल चर्चाओं में भाग लिया। वह, **16वें नीमराणा सम्मेलन** में ''मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ : हाऊ टू मेक (प्राडक्टिव जाब्स) इन इण्डिया'' पर सत्र में एक पैनलकार थे जिसका आयोजन एनसीएईआर द्वारा 12–14 दिसंबर 2014 को किया गया था। वह, ''विज़न, मिशन एण्ड प्रायरिटी थीम्स फार नेक्स्ट फ्यु ईअर्स'' पर एक सत्र में पैनलकार थे, नेशनल सेंटर फार गुड गवर्नेन्स, विज्ञान भवन एनेक्सी, 20 दिसंबर 2014 को। वह, ''वेस्ट बंगाल फ्राम एक्सटरनल पर्सपेक्टिव'' पर सत्र में, ''फोर्थ वेस्ट बंगाल ग्रोथ वर्कशाप'' में जिसका आयोजन भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता द्वारा 26–27 दिसंबर 2014 को किया गया था।

डा. मंडल ने, **''ओवल–आर्ब्जवर फाउंडेशन राउण्ड टेबल'' में ''मेजरिंग गवर्नेंस इन इण्डिया''** पर बैठक की अध्यक्षता की, नई दिल्ली, 4 फरवरी 2015। उन्होंने ''मेक इन इण्डिया : चेलेंजिज एण्ड चेंज एण्ड दि इण्डियन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेंट'', पर एक प्रमुख अभिभाषण दिया, **एनसीएईआर–पीआरआई सेमिनार**, 6 फरवरी, 2015। उन्होंने, ''गवर्नेन्स परफोर्मेन्स आफ इण्डियन स्टेट्स, 2011 और 2012'' में एक सेमिनार दिया, दक्षिण एशियाई सेमिनार श्रृंखला, एशिया विकास बैंक, मनीला, 17 फरवरी, 2015। उन्होंने, केविन रूड्ड, प्रधान, एशिया सोसायटी तथा पूर्व आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ एक पैनल चर्चा में भाग लिया, ''एशियाई क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दे'', आईसीआरआईइआर और एशिया सोसायटी, इण्डिया, 5 मार्च, 2015, नई दिल्ली।

डा. मंडल के प्रकाशनों में सम्मिलित थे : ''मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स : हाऊ इज इण्डिया डूइंग ?'' एस. जानकीरजन, एल. वेंकटाचलम और आर एम सालेथ (सं.), ''इण्डियन इकोनामी इन ट्रांजीशन, एसेज इन आर आफ सी.टी. कुरियन'', सेज इण्डिया, जनवरी 2015। उन्होंने समाचार–पत्र लेख भी लिखे जैसे कि ''बैलेंसिंग फिस्कल स्पेस'', फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 28–2–2015 और ''गवर्नमेंट

गेट्स इट्स प्रायरिटीज राइट'', फाइनेंशियल एक्सप्रैस, 9.3. 2015 ।

डॉ. तपस सेन, प्रोफेसर ने आलोच्य वर्ष में, ''इंटरगवर्नमेंटल फाइनेंस इन फाइव एमर्जिंग मार्केट इकोनामीज'' नामक एक परियोजना पर कार्यरत एक अनुसंधान टीम का नेतृत्व किया, जिसका प्रायोजन चौदहवें वित्त आयोग ने किया था, परियोजना के लिए अनुसंधान टीम में सम्मिलित अन्य सदस्य थे : सुधांशु कुमार, मनीष गुप्ता और एच.के. अमरनाथ ।

डा. सेन ने प्रताप आर जेना के साथ **''रीव्यू आफ कम्प्लाएंस आफ दि प्रोविजन्स मेड इन ओडिशा एफआरबीएम एक्ट फार दि ईअर, 2013–14,** जिसका प्रायोजन ओडिशा सरकार ने किया था । यह समीक्षा एक सांविधिक आवश्यकता की पूर्ति करता है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान, उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षार्थी प्रतिभागियों के समक्ष ''सब्सिडीज एण्ड इट्स इम्पेक्ट्स आन इण्डियन इकोनामी'', और ''स्टेट फाइनेंसिज'' पर दो व्याख्यान दिए । राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद में, 11 जुलाई, 2014 को । उन्होंने, वाणिज्यिक कर अधिकारियों के समक्ष सीटीआरपीएफपी में ''ब्राजील की संघीय प्रणाली में एक उप–राष्ट्रीय ''वार'' पर व्याख्यान दिया, समाज विज्ञान अध्ययन केंद्र (सीएसएसएस) कोलकाता में, 14 अगस्त 2014 को । उन्होंने ''राजस्थान राज्य वित्त'' पर एक सार्वजनिक व्याख्यान दिया, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में, 12 सितंबर 2014 को । इसके अलावा, उन्होंने स्नातकोत्तर छात्रों के समक्ष ''भारतीय सार्वजनिक वित्त'' पर चार व्याख्यान दिए, आईजीआईडीआर, मुंबई में, 28–29 अक्तूबर 2014 को । उन्होंने, भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों के लिए ''इम्प्रूविंग पब्लिक एक्सपेंडीचर मैनेजमेंट एण्ड फाइनेंशियल एकाउनटेबिलिटी'' पर एक व्याख्यान दिया, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे में, 21 नवंबर 2014 को । उन्होंने, ''सार्वजनिक नीति और शासन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के लिए'' भारत में राजकोषीय नीति'' पर भी जिंदल राजकीय और सार्वजनिक नीति स्कूल, सोनीपत, हरियाणा, 4 मार्च 2015 ।

डा. सेन ने ''रोल आफ मिनरल्स इन इकोनामिक डेपलपमेंट'', पर सार्वजनिक गोलमेज में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया, सम्बलपुर, ओडिशा, 30 नवंबर 2014 । उन्होंने, सीईएसपी, ज.ने.वि. द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में ''फिस्कल पॉलिसी इन इण्डिया'' पर एक पत्र प्रस्तुत किया, ''इण्डियाज मेक्रो इकोनामी'' पर 13 फरवरी 2015, नई दिल्ली । उन्होंने ''इंटरनेशनल कन्फरेंस आन चेंजिंग लेण्ड्स्केप आफ वर्ल्ड इकोनामीज : नीड फार आल्टर्नेटिव ग्रोथ मॉडल'' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए ''विकास और संवृद्धि'' पर समापन भाषण दिया, जी.डी. गोयनका यूनिवर्सिटी, गुड़गांव, 20 फरवरी, 2015 । उन्होंने, ''इन्नोवेटिव मेथ्ड्स आफ फाइनेंसिंग हायर एज्युकेशन'' पर एक सेमिनार में एक सत्र की अध्यक्षता की, 24 फरवरी 2015, एनयूईपीए–नई दिल्ली । उन्होंने, ''फिस्कल फेडरलिज्म एण्ड इट्स इम्पेक्ट आन इकोनामिक ग्रोथ इन इण्डियन स्टेट्स : रोल आफ ग्राण्ट्स एण्ड रायल्टीज'' पर एक कार्यशाला में एक सत्र की अध्यक्षता की जिसका आयोजन ''टेरी'' नई दिल्ली में और उसके द्व ारा किया गया था, 5 मार्च, 2015 । डा. सेन ने ''बजट 2015 पर एक कार्यशाला में ''फिस्कल पॉलिसी इम्परेटिव्ज एण्ड दि नेशनल बजट 2015'' पर एक प्रस्तुतिकरण किया जिसका आयोजन मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, चेन्नई में और उसके द्वारा 20 मार्च 2015 को किया गया था ।

डा. सेन को, यूएनडीपी (भारत) को प्रस्तुत एक अनुसंधान रिपोर्ट के एक बाह्य समीक्षाकर्ता के रूप में नियुक्त किया

गया, अक्तूबर 2014। वह, "इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली" के लिए समीक्षाकार के रूप में बने रहे। वह, भारत में स्कूल शिक्षा के संबंध में "वित्तीय सांख्यिकी विशेषज्ञ समूह" के एक सदस्य हैं, मा.सं.वि. मंत्रालय, भारत सरकार। वह शैक्षिक वित्त विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए), नई दिल्ली की शैक्षिक सलाहकार समिति के भी एक सदस्य है।

डा. सेन का वर्ष 2014–15 में प्रकाशित शैक्षिक कार्य है : "फिस्कल फेडरलिज्म इन आपरेशन : केस आफ इण्डिया", लेंसी लोबो, मृत्युंजय साहू और जयेश शाह (सं.), "फेडरलिज्म इन इण्डिया : टूवर्ड्स ए फ्रेश बेलेन्स आफ पावर", जयपुर, रावत पब्लिनकेशन्स।

डा. रीता पाण्डेय, प्रोफेसर, ने वर्ष 2014–15 में **"बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनीशिएटिव इन इण्डिया : क्वानटीफाइंग दि बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप एण्ड डवलपिंग रिसोर्स मोबाइलेजन स्ट्रेटेजीज"** नामक एक परियोजना शुरू की। इस अध्ययन का प्रायोजन यूएनडीपी और एमओईएफसीसी द्वारा किया गया था।

डा. पाण्डेय ने, वर्ष 2014–15 में अनेक सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लिया और पत्र प्रस्तुत किए। उन्हें, "इनकारपोरेटिंग बायोडाइवर्सिटी एण्ड इकोसिस्टम सर्विसिज इनटू नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी" पर एक कार्यशाला और नीति संवाद के लिए आमंत्रित किया गया, 20–21 सितंबर 2014, किंग्स कालेज, कैम्ब्रज, यू.के.। "ग्रीन एण्ड इनक्लुजिव इकोनामी" पर भारत–जर्मन विशेषज्ञ समूह के एक सदस्य के रूप में, डा. पाण्डेय ने इसकी तीसरी बैठक में भाग लिया, नवंबर 2014, बर्लिन, जर्मनी। इसके अतिरिक्त उन्होंने **सेकेण्ड यूरोपियाई रिसोर्स फोरम** में भाग लिया, 10–11 नवंबर, 2014, बर्लिन, जर्मनी में। उन्हें "रिफोर्मिंग फोसिल फ्युल सब्सिडीज फार एन इनक्लुजिव ग्रीन इकोनामी" पर एक कार्यशाला में एक विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसका आयोजन यूएनईपी और जीआईजेड द्वारा 28–29 अप्रैल 2014 को नैरोबी, केन्या में किया गया था।

"रोल आफ फिस्कल इन्स्ट्रुमेन्ट्स इन प्रोमोटिंग लो कार्बन टैक्नोलॉजी इनोवेशन" नामक एक पत्र (सह–लेखक : मीता केसवानी मेहरा) डा. पाण्डे द्वारा "फिस्कल पॉलिसीज एण्ड दि ग्रीन इकोनामी ट्रानजीशन : जेनेरेटिंग नोलीज क्रिएटिंग इम्पेक्ट" पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक पत्र प्रस्तुत किया गया, 29–30 जनवरी, वेनिस, इटली।

उन्होंने, 'एनवायरनमेंटल फिस्कल रिफोर्म्स एण्ड गुड्स सर्विसिज, टेक्स रेजीम" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित और उसमें भाग लिया, 26 फरवरी, 2015, चेन्नई (सह–आयोजक : तमिलनाडु राज्य योजना आयोग)। उन्होंने, "फिस्कल इन्स्ट्रुमेन्ट्स फार एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन" पर एक व्याख्यान दिया, 13 मई 2014, आईईएस के परिवीक्षार्थियों के लिए, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली।

डा. पाण्डेय के प्रकाशनों में दो एनआईपीएफपी कार्य पत्र सम्मिलित हैं–एक पुस्तक तथा एक लेख, "डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इंडेक्स फार हिल स्टेट्स इन इण्डिया", कार्य पत्र सं. 134 का प्रकाशन अप्रैल 2014 में किया गया, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली (सह–लेखक : पुरनमिता दास गुप्ता) तथा "ग्राउण्ड वाटर इरीगेशन इन पंजाब : सम इश्यूज एण्ड वे फार्वर्ड, एनआईपीएफपी कार्य पत्र सं. 140, अगस्त 2014 में प्रकाशित किया गया। उनकी "दि नेशनल क्लीन एनर्जी फण्ड आफ इण्डिया : ए फ्रेमवर्क फार प्रोमोटिंग इफेक्टिव यूटीलाइजेशन" नामक पुस्तक, स्प्रिंगेर द्वारा "एनर्जी पॉलिसी ब्रीफ सीरीज 2014" के अंतर्गत प्रकाशित की गई

(सह–लेखक : संजय बाली और नंदिता मोंगिया) । डा. पाण्डेय को ''न्यूजलेटर आफ दि ग्रीन फिस्कल पॉलिसी नेटवर्क'' के उद्घाटन अंक में'' एक लेख लिखने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसकी स्थापना यूएनईपी, जीआईजेड और आईएमएफ द्वारा की गई थी, अक्तूबर 2014 ।

डा. आर. कविता राव, प्रोफेसर ने **''टेक्स पॉलिसी एण्ड एनटरप्राइज डेवलपमेंट इन साउथ एशिया''** नाम परियोजना पूरी की । इसे ''गवर्नेन्स इंस्टीट्यूट नेटवर्क इंटरनेशनल, इस्लामाबाद'' द्वारा वर्ष 2014–15 में प्रायोजित किया गया था । उनकी परियोजना **''स्टडी आन डेवलपमेंट आफ एन एनेलिटिकल मॉडल फार वाइडनिंग आफ दि टेक्सपेयर्स बेस''** पूरी होने वाली है । उन्होंने, **''स्टडी आन बिहार स्टेट फाइनेंसिज–पॉलिसी आप्शन्स फार टेक्स राशनलाइजेशन एण्ड मोबिलाइजेशन आफ रेवेन्यु''** नामक चल रही परियोजना पर भी कार्य करना जारी रखा, तपस सेन और सच्चिदानन्द मुखर्जी के साथ ।

डा. राव ने ''फैक्टर्स इनफ्लुएंसिंग अनइनकोरपोरेटिड एनटरप्राइजिज टू रजिस्टर विद स्टेट टैक्स अथॉरिटी : एन एनेलिसिस विद एनटरप्राइजिज सर्वे डेटा'' पर एक सहलिखित पत्र **''पेपर्स इन पब्लिक इकोनामिक्स एण्ड पॉलिसी''** एक सम्मेलन में प्रस्तुत किया । उन्होंने, ''थ्योरी एण्ड प्रिंसिपल्स आफ टेक्सेशन'' और ''टेक्सेशन आफ गुड्स एण्ड सर्विसिज'' पर एक व्याख्यान (सुधांशु कुमार के साथ), भारतीय सांख्यिकीय सेवा परिवीक्षार्थियों के लिए, 18 जून 2014 ; ''गुड्स एण्ड सर्विसिज टैक्स (जीएसटी) एण्ड इश्यूज इन अनएकाउंटिड इकोनामी'', **अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस और आईएफएस) के अधिकारियों के लिए ''ट्रेनिंग प्रोग्राम आन फिस्कल पॉलिसी एण्ड मेक्रोइकोनामिक मैनेजमेंट''** पर, एनआईपीएफपी, 19 जून 2014 तथा ''रेवेन्यु रीसीप्ट्स : इश्यूज रिलेटिंग इण्डियन टैक्स सिस्टम'' पर, **''ट्रेनिंग प्रोग्राम इन एफआरबीएम एक्ट''** पर सीएजी अधिकारियों के लिए, 11 सितंबर 2014 । उन्होंने ''टैक्स पॉलिसी एण्ड एन्टरप्राइजिज डेवलपमेंट इन साउथ एशिया'' पर एक दिन की नीति निर्माण कार्यशाला में भाग लिया, जिसका आयोजन संयुक्त रूप से एनआईपीएफपी, जीआईआई, आईआईडी, बीएनयू, आईपीएस और आईडीआरसी द्वारा संयुक्त रूप से एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में किया गया, 15 अक्तूबर, 2014 ।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान, डा. राव के प्रकाशित कार्यों में तीन लेख सम्मिलित हैं : ''पॉलिसी आप्शन्स फार इनक्लुडिंग पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली, वस्तु और सेवा कर में,'' खण्ड 50, अंक 9, 2015, ''इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, ''कारपोरेट टेक्सिज एण्ड एग्जम्प्शन्स : व्हाट डज दि प्रोपोस्ड एजेंडा मीन ? खण्ड 4, अंक 2, मार्च 2015 और ''इंकम टैक्स चेंजिज : व्हाट इज दि आब्जेक्टिव एण्ड व्हाट आर दि इम्प्लीकेशन्स ? खण्ड–XLIX, अंक 32, ''एक्सप्लोरिंग पॉलिसी आप्शन्स टू इन्क्लूड पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली–भारत में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के अंतर्गत'', (एस. मुखर्जी के साथ), अंक 136 और ''हवाला बाजारों की विद्यमानता में नीतियां डिजाइन करना'' (सुरांजली टंडन), अंक 142, एनआईपीएफपी कार्य पत्र श्रृंखला में प्रकाशित हुई ।

डा. इला पटनायक, प्रोफेसर (भा.रि. बैंक पीठ), को वेतन के बिना छुट्टी मंजूर की गई, प्रारंभ में 1 मई 2014 से दो वर्ष की अवधि के लिए, जिससे कि वह प्रधान आर्थिक

सलाहकार, वित्त विभाग, आर्थिक कार्य विभाग में अपना कार्य संभाल सकें।

डा. अजय शाह, प्रोफेसर ने वर्ष 2014–15 के दौरान अपनी परियोजना, एनआईपीएफपी–यूआईडीएआई स्टडी आन प्राइसिंग एण्ड दि **ओथेनटिकेशन एण्ड ईकेवाईसी सेवाएं, इसके द्वारा प्रस्तावित'',** भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित। उन्होंने सतत नामांकन, अद्यतन बनाने और यूआईडीएआई द्वारा प्रस्तावित/प्रस्तुत की जाने वाली अन्य सेवाओं के लिए व्यवसाय योजना के विभिन्न मॉडल विकसित करने के लिए एनआईपीएफपी–यूआईडीएआई परामर्श परियोजना को भी कवर किया जा सके। डा. शाह ने, **एनआईपीएफपी–डीईए अनुसंधान** कार्यक्रम का एक भाग बने रहे जिसे आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था (1 अप्रैल, 2014–31 मार्च 2017)। **वह व्यवसाय साइकिल्स पर अनुसंधान** भी आयोजित कर रहे हैं, इण्डिया वैल्युं फण्ड एसोसिएट्स द्वारा प्रायोजित।

डा. शाह को **''असेस्मेंट आफ दि रिस्कीनैस आफ दि एयरपोर्ट सेक्टर एण्ड एस्टीमेटिंग फेयर रेट आफ रीटर्न आन इक्विटी (आरओई)** से संबंधित एक कार्य सौंपा गया, जिसे एयरपोर्ट इकोनामिक रेगुलेटरी अथोरिटी आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित किया गया था। डा. शाह द्वारा आयोजित चल रही एक परियोजना है: ''फारेन बोरोइंग बाई इण्डियन फर्म्स: इम्प्लीकेशन्स फार ग्रोथ एण्ड मेक्रोइकोनामिक स्टेबिलिटी''। डा. शाह द्वारा आयोजित चल रही परियोजना है ; फारेन बोरोइंग बाई इण्डियन फर्म्स: इम्प्लीकेशन्स फार ग्रोथ एण्ड मेक्रोइकोनोमिक स्टेबिलिटी'', जिसे इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर: लंदन अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस स्कूल, यू.के. द्वारा प्रायोजित किया गया था।

आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान, डा. शाह ने अनेक व्याख्यान दिए जिन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) द्वारा मसूरी में आयोजित किया गया था। 28 नवंबर 2014 को उन्होंने ''फाइनेंशियल सेक्टर रिफोर्म्स'' पर एक व्याख्यान **आईएएस अधिकारियों के लिए चरण–V मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम** में दिया। उन्होंने ''असम्भव, ट्रिनिटी'', ''स्टेबिलाइजेशन आफ मोनेटरी पॉलिसी'', ''स्टेबिलाइजेशन आफ फिस्कल पॉलिसी'' और अखिल भारतीय सेवाओं में नए प्रवेशकर्त्ताओं, यथा आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस, समूह ''क''–केंद्रीय सेवाओं और शाही भूटान सिविल सेवाओं से प्रतिभागियों के लिए 89वें फाउंडेशन कोर्स में ''करेंट इण्डियन थिंकिंग पर व्याख्यान दिए 27 और 28 अक्तूबर 2014 को। वह, ''फिस्कल चेलेंजिज बिफोर दि न्यू गवर्नमेंट एण्ड दि एमर्जिंग कानटोर्स फ्राम दि बजट'' पर चर्चा करने के लिए, एक पैनलकार थे जिसे चरण–III पर आईएएस अधिकारियों के लिए मिड–कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम'' 8 अक्तूबर 2014 को आयोजित किया गया था। उन्होंने, चरण–III मिड–कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फार आईएएस अधिकारियों के लिए 'एन ओवरव्यु आफ इण्डियन इकोनामी'' पर एक व्याख्यान 19 अगस्त 2014 को एलबीएस एनएए में भी दिया।

डा. शाह ने, ''इवोल्युशन आफ इण्डियाज एक्सचेंज रेट'', और ''स्टेट केपेसिटी'' पर एक सप्ताह के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफएस) अधिकारियों के लिए ''फिस्कल पॉलिसी एण्ड मेक्रोइकोनामिक मैनेजमेंट'' पर एक वार्ता दी जिसका आयोजन एनआईपीएफपी, नई दिल्ली द्वारा 16–20 जून 2014 को किया गया था।

डा. शाह ने न केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान दिए बल्कि अपना समय पूरे देश में सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने पर भी लगाया। उन्होंने "इण्डियन फाइनेंशियल मार्केट्स–इंटेग्रेशन फार ए पैराडाईम शिफ्ट, सीआईआई छठा पूंजी बाजार शिखर–वैश्वीकरण और भारतीय पूंजी बाजार का विकास" पर एक सत्र में भाग लिया और उसे सम्बोधित किया जिसका आयोजन सीआईआई द्वारा 30 मार्च 2015 को मुंबई में किया गया था। उन्होंने एक चर्चावार के रूप में भाग लिया तथा **"ईएम एक्सचेंज रीसर्च प्रोग्राम"** में देश–विशिष्ट दबावों" पर एक प्रस्तुतिकरण भी किया जिसका आयोजन नीमराणा फोर्ट पैलेस, राजस्थान में 6 से 8 मार्च 2015 तक किया गया था। उन्हें **"इण्डिया एण्ड दि पोस्ट 2015 एजेण्डा : शेपिंग दि कनेक्शन्स बिटविन लॉ एण्ड डेवलपमेंट"** में एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था जिसका आयोजन एडवोकेट्स फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट एण्ड बिंघम सेंटर फॉर रूल आफ लॉ द्वारा 27 फरवरी 2015 को नई दिल्ली में किया गया था। उन्होंने "इन्फ्रास्ट्रक्चर एट इण्डियन इकोनामिक पॉलिसी स्ट्रेटजी कन्फरेंस" पर एक सत्र में "सैटिंग अप दि सेकेण्ड वेब" में भाग लिया और एक प्रस्तुतिकरण किया। इसका आयोजन एनआईपीएफपी द्वारा 12–13 जनवरी 2015 को मधुबन रिसोर्ट, गुजरात में किया गया था।

डा. शाह ने, "नेक्स्ट जेनेरेशन फिस्कल रिफोर्म फ्रेमवर्क्स टू डेलिवर इफेक्टिव काउंटर–साइक्लिकल पॉलिसी ; इण्डियन एण्ड इंटरनेशनल एक्सपीरिएंसिज" पर एक सम्मेलन में "नेक्स्ट स्टेप्स इन फिस्कल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग" पर एक सत्र में "फिस्कल फाइनेंशियल एण्ड मोनेटरी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग" पर एक प्रस्तुतिकरण किया जिसका आयोजन एनआईपीएफपी, नई दिल्ली और आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12–13 दिसंबर 2014 को होटल सिडाडे डे, गोआ में किया गया था। उन्होंने, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की सिफारिश पर "भारतीय वित्तीय संहिता संबंधी राष्ट्रीय सेमिनार में "रेगुलेटरी रेजीम : आर्किटेक्चर, गवर्नेन्स एण्ड अप्रोचिज" पर तकनीकी सत्र में एक वार्ता दी, मुंबई में 29 नवंबर, 2014 को।

डा. शाह, "फाइनेंसिंग फार इकोनोमिक ग्रोथ–ए पॉलिसी रोडमेप" पर एक सेमिनार में एक सत्र में वक्ता थे, जिसका आयोजन वित्त विभाग, गुजरात सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को गांधीनगर, गुजरात में किया गया था। उन्होंने, "डिपोजिटरी रीसीप्ट : दि चेंजिंग पैराडाइम" पर एक सेमिनार में वक्ता के रूप में भाग लिया, जिसका आयोजन बीएसई द्व ारा बीएनवाई मेलोन और पिवोट मेनेजमेंट कनसल्टिंग की भागीदारी के साथ 8 सितंबर, 2014 को मुम्बई में किया गया था। वह, "एमर्जिंग पेंशन लेण्डस्केप इन इण्डिया–दि वे फोरवर्ड एट दि फर्स्ट पेंशन कानक्लेव" पर चर्चा सत्र में एक पैनलकार थे जिसका आयोजन पेंशन फण्ड रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथोरिटी द्वारा 26 अगस्त 2014 को इण्डिया हेबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में किया गया था। उन्होंने "इनसोल इण्डिया कन्फरेंस आफ इण्डियन इकोनामी–चेलेंजिज, रीकन्सट्रक्शन एण्ड इफेक्ट आफ दि कंपनी एक्ट, 2013" में "प्रेजेन्ट स्टेट्स आफ इनसोलवेंसी लॉ इन इण्डिया विद कम्पेरीजन आफ ओईसीडी कन्ट्रीज" पर एक वक्ता के रूप में भाग लिया, जिसका आयोजन "इनसोल, इण्डिया" द्वारा 2 से 4 मई 2014 तक चंडीगढ़ में किया गया था।

डा. शाह के आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान प्रकाशित कार्यों में सम्मिलित थे : "फंडामेंटल रीडिजाइन आफ फाइनेंशियल लॉ : दि इण्डियन अप्रोच", इला पटनायक के

साथ, ''इण्डिया रिव्यू'' खण्ड 14, अंक 1, पृ. 91–110, मार्च 2015 और ''मोटिवेशन्स फार कैपिटल कन्ट्रोल्स एण्ड देअर इफेक्टिवनैस'', राधिका पाण्डेय, गुरनैन के. पसरीचा और इला पटनायक के साथ, बैंक आफ कनाडा आधार पत्र, फरवरी 2015 ।

डा. शाह, ''रेजोल्युशन कारपोरेशन, पब्लिक डेट मेनेजेंट एजेंसी'' पर कार्य दल, ''फाइनेंशियल सेक्टर अपीलेट ट्रिब्युनल'' पर कार्य दल, ''फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट सेंटर'' पर कार्य दल और पेंशन सलाहकार समिति के सितंबर 2014 में एक सदस्य बन गए । वह, ''कामन क्लीयरिंग फार कामोडिटी एक्सचेंजिज'' पर कार्य दल के भी जून 2014 में एक सदस्य बन गए । डा. शाह, '' नेशनल बल्क हेण्डलिंग कारपोरेशन लि.'' के निदेशक बोर्ड में 2014 में और ''गुजरात उद्योग विद्युत क. लि., में 2015 में शामिल हो गए । उन्होंने, गुजरात राज्य उर्वरक और केमिकल्स लि. में (2006 से), एक्सेंट केपिटल एडवाइजर्स इण्डिया प्रा. लि. में (2008 से) और सेंटर फार मानीटरिंग इण्डियन इकोनामी प्रा. लि. में (1993 से) निदेशक के पद पर अपनी स्थिति बनाए रखी ।

डा. एन.आर. भानुमूर्ति, प्रोफेसर ने **''मेक्रोइकोनामिक पॉलिसी सिमुलेशन्स फार दि फोर्टीन्थ फाइनेंस कमीशन''** नामक परियोजना पूरी की जिसे 2014–15 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा प्रायोजित किया गया था । सुकन्या बोस और परमा देवी अधिकारी अनुसंधान टीम के अन्य सदस्य थे । उन्होंने पांच साल तक (2010–2015) डा. सुकन्या बोस के साथ **''मिड टर्म एप्राइजल फार दि ट्वेल्थ प्लान पीरियड फार प्लानिंग कमीशन''** पर भी कार्य किया ।

डा. भानुमूर्ति ने, एच.के. अमरनाथ, अखिलेश वर्मा और आदर्श गुप्ता को मिलाकर अपनी अनुसंधान टीम के साथ **''अंडरस्टेडिंग हाई अनस्पेन्ट बेलेंसिज एण्ड फंड फ्लो मैकेनिज्म इन मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम''** नामक अपनी परियोजना पूरी की, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया था । उन्होंने, ''यूनिसेफ'' भोपाल द्वारा प्रायोजित **''एमडीजी रिपोर्ट फार मध्य प्रदेश''** परियोजना पर अपना कार्य एच.के. अमरनाथ, सुकन्या बोस, परमा देवी अधिकारी और अर्काज्योति जाना के साथ जारी रखा । इस वर्ष उन्होंने एक छात्र को अनुसंधान मार्गदर्शन प्रदान किया जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सफलतापूर्वक पी.एचडी. डिग्री अवार्ड की गई ।

वर्ष 2014–15 के दौरान डा. भानुमूर्ति सेमिनारों, सम्मेलनों, वार्ताओं और व्याख्यानों में व्यस्त रहे । उन्होंने ''एनसीएईआर क्वार्टरली रीव्यु आफ दि इण्डियन इकोनामी'' के लिए एक चर्चाकार के रूप में भाग लिया, 13 नवंबर 2014 । वह, ''फिस्कल चेलेंजिज विफोर दि न्यु गवर्नमेंट एण्ड दि एमर्जिंग कन्टोर्स फ्राम दि बजट'' पर एक सत्र में पैनलकार थे, 8 अक्तूबर 2014 को एलबीएसएनएए में । उन्हें, **''पालिसीज फार सस्टेनिंग हाई ग्रोथ इन इण्डिया''** पर एक सम्मेलन में एक चर्चाकार के रूप में आमंत्रित किया गया, 20 अगस्त, 2014 । वह, ''इण्डिया 2020 : इकोनोमिक आउटलुक'' पर एक चर्चा में पैनलकार थे जिसका आयोजन डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा 22 अगस्त 2014 को किया गया था । वह, ''यूनेस्केप'' इकोनामिक एण्ड सोशल सर्वे आफ एशिया एण्ड दि पेसिफिक–2014'' के विमोचन के दौरान एक पैनलकार थे, 30 सितंबर 2014, आईआईसी, दिल्ली । उन्होंने ''यूएन–ईएससीडब्ल्यूए'', बेरूत, लेबनान द्वारा 8 से 10 दिसंबर 2014 को आयोजित एक कार्यशाला में ''मेक्रो–इकोनामीट्रिक मॉडलिंग'' पर व्याख्यान तथा ''मोनेटरी पॉलिसी इन इण्डिया

एण्ड आरबीआई'' पर एक वार्ता दी, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, 16 जुलाई, 2014। उन्होंने, ''इम्प्लीकेशन्स आफ यूनियन बजट'' पर प्रमुख अभिभाषण दिया, ''स्कोप'' कन्वेंशन सेंटर, 11 जुलाई, 2014।

डा. भानुमूर्ति ने **''थर्ड इंटरनेशनल वर्कशाप आन एक्सेस टू फाइनेंस,** XL **आर**–I'' के दौरान, ''फाइनेंशियल एक्सेस–मेजरमेंट एण्ड डीटरमीनेन्ट्स : ए केस स्टडी आफ अनआर्गनाइज्ड मेन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजिज इन इण्डिया'' पर एक पत्र प्रस्तुत किया, जमशेदपुर, 30–31 अक्तूबर 2014। उन्होंने ''मेक्रोइकोनामिक इश्यूज इन इण्डिया : मोनेटरी पॉलिसी एण्ड फिस्कल पॉलिसी'' पर एक वार्ता दी, इंटरनेशनल समर स्कूल, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, 19 जून 2014, ''टार्गेटिंग डेट एण्ड डेफिसिट'' पर, आईएएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एनआईपीएफपी 18 जून, 2014, ''फिस्कल–मोनेटरी नेक्सस इन दि कन्टेक्स्ट आफ टार्गेटिंग डेट'', आईईएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, 12 मई और ''फिस्कल एण्ड मोनेटरी पॉलिसीज इन इण्डिया'', पर, ''इंस्टीट्यूट आफ गवर्नमेंट एकाउंट्स एण्ड फाइनेंस'', 10 फरवरी, 2015।

डा. भानुमूर्ति ने ''जी डी गोयनका यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रमुख अभिभाषण दिया, 20 फरवरी, 2015, ''इम्प्लीकेशन्स आफ यूनियन बजट, 2015–16'' पर, ''पेट्रोफेड'', दिल्ली में, 2 मार्च 2015। उन्होंने ''फिस्कल–मोनेटरी पॉलिसीज इन इण्डिया'' पर एक आमंत्रित वार्ता दी, इंस्टीट्यूट आफ गवर्नमेंट एकाउंट्स एण्ड फाइनेंस, 16 मार्च 2015। उन्होंने 'वेक्टर आटो रीग्रेसन मॉडल'' पर दो व्याख्यान दिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 18–19 मार्च, 2015। उन्होंने ''फिस्कल–मोनेटरी नेक्सस इन इण्डिया'' पर एक वार्ता दी, आईएसएस अधिकारियों के लिए, एनआईपीएफपी, 25 मार्च 2015। उन्होंने, ''अनस्पेन्ट बेलेंसिज एण्ड फण्ड फ्लो मैकेनिज्म'' पर प्रमुख अभिभाषण दिया, ''एमजीएनआरईजीएस'' के अंतर्गत, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, 28 मार्च, 2015।

अनुसंधान–उन्मुख परियोजनाओं के अलावा, डा. भानुमूर्ति ने आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान अपना समय बहुत–सी सरकारी समितियों और शैक्षिक निकायों पर बिताया। वह, 14वां वित्त आयोग अवार्ड, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ''रेवेन्यु डेफिसिट ग्राण्ट्स'' जारी करने के लिए केंद्रीय मानीटरन समिति (सीएफसी) के एक सदस्य थे। वह, ''रेवेन्यू फोरकास्टिंग, टेक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफोर्म्स कमीशन'', भारत सरकार, 2014–15'' पर फोकस ग्रुप के एक सदस्य थे। वह, सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के संबंध में सलाहकार समिति के एक सदस्य के रूप में बने रहे। आजकल वह, अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय आर्थिक एसोसिएशन ट्रस्ट के प्रबंधन ट्रस्टी और भारतीय इकोनामीट्रिक सोसायटी के सचिव हैं। वह, जुलाई 2014 से ''नेशनल रेफ्रेंस ग्रुप'', ''कट्स'' जयपुर के एक सदस्य हैं।

आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान, डा. भानुमूर्ति के अनेक प्रकाशन प्रकाशित हुए। उनकी सह–लिखित पुस्तक ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम'' के अंतर्गत ''अनस्पेन्ट बेलेसिंज एण्ड फण्ड फ्लो मेकेनिज्म'' 2014 में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने पत्र ''रीसेंट डाउनटर्न इन एमर्जिंग इकोनोमीज : मेक्रोइकोनामिक इम्प्लीकेशन्स फार दि सस्टेनेबिल डेवलपमेंट : ए केस स्टडी फार इण्डिया'' के साथ यूएन–डीईएसए कार्य पत्र श्रृंखला में योगदान किया, का. पत्र 137, न्यूयार्क 2014। वसीम अहमद और संजय सहगल के सहयोग से उन्होंने ''दि यूरोजोन क्राइसिस

एण्ड इट्स कन्टेजियन इफेक्ट्स आन दि यूरोपियन स्टाक मार्केट्स'' नामक एक लेख प्रकाशित किया, ''स्टडीज इन इकोनामिक्स एण्ड फाइनेंस, 2014, खण्ड 31, अंक 3 और ''रेजीम डीपेन्डेंट डायनेमिक्स एण्ड यूरोपियन स्टाक मार्केट्स : इज असेट अलोकेशन रिअली पासिबिल ?'' ''एम्पीरिका : जरनल आफ यूरोपियन इकोनामिक्स'', फरवरी 2015, खण्ड 42, पृ. 77–107 ।

डा. भानुमूर्ति ने ''एक्सटर्नल शाक्स एण्ड दि इण्डियन इकोनामी : एनेलाइजिंग थ्रू ए स्माल, स्ट्रक्चरल क्वार्टरली मेक्रोइकोनामीट्रिक माडल'' (लोकेन्द्र कुमारवत के साथ) का प्रकाशन किया, बी. कामैय्या (सं.) के ''सिलेक्ट इश्यूज इन मेक्रोइकोनामिक्स : ए क्वानटीटेटिव अप्रोच : ए फेस्टक्रिफ्ट इन आनर आफ दिलीप नचाने'', आईयूपी पब्लिकेशन्स में । उन्होंने ''आयल प्राइस शॉक, पास–थ्रु पॉलिसी एण्ड इट्स इम्पेक्ट आन दि इण्डियन इकोनामी'' पर एक लेख लिखा, रतन खसनाबिस और इन्द्राणी चक्रवर्ती (सं.) के ''मार्केट रेगुलेशन्स एण्ड फाइनेंस : ग्लोबल मेल्टडाउन एण्ड फाइनेंस : ग्लोबल मेल्टडाउन एण्ड दि इण्डियन इकोनामी'', में, स्प्रिंगेर, मई 2014 (सुरजीत दास और सुकन्या बोस के साथ), पृ. 231–253 । उनका लेख ''मॉडलिंग इण्डियाज एक्सटर्नल सेक्टर : रिव्यु एण्ड सम एम्पीरिक्स'', एनसीएईआर (सुकन्या बोस और स्वयंसिद्धा पाण्डा के साथ), ''मार्जिन–दि जरनल आफ एप्लाइड इकोनामिक रीसर्च, खण्ड 8, अंक 4, 2014 ।

डा. भानुमूर्ति ने ''डज वीक रूपि मैटर फार इण्डियाज एक्स्पोर्ट्स'' का भी लेखन किया, चंदन शर्मा के साथ, एलुमलाई कन्नन (सं.) के ''इकोनामिक ग्रोथ, ट्रेड एण्ड पावर्टी : ए कम्पेरेटिव एनेलिसिस आफ इण्डिया एण्ड चाइना'', कोणार्क पब्लिशर्स : टी.ए. भवानी के साथ, ''फाइनेंशियल एक्सेस–मेजरमेंट एण्ड डीटरमीनेन्ट्स : ए केस स्टडी आफ अनआर्गनाइज्ड मेन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजिज इन इण्डिया'' नामक लेख एनआईपीएफपी कार्य पत्र श्रृंखला (143) 2015 में प्रकाशित हुआ । उनका लेख ''यूनियन बजट 2015–16 : ग्रोथ–ओरिएन्टिड बजट'' खण्ड 59, मार्च, 2015'' योजना में प्रकाशित, पृ. 10–12 (एच.के. अमरनाथ के साथ) ।

कार्य पत्र श्रृंखला और पत्रिका प्रकाशनों के अलावा डा. भानुमूर्ति ने विभिन्न मेगजीनों और दैनिक समाचार–पत्रों के लिए 16 लघु प्रार्थित लेख लिखे, नामतः ''इकोनामिक टाइम्स'', ''मिन्ट'', ''फाइनेंशियल क्रोनिकल'', ''दि टेलीग्राफ'', ''राजस्थान पत्रिका'', ''इकोनामी मैटर्स'' (सीआईआई) और ''हायर एज्युकेशन'' (टाइम्स आफ इण्डिया मेगजीन) ।

डा. पिनाकी चक्रवर्ती, प्रोफेसर ने, 8 मई 2013 से 31 दिसंबर 2014 तक आर्थिक सलाहकार के रूप में चौदहवें वित्त आयोग में अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी करने के बाद, 1 जनवरी 2015 से एनआईपीएफपी में अपने शैक्षिक कार्य पुनः जारी किए ।

आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान, डा. पिनाकी चक्रवर्ती ने एक चल रही परियोजना ''व्हाट इज दि क्वालिटी आफ गवर्नेन्स अक्रास इण्डियन स्टेट्स एण्ड डज इट मैटर'' पर अपने अनुसंधान सहयोगियों के साथ कार्य किया, यथा स्टानली एल. विनेर और जे. स्टीफन फेरिस, कार्लेटन यूनिवर्सिटी और भारती भूषण दास, एनआईपीएफपी ।

डा. चक्रवर्ती ने, ''डेट मेनेजमेंट'' पर एक व्याख्यान दिया, 26 मार्च 2015, इंस्टीट्यूट आफ गवर्नमेन्ट्स एकाउन्ट्स एण्ड फाइनेंस, नई दिल्ली । उन्होंने ''पब्लिक पॉलिसी एण्ड इकोनामिक डेवलपमेंट्स'' पर ''नेशनल कन्फरेन्स आन पब्लिक फाइनेंस'' पर एक प्रमुख अभिभाषण दिया, 26–27 मार्च 2015, अर्थशास्त्र विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तमिलनाडु, तिरूवारूर । उन्होंने उसी स्थल पर ''यूनियन बजट 2015–16'' पर भी एक

व्याख्यान दिया। इनके अलावा, उन्होंने एनआईपीएफपी में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनेक व्याख्यानदिए।

डा. चक्रवर्ती के प्रकाशनों में सम्मिलित हैं : ''स्टेट लेवल रिफोर्म्स, ग्रोथ एण्ड डेवलपमेंट इन इंडियन स्टेट्स (2014)'' नामक एक पुस्तक, अरविन्द पनगढिया और एम. गोविन्द राव के साथ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, न्यूयार्क। उन्होंने, ''इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली के ''बजट 2015–16' पर एक विशेष अंक में ''फाइनेंस कमीशन्स रिकमेंडेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्टेड फिस्कल स्पेस'' नामक एक लेख प्रकाशित किया।

डा. चक्रवर्ती को, ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा वित्तपोषित ''स्टेट लेवल एक्सपोर्ट्स एण्ड इकोनामिक ग्रोथ'' के संबंध में सलाहकार समिति के एक बाह्य सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने इस अवधि के दौरान ''इग्नू'', नई दिल्ली, ज.ने.वि., नई दिल्ली, एनआईटी, सिल्वर (असम) और कलकत्ता विश्वविद्यालय को प्रस्तुत एम. फिल और पी.एचडी. शोध निबंधों का मूल्यांकन कार्य किया।

डॉ. अंजन मुखर्जी, आनरेरी विजिटिंग प्रोफेसर ने आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान चार पत्र प्रस्तुत किए, दो सम्मेलन आयोजित किए, और एक पुस्तक के लिए एक चैप्टर लिखा। उन्होंने ''टू एग्जाम्पिल्स फ्राम क्लासीकल जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी एण्ड देअर इम्प्लीकेशन्स'', पत्र ''**इंटरनेशनल कन्फरेंस आन पर्सपेक्टिव आन इकोनामिक थ्योरी** एण्ड एप्लीकेशन्स (प्रोफेसर अमितव बोस के सम्मान में), भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता में अगस्त 2014 में प्रस्तुत किए। उन्होंने **''वर्कशाप इन जनरल इक्वीलिब्रियम थ्योरी एण्ड इट्स एप्लीकेशन्स''** पर तथा '' आन दि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरियम आफ वेलफेयर इकोनामिक्स'' पर सेंटर फार एडवांस्ड स्टडीज इन इकोनामिक्स, यादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता में फरवरी 2015 में ''आन दि सेकण्ड फंडामेंटल थ्योरियम आफ पॉजिटिव इकोनामिक्स'' पर वार्ता दी। शिव नाडार यूनिवर्सिटी, अर्थशास्त्र विभाग, में 13 अगस्त 2014 को उन्होंने ''प्रोपर्टीज आफ कम्पीटिटिव इक्लीब्रिआ'' पर एक भाषण दिया।

डा. मुखर्जी ने, **''बिहार ग्रोथ कन्फरेंस''** भी अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र, पटना में आयोजित की, 19–20 जुलाई 2014। उन्होंने **''बिहार सेशन आफ दि ग्रोथ वीक''** भी आयोजित किया। लंदन अर्थशास्त्र स्कूल में और साथ ही **''इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर्स एनुअल कन्फरेंस'',** लंदन में बिहार मुख्यमंत्री का विशेष व्याख्यान, 23–25 सितंबर 2014।

आलोच्य वर्ष के दौरान, मुखर्जी के प्रकाशित कार्यों में सम्मिलित हैं : ''व्हेन इज कम्पीटिटिव बिहेवियर ए बेस्ट रेस्पोन्स ?'' एस. मार्जित और एम. राजीव (सं.) के ''एमर्जिंग इश्यूज इन इकोनामिक डेवलपमेंट : ए कन्टेम्पोरेरी थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिव'', में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, 2014, दिल्ली।

डा. मुखर्जी, कन्ट्री डायरेक्टर के पद पर बने रहे, इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर्स इण्डिया–बिहार प्रोग्राम, पटना और पूर्व – प्रोफेसर, ज.ने.वि. बने हुए हैं।

डा. प्रताप रंजन जेना, एसोसिएट प्रोफेसर, ने ''दि रिव्यु आफ कम्प्लाएन्स आफ दि गवर्नमेंट आफ ओडिशा टू दि एफआरबीएम एक्ट–2012–13'' नामक परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की, डा. तपस सेन द्वारा सह–लिखित तथा ओडिशा सरकार द्वारा आलोच्य वर्ष 2014–15 में प्रायोजित। उन्होंने, मनीश गुप्ता और श्रुति त्रिपाठी के साथ **''ट्रेनिंग एण्ड असिस्टेन्टस प्रोग्राम फार दि कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल (सीएजी) आफ इण्डिया आन पब्लिक डेट मेनेजमेंट एण्ड एफआरबीएम**

एक्ट एण्ड इट्स इम्प्लीमेंन्टेशन'', भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा प्रायोजित ।

डा. जेना ने, चल रही परियोजना **''मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी फार गोआ फार 2015–16''** पर कार्य जारी रखा (सतादु सिकदर के साथ), गोआ सरकार द्वारा प्रायोजित । उन्होंने **''दि रिव्यु आफ कम्प्लाएंस आफ दि गवर्नमेंट आफ सिक्किम टू दि एफआरबीएम एक्ट–2012–13''** (सतादु सिकदर के साथ) जारी रखा, सिक्किम सरकार द्वारा प्रायोजित । उनकी चल रही अन्य परियोजना थी : **''मीडियम टर्म फिस्कल प्लान अण्डर एफआरबीएम एक्ट आफ सिक्किम–2015–16''**, सिक्किम सरकार द्वारा प्रायोजित ।

अनुसंधान परियोजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए डा. जेना ने वर्ष 2014–15 में सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया । उन्होंने ''पीएफएम रिफोर्म्स टू सस्टेन फिस्कल रूल्स : ए सब–नेशनल पर्सपेक्टिव फ्राम इण्डिया'' पर एक प्रस्तुतिकरण किया, ''इंटरनेशनल कन्सोर्टियम आन गवर्नमेंटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट'' (आईसीजीएफएम), विंटर कन्फरेंस आन पीएफएम फाउंडेशन फार पब्लिक गवर्नैन्स'' में वाशिंगटन, 1–3 दिसंबर 2014 ।

डा. जेना ने, ''फिस्कल प्रोफाइल आफ ओडिशा'' पर अनेक आमंत्रित व्याख्यान दिए, **''ट्रेनिंग प्रोग्राम आन पब्लिक फाइनेंस एण्ड बजट फार ओडिशा गवर्नमेंट''**, जिंदल स्कूल आफ गवर्नमेंट एण्ड पब्लिक पॉलिसी (जेएसजीपी), ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, 30 जून, 2015, ''पब्लिक एक्सपेंडीचर एण्ड फाइनेंशियल एकाउनटेबिलिटी'' और ''पब्लिक फाइनेंशियल मेनेजमेंट करेंट इश्यूज'' पर, 23 फरवरी, 2015 को, ''पीएफएम परफोर्मेन्स मेजरमेंट फ्रेमवर्क'' और ''पब्लिक फाइनेंशियल मेनेजमेंट सिस्टम्स'' पर, 25 मार्च 2015, **''आईटीईसी ट्रेनिंग प्रोग्राम आन पब्लिक एक्सपेंडीचर मेनेजमेंट एण्ड गवर्नमेंट एकाउंटिंग''** में, इंस्टीट्यूट आफ गवर्नमेंट एकाउन्ट्स एण्ड फाइनेंस, नई दिल्ली ।

डा. जेना ने एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण भी दिया । उनके व्याख्यानों में सम्मिलित थे : ''सार्वजनिक व्यय प्रबंधन'' और ''सार्वजनिक व्यय तथा वित्तीय जवाबदेही : पीएफएम परफोमेन्स मेजरमेंट फ्रेमवर्क'', **''पब्लिक फाइनेंस फार इण्डियन इकोनामिक सर्विस प्रोबेशनर्स''**, 14 मई 2014 और **''कोर्स आन ''फिस्कल एण्ड मोनेटरी पॉलिसी'', भारतीय सांख्यिकीय सेवा परिवीक्षार्थियों के लिए''**, 17 जून 2014, ''राजकोषीय प्रबंधन सिद्धांत और एफआरबीएम अधिनियम : इवेल्युएशन केस स्टडीज फ्राम स्टेट्स'', **''ट्रेनिंग प्रोग्राम इन ''एफआरबीएम एक्ट फार दि आफिसर्स आफ दि कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल'',** 10–12 सितंबर, 2014, ''फडामेंटल्स आफ बजटिंग सिस्टम इन इण्डिया'', **''ट्रेनिंग प्रोग्राम फार स्टूडेन्ट्स आफ कालेज आफ आर्ट्स एण्ड साइंस, गोआ, 18 नवंबर 2014, ''पब्लिक एक्सपेंडीचर मेनेजमेंट''** और ''डेवलपमेंट एण्ड एक्सपीरिएन्स आफ फिस्कल रूल्स इन इण्डिया'', **''कोर्स इन पब्लिक फाइनेंस'', फार इंडियन आडिट एण्ड एकाउंन्ट्स सर्विस प्रोबेशनर्स**, 2–4 फरवरी 2015 ; ''इश्यूज इन पब्लिक एक्सपेंडीचर मेनेजमेंट'', **''कोर्स आन मोनेटरी एण्ड फिस्कल पॉलिसी'' फार आफीसर ट्रेनीज आफ इण्डियन स्टेटिस्टिकल सर्विस'',** 24 मार्च, 2015 ।

डा. जेना के प्रकाशन कार्यों में लेख सम्मिलित थे, ''ए कन्वेंशनल बजट होल्ड्स होप्स फार दि फ्युवर :

मेक्रो–इकोनामिक व्यु'', ''दि चार्टर्ड एकाउंटेट जरनल'', खण्ड 3, अंक 2, अगस्त 2014 और एक आगामी लेख'', रिफोर्म इनीशिएटिव्ज इन दि बजटिंग सिस्टम इन इण्डिया'' – पब्लिक बजटिंग एण्ड फाइनेंस, विले ब्लैकवैल।

डा. जेना ''पावर्टी टास्क फोर्स'', उड़ीसा सरकार के एक सदस्य बन गए। कार्य बल निर्धनता कटौति कार्यनीति तैयार करेगा और राज्य में कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगा। वर्ष 2014–15 में डा. जेना दो पत्रिका लेखों के लिए बाह्य समीक्षाकर्त्ता बन गए – ''पब्लिक एकाउंटेबिलिटी एण्ड दि ''पेफा : एन असेसमेंट'', ''इंटरनेशनल रीव्यु आफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसिज'', इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसिज'', सेज पब्लिकेशन्स; और ''हेज दि मीडियम टर्म एक्सपेंडीचर फ्रेमवर्क (एमटीईएफ) बीन इफेक्टिव इन नेपाल ?'' पब्लिक बजटिंग एण्ड फाइनेंस, विले ब्लैकवेल।

डा. लेखा चक्रवर्ती, एसोसिएट प्रोफेसर, ने आलोच्य वर्ष 2014–15 में, ''इफेक्टिव स्टेट्स एण्ड इनक्लुजिव डेवलपमेंट सेंटर (ईएसआईडी) के प्रभावी राज्यों और ईस्ट अंगलिया यूनिवर्सिटी, यू.के. के सहयोग से ''फिस्कल रीसर्च आन माइनिंग इन न्युली–क्रिएटिव स्टेट्स आफ इण्डिया'' परियोजना पर अपना कार्य जारी रखा। उनकी अन्य चल रही परियोजनाएं हैं : **''मेक्रोइकोनामिक पॉलिसी फार माइनिंग सेक्टर इन इण्डिया एण्ड एक आईएमएफ (वाशिंगटन डी.सी.), 25 कन्ट्री स्टडी आन जेण्डर बजटिंग इन एशिया–पैसिफिक पर परियोजना।**

डा. चक्रवर्ती, ''इकोनामिक पॉलिसी फार दि ट्वेन्टी फर्स्ट सेंचुरी'' के लिए एक अनुसंधान संकाय के रूप में जुड़ी हैं। वह, इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट, जर्मनी की एक सदस्य बनी रही।

डा. चक्रवर्ती ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भिन्न–भिन्न हैसियत से अपना योगदान किया। उन्हें **''इनक्लुजिव ग्रोथ–शेपिंग ए न्यु ग्लोबल रीसर्च प्रोजेक्ट''** पर एक बैठक में ''ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क (जीडीएन) द्व ारा एक विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया, विदेश कार्य और अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्रालय, पैरिस, 12–13 मई 2014। उन्हें, **यूएनडीपी एशिया–पेसिफिक रीजनल टेक्नीकल वर्कशाप आन क्लाइमेंट रेस्पोन्सिव बजटिंग,** बैंगकाक में एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया 5–7 नवंबर 2014। उन्हें, आईएमएफ द्वारा जीआरबी पर एक ग्लोबल प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए आमंत्रित किया गया, मार्च 2015, वाशिंगटन डी सी। उन्हें ''फिस्कल डी–सेंट्रलाइजेशन एण्ड जीआरबी'' पर एक वार्ता देने के लिए आमंत्रित किया गया, मार्च 2015, वाशिंगटन डीसी, इंटर–अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक (आईडीबी) द्वारा एक आमंत्रण पर । वह, एशिया, प्रशांत, बाली, इंडोनेशिया, 2014 की यूएन ''एस्केप'' बैठकों में जीआरबी पर एक विशेषज्ञ थी ''माइनिंग, टेक्सेशन एण्ड प्रोफिटेबिलिटी लिंक्स आफ इण्डियन फर्म्स : एवीडेंस फ्राम डायनेमिक पैनल डेटा'' (साहिल खगोत्र के साथ) को **''सेवेन्टी फर्स्ट एनुअल कांग्रेस आफ दि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस (आईआईपीएफ), डबलिन** में प्रस्तुतिकरण के लिए चुना गया, 2015।

डा. चक्रवर्ती ने ''इम्पेक्ट आफ डेफिसिट्स'' पर एक व्याख्यान दिया, फेज–3, **ट्रेनिंग प्रोग्राम फार आईएएस, आफिसर्स,** एलबीएसएनएए, मसूरी 8 अक्तूबर, 2014। वह, प्रोग्राम आन **''गवर्नेन्स ट्रांसपेरेंसी एण्ड एकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक फाइनेंस मेनेजमेंट फार मिडिल टू सीनियर लेवल**

आफिसर्स आफ इण्डियन स्टेटिस्टिकल सर्विस एण्ड सीनियर आफिसर्स आफ स्टेट्स/यूटी, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे, 17 नवंबर, 2014। उन्होंने, ''रिफोर्म्स इन नान–टैक्स रेवेन्यु : केस स्टडी आन माइनिंग'' पर एक कार्यशाला का नेतृत्व किया, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे, 17–22 नवंबर, 2014। उन्होंने, सीडब्ल्यूडीएस और यूएनएफपीए, आईआईसी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ''एनडेनजरिंग स्टेटिस्टिक्स'' पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया, 9 दिसंबर, 2014। उन्होंने ''स्टडी रीलीज बाई आईएनजी एण्ड दि नीदरलेण्ड्स प्लेटफार्म फार माइक्रो फाइनेंस'' के अवसर पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया, एम्बेसेडर्स रेजीडेंस, 10 औरंगजेब रोड, नई दिल्ली, 3 सितंबर 2014।

डा. चक्रवर्ती ने वर्ष 2014–15 के दौरान, संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनेक व्याख्यान दिए। उन्होंने दो व्याख्यान दिए–''थ्योरीज आफ पब्लिक एक्सपेंडीचर'' और ''इम्पेक्ट आफ फिस्कल डेफिसिट'', **भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारी प्रशिक्षार्थियों के लिए ''मोनेटरी एण्ड फिस्कल पॉलिसी''** पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 23–27 मार्च 2015। उन्होंने तीन व्याख्यान दिए : फिस्कल पॉलिसी एण्ड ह्युमन डेवलपमेंट : जेण्डर बजटिंग'', ''थ्योरीज आफ पब्लिक एक्सपेंडीचर'' और ''मेक्रोइकोनामिक इम्पेक्ट आफ डेफिसिट'', ''पब्लिक फाइनेंस'' में पाठ्यक्रम–भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षार्थियों के लिए, पाठ्यक्रम, 2–13 फरवरी, 2015। उन्होंने दो व्याख्यान दिए – ''मेक्रो इम्पेक्ट्स आफ डेफिसिट्स'' और ''फिस्कल पॉलिसी एण्ड मेक्रोइकोनामिक मेनेजमेंट'', **अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और आईएफएस) अधिकारियों के लिए ''फिस्कल पॉलिसी एण्ड मेक्रोइकोनामिक मेनेजमेंट'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम,** में 16–20 जून, 2014। उन्होंने तीन व्याख्यान दिए : ''मेक्रोइकोनामिक इम्पेक्ट आफ डेफिसिस्ट्स'', ''थ्योरी आफ पब्लिक एक्सपेंडीचर'' और ''जेण्डर बजटिंग'', **''भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षार्थियों के लिए ''पब्लिक फाइनेंस में पाठ्यक्रम''** 3–14 फरवरी, 2014।

डा. चक्रवर्ती ने ''टूवर्ड्स ए न्यु मेक्रोइकोनामिक कन्सेन्सस'' पर एक अतिथि व्याख्यान, महाराजा महिला कालेज, तिरूवनन्तपुरम में दिया, जनवरी 2014। उन्होंने ''फिस्कल पॉलिसी एण्ड ह्युमन डेवलपमेंट'' पर एक सम्मेलन में, रोहतक विश्वविद्यालय, हरियाणा में अध्यक्षीय भाषण दिया। उन्होंने ''इम्पेक्ट आफ डेफिसिट्स'' पर एक व्याख्यान दिया, अफगानिस्तान सरकार, वित्त मंत्रालय अधिकारियों के लिए, एमडीआई, गुड़गांव, 20 मई 2014। उन्होंने ''एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए इंटर–गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स'' पर एक व्याख्यान दिया, एनईयूपीए, नई दिल्ली, मई 2014। एक आमंत्रित वक्ता के रूप में उन्होंने दो व्याख्यान दिए : ''फिस्कल डेफिसिट्स एण्ड मोनेटरी पब्लिक लिंक्स एण्ड जीआरबी'', भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) की सार्वजनिक वित्त और नीति पर'' एमडीपी के अधिकारियों के लिए, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद में, 8 जुलाई, 2014।

आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान डा. चक्रवर्ती के प्रकाशित कार्यों की सूची में दो एनआईपीएफपी ''वन पेजर'' सम्मिलित थे – ''नान–टेक्स रेवेन्यु : एनेलाइजिंग दि इम्पेक्ट आफ माइनिंग रायल्टी आन कम्पीटीटिवनैस एण्ड इंटेग्रेटिंग टाइम यूज इन पब्लिक पॉलिसी''। ''मेक्रोइकोनामिक पॉलिसी फार फेरस सेक्टर : एनेलाइजिंग माइनिंग टेक्सेशन

रेजीम'' पर उनका पत्र एमएमडीआर, 2014 के लिए ''नीति अनुसंधान इनपुट के रूप में प्रकाशित किया गया, टाटा स्टील लि. (दिसंबर)। उन्होंने ''मेक्रोइकोनामिक वोलेटिलिटी एण्ड रीजनल फिस्कल एण्ड मोनेटरी पॉलिसीज इन लातिन अमरीका, केरिबियन, एशिया एण्ड पेसिफिक'' पर कार्य किया जिसे ''ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क (जीडीएन) में एक संश्लेषण ड्राफ्ट पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया।

डा. चक्रवर्ती ने, लेखों के साथ पत्रिकाओं के लिए भी अपना योगदान दिया, जैसे कि ''मेक्रोइकोनामिक्स आफ यूनियन बजट 2014'', ''योजना'', भारत सरकार में प्रकाशित हुआ। ''इकोनामिक पॉलिसी रिवाइवल फार माइनिंग'' पर उनका लेख (साहिल रवगोत्रा के साथ) ''सोशल साइंसिज द्व ारा प्रकाशित किया गया, फरवरी 2015। ''मेक्रोइकोनामिक पॉलिसी रिवाइवल इन माइनिंग एण्ड एनवायरनमेंट फेडरलिज्म : ग्लिम्पसिज फ्राम मोदी बजट, 2015–16'' पर उनका लेख (साहिल रवगोत्रा के साथ) ''योजना'' भारत सरकार में प्रकाशित किया गया।

डा. चक्रवर्ती ने तीन एनआईपीएफपी कार्य पत्र और तीन लैवी अर्थशास्त्र संस्थान कार्य पत्र प्रकाशित किए–''पब्लिक पॉलिसी आन नान–टेक्स रेवेन्यु : एनेलाइजिंग दि इम्पेक्ट आफ माइनिंग रायल्टी आन कम्पीटिटिवनेस'', का.प. सं. 129, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली, ''इंटेग्रेटिंग टाइम यूज इन पब्लिक पॉलिसी'', का. प. सं. 127, एनआईपीएफपी (लैवी अर्थशास्त्र संस्थान में भी का.प. सं. 785 के रूप में), नई दिल्ली और ''जेण डर बजटिंग एज फिस्कल इन्नोवेशन : एवीडेंस फ्राम इण्डिया'', कार्य पत्र, एनआईपीएफपी (लैवी अर्थशास्त्र संस्थान, न्यूयार्क में भी का.प. सं. 797)। उन्होंने, वीणा नैय्यर के सहयोग से ''फाइनेंशियल इनक्लुजन'' पर एक लेख लिखा, फाइनेंशियल एक्सप्रैस, अगस्त 2014।

डा. चक्रवर्ती ने, फोर्ढम विश्वविद्यालय, न्यूयार्क के ऋषिकेश विनोद के साथ ''इफ डेफिसिट्स आर नाट दि कल्प्रिट, व्हाट डीटरमाइन्स इण्डियन इंटरेस्ट रेट्स ? नामक एक पत्र के संबंध में सहयोग किया। ''मेग्जीमम एनट्रापी बूट्सट्रेप मेथ्ड'' का उपयोग करते हुए एक मूल्यांकन तथा बाद में इसे लैवी अर्थशास्त्र संस्थान कार्य पत्र (का. प. 811) के रूप में प्रकाशित किया गया, जुलाई 2014। यह पत्र उनके सह–लेखक हनी करूण द्वारा, आईजीआईडीआर, मुंबई में आयोजित इकोनामिट्रिक कन्फरेंस की 51वीं वार्षिक कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया।

डा. चक्रवर्ती, ''मेक्रोइकोनामिक वोलेटलिटी आफ कैरिबियन एण्ड पेसिफिक कन्ट्रीज प्रोजेक्ट'' पर ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क (जीडीएन) के लिए प्रोजेक्ट परामर्शदाता थी, विदेश कार्य मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय विकास, पैरिस। उन्होंने **''वन वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम फार फिस्कल पॉलिसी एण्ड मेक्रोइकोनामिक मेनेजमेंट फार आईएएस आफिसर्स''** में एक प्रोग्राम समन्वयकर्ता की जिम्मेदारी संभाली, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली, 16–20 जून 2014। उन्होंने ''जेण्डर रेस्पोन्सिव बजटिंग'' पर आधे दिन की बैठक का समन्वय किया जिसे डब्ल्युपीसी, नई दिल्ली और अफगानिस्तान आधारित ''इक्वलिटी आफ पीस एण्ड डेवलपमेंट (ईपीडी) के समन्वय से, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और चुनिंदा क्षेत्रकीय मंत्रालयों, अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों के साथ एनआईपीएफपी, 28 अक्तूबर 2014 को आयोजित किया गया था। उन्होंने एनआईपीएफपी के नए प्रकाशन–मई 2014 में प्रकाशित 'वन पेजर' के संबंध में कार्यक्रम प्रबंधक की हैसियत धारण की।

डा. चक्रवर्ती ने ''इन्फ्लेशन टार्गेटिंग'' नामक एक पी.एचडी. शोध निबंध का मूल्यांकन भी किया, यूनिवर्सिटी

आफ विटवाइटर्सरेण्ड, जोहांसबर्ग। उन्होंने ''सर्वे आफ जीआरबी इन दि रीजन'' में योगदान किया जो एक प्रायोजित परियोजना है, आईएमएफ, वाशिंगटन डी सी। उन्होंने, ''एप्लाइड इकोनामिक्स'' के लिए पत्रों की समीक्षा की (पहले एप्लाइड फाइनेंशियल इकोनामिक्स के रूप में ज्ञात) ; सिंगापुर इकोनामिक रीव्यु : जरनल आफ इकोनामिक एण्ड फाइनेंशियल सर्विसिज (जेईएफ) ; जरनल आफ पापुलेशन इकोनामिक्स। वह, एम. फिल, शोध निबंध, सीईएसपी, ज.ने.वि., नई दिल्ली की एक बाह्य परीक्षक थी।

डा. मीता चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर ने आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान, **''हैव न्युली क्रिएटिड इण्डियन स्टेट्स प्रोमोटिड इन्क्लुजिव डेवलपमेंट ? ए कम्पेरीजन आफ झारखण्ड एण्ड छत्तीसगढ़''** नामक परियोजना पर कार्य शुरू किया।

डा. मीता ने ''अण्डरस्टेंडिंग ह्युमन डेवलपमेंट : कनसेप्ट्स, मेजरमेन्ट्स एण्ड प्रोक्योरमेंट आफ सर्विसिज'' पर एक राष्ट्र स्तर कार्यशाला में ''फाइनेसिंग ह्युमन डेवलपमेंट'' पर एक व्याख्यान भी दिया, जिसका आयोजन महाराष्ट्र सरकार और यूएनडीपी द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 25 अगस्त को ''यशदा'', पुणे में किया गया था। उन्होंने ''गवर्नमेंट हैल्थ स्पेंडिंग इन इण्डिया'' पर ''बुलेटिन आफ वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन'' (डब्ल्युएचओ) के लिए एक पत्र की समीक्षा की, अगस्त 2014।

आलोच्य वर्ष के दौरान, उन्हें, ''नेशनल हैल्थ एकाउन्ट्स'' पर विशेषज्ञ समूह समिति का एक सदस्य, और ''नेशनल हैल्थ प्रोफाइल'' पर विशेषज्ञ समूह का एक सदस्य नियुक्त किया गया। इन दोनों का गठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था।

डा. सच्चिदानन्द मुखर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर ने वर्ष 2014–15 में एक टीम सदस्य के रूप में ''डेवलपमेंट आफ एन एनेलिटिकल मॉडल फार वाइडनिंग आफ दि टेक्सपेयर्स बेस'' पर परियोजना पूरी की। उन्होंने, ''स्टडी आफ बिहार स्टेट फाइनेंसिज–पॉलिसीा आप्शन्स फार टेक्स राशनलाइजेशन एण्ड मोबिलाइजेशन आफ रेवेन्यु'' नामक परियोजना पर कार्य करना जारी रखा।

डा. मुखर्जी ने, एनआईपीएफपी तथा देश भर में अन्य शैक्षिक संस्थानों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लिया। उन्होंने, भारतीय सांख्यिकीय सेवा परिवीक्षार्थियों के लिए ''टेक्सेशन आफ गुड्स एण्ड सर्विसिज'' पर एक व्याख्यान 26 मार्च 2015 को, ''थ्योरी एण्ड प्रिंसिपल्स आफ टेक्सेशन'' पर और भारतीय लेखा–परीक्षा और लेखा–सेवा (आईएएण्डएएस) परिवीक्षार्थियों के लिए ''इवोल्युशन आफ स्टेट टेक्सिज'' पर 9 और 10 फरवरी, 2015 को, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) परिवीक्षार्थियों के लिए ''पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली क्षेत्र के संदर्भ में जीएसटी'' पर 14 मई 2014 को और भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) परिवीक्षार्थियों के लिए ''एनेलाइजिंग दि इम्पेक्ट आफ टेक्सिज थ्रू इनपुट–आउटपुट मॉडल्स'' पर 18 जून 2014 को, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली में एक व्याख्यान दिया।

डा. मुखर्जी ने, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के मध्य से वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को ''टेक्सेशन एण्ड चेलेजिंज इन रेवेन्यु पॉलिसी'' और ''जीएसटी इन दि कन्टेक्स्ट आफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एण्ड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर'' ''रीफ्रेशर प्रोग्राम आन फाइनेशियल मेनेजमेंट'', 17–21 नवंबर 2014, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे में पढ़ाया। उन्होंने ''टेरी'' विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के एमएससी

(अर्थशास्त्र) छात्रों को ''मेथेडोलोजी टू स्टडी नानपाइंट सोर्स ग्राउंटवाटर पाल्युशन इन इण्डिया'' पढ़ाया, नई दिल्ली, 1 सितंबर 2014 । उन्होंने, वित्त मंत्रालय, अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों को ''स्ट्रक्चर आफ इनडायरेक्ट टेक्सिज इन इण्डिया'' पर एक व्याख्यान दिया, प्रबंध विकास संस्थान, गुड़गांव, 21 मई 2014 ।

डा. मुखर्जी ने, ''यूजीसी–प्रायोजित ''ग्लोबलाइजेशन एण्ड इकोनामिक डेवलपमेंट : इश्यूज रिलेटिड टू इण्डियन इकोनामी'' पर राष्ट्रीय सेमिनार में ''एनवायरनमेंटल चेलेंजिज इन टाइम्स आफ ग्लोबलाइजेशन – ए मेक्रो–पर्सपेक्टिव'' पर व्याख्यान दिया, जिसका आयोजन अर्थशास्त्र विभाग, लालबाबा कालेज और अर्थशास्त्र विभाग, कल्याणी विश्वविद्यालय, प. बंगाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, 21–22 नवंबर 2014 । उन्होंने ''इण्डिया–आस्ट्रेलिया जी–20 राउण्डटेबल में भाग लिया, जिसका आयोजन, एनआईपीएफपी, ब्रुकिंग्स इण्डिया और आस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था तथा ''क्रेडिट एनहांसमेंट एण्ड गारंटी अरेंजमेंट फार इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट'' पर व्याख्यान दिया (प्रोफेसर रामप्रसाद सेनगुप्ता के साथ), नई दिल्ली, 10 सितंबर, 2014 ।

डा. मुखर्जी ने पत्र प्रस्तुत किए – ''डिमांड फार इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट फार वाटर सर्विसिज : की फीचर्स एण्ड असेसमेंट मेथ्ड्स'', ''मेनेजिंग दि ग्लोबलाइजेशन आफ सेनिटेशन वाटर सर्विसिज : ''ब्ल्यु गोल्ड'', रेगुलेटेरी चेलेंजिज'', 23–24 मार्च 2015, ''दि चाइनीज यूनिवर्सिटी आफ हांग कांग, हांग कांग एसएआर, ''डज फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लुएंस पर केपिता सीओर एमीशन ए क्रास कन्ट्री एम्पीरिकल एनेलिसिस'', ''फिस्कल पॉलिसीज एण्ड दि ग्रीन इकोनामी ट्रांजीशन : जेनेरेटिंग नोलिज–क्रिएटिंग इम्पेक्ट'' पर **''थर्ड एनुअल कन्फरेंस आफ दि ग्रीन ग्रोथ नोलिज प्लेटफार्म (जीजीकेपी)** में, 29–30 जनवरी 2015, का फोसकारी यूनिवर्सिटी आफ वेनिस, वेनिस, इटली (सह–लेखक ने पत्र प्रस्तुत किया)'' । ''हाऊ सीओ 2 एमीशन्स आर इन्फ्लुएन्स्ड बाई स्केल, कम्पोजीशन एण्ड टेकनीक इफेक्ट्स ? एम्पीरिकल एविडेसिंज फ्राम पैनल डेटा एनेलिसिस'', ''फोर्थ रीसर्च कन्फरेंस आन एम्पीरिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड एण्ड फाइनेंस'', में, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली, 18–19 दिसंबर 2014 । डा. मुखर्जी ने, आर. कविता राव के साथ ''फेक्टर्स इनफ्लुएन्सिंग अनइनकारपोरेटिड एन्टरप्राइजिज टू रजिस्टर विद स्टेट टेक्स अथोरिटी :' एन एनेलिसिस विद एनटरप्राइसिज सर्वे डेटा'', प्रस्तुत किया, **''कन्फरेंस आन पेपर्स इन पब्लिक इकोनामिक्स एण्ड पॉलिसी''** पर , 12–13 मार्च 2015, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली ।

डा. मुखर्जी के आलोच्य वर्ष के दौरान, प्रकाशनों में सम्मिलित थे : एक सह–सम्पादित पुस्तक, 5 पत्रिका लेख, संपादित पुस्तकों में 2 चेप्टर और 4 कार्य पत्र । ''एनवायरनमेंटल चेलेंजिज एण्ड गवर्नेन्स : डायवर्स पर्सपेक्टिव्ज फ्राम एशिया'', 9 मार्च 2015, राउतलेज, यू.के., उनके द्वारा सह–संपादित । पुस्तक में, संपादकों द्वारा लिखित ''वाकिंग ए थिन लाइन बिटविन ग्रोथ एण्ड डेवलपमेंट कन्सर्स ? एनवायरनमेंटल गवर्नेन्स इन इण्डिया'' पर एक चेप्टर सम्मिलित था ।

डा. मुखर्जी ने ''प्रजनन'' पत्रिका की समीक्षा जारी रखी – ''सामाजिक और प्रबंधन विज्ञान की पत्रिका (राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे), ''इकोनामिक्स बुलेटिन, फारेन ट्रेड रीव्यु (सेज जरनल) और ''रीव्यु आफ डेवलपमेंट एण्ड चेंज'' (मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, चेन्नई) । वह ''पब्लिक फाइनेंस एण्ड फिस्कल पॉलिसी'' पर एक संपादित पुस्तक के ''बुक प्रोपोजल

रीव्युअर'' भी थे, केम्ब्रज यूनिवर्सिटी प्रैस, नई दिल्ली, 2014।

डा. मुखर्जी को, सलाहकार समूह–डीएसटी नीति अनुसंधान केंद्र, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर (सेंट्रल) विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ.प्र. के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

डा. सी. भुजंग राव, सहायक प्रोफेसर ने आलोच्य वर्ष 2014–15 में अनेक कार्यशालाओं, सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लिया। उन्होंने, ''टैक्स पॉलिसी एण्ड एन्टरप्राइज डेवलपमेंट इन साउथ एशिया'' पर ''पॉलिसी एनगेजमेंट कार्यशाला में भाग लिया, एनआईपीएफपी, 15 अक्तूबर 2014। उन्होंने, ''स्ट्रक्चरल रिफोर्म एण्ड ग्रोथ इन इण्डिया'' पर ''दिल्ली इकोनामिक्स कानक्लेव'' में भाग लिया जिसका आयोजन वित्त मंत्रालय द्वारा 10–11 दिसंबर 2014 को ''दि ग्राण्ड होटल, वसंत कुंज, नई दिल्ली में किया गया था। उन्होंने, ''विन्टर स्कूल 2014'' में भाग लिया जिसका आयोजन अर्थशास्त्र विभाग और विकास अर्थशास्त्र केंद्र द्वारा दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल में 15–17 दिसंबर 2014 को किया गया था। वह, ''न्यु अप्रोचिज टू इकोनामिक चेलेंजिज (एनएईसी)'' पर एक कार्यशाला के भी एक भाग थे, जिसका आयोजन ओईसीडी और एनआईपीएफपी द्वारा 24 फरवरी 2015 को किया गया था।

डा. राव ने, ''दि यूनियन बजट 2015–16 : रिफोर्म एण्ड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्ज'' में भाग लिया जिसका आयोजन एनआईपीएफपी व अन्य संगठनों द्वारा 9 मार्च 2015 को ताजमहल होटल, नई दिल्ली में किया गया था। वह, ''स्टेट फिस्कल केपेसिटी एण्ड टेक्स अफर्ट : एवीडेंस फार इण्डियन स्टेट्स'' पत्र के लिए चर्चाकार थे, जिसे अजीत कार्निक और स्वाति राजू द्वारा ''पेपर्स इन पब्लिक इकोनामिक्स एण्ड पॉलिसी'' पर दो दिन के सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, 12 मार्च 2015 को एनआईपीएफपी में। उन्होंने, ''पांचवे डा. राजा जे. चेलैय्या स्मारक व्याख्यान में भी भाग लिया था जो डा. सी. रंगाराजन द्वारा 13 मार्च 2015 को इण्डिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में दिया गया था।

डा. राव ने आलोच्य वर्ष के दौरान, एक पत्रिका लेख प्रकाशित किया और एक पुस्तक के लिए दो चेप्टर लिखे।। उनका लेख (सह लेखक : डी.के. श्रीवास्तव) ''डीपेन्डेन्स आफ स्टेट्स आन सेंट्रल ट्रांसफर्स : स्टेटवाइज एनेलिसिस'' ''ग्लोबल बिजनिस रीव्यु में 2014 में प्रकाशित किया गया। ''एनवायरनमेंटल टेक्स रिफोर्म्स इंटरनेशनल एक्सपीरिएन्स'' (सह लिखित) और ''रोल आफ एनवायरनमेंटल स्टडीज इन इण्डिया'' (सह–लिखित) पर उनके चेप्टर, डी.के. श्रीवास्तव और के.एस. कवि कुमार (सं.) ''एनवायरनमेंट एण्ड फिस्कल रिफोर्म्स इन इण्डिया'', नई दिल्ली में प्रकाशित किए गए।

डा. राव ने ''ग्लोबल बिजनिस रीव्यु'' पत्रिका, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली के लिए एक रेफरी के रूप में अपना कार्य जारी रखा।

डा. एच.के. अमरनाथ, असिस्टेंट प्रोफेसर, ने आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान ''अन्डरस्टेंडिंग हाई अनस्पेन्ट बेलेंसिज एण्ड फण्ड फ्लो मेकेनिज्म इन मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स'' परियोजना पूरी की जिसे एन.आर. भानुमूर्ति के नेतृत्व में एक अनुसंधान टीम के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया था। उन्होंने ''स्टडी आन इंटर–गवर्नमेंटल फाइनेंस इन एमर्जिंग मार्केट इकोनामीज'' नामक परियोजना भी पूरी की जिसका वित्त पोषण चौदहवें वित्त आयोग ने किया था, तपस सेन, मनीष गुप्ता, सुधांशु कुमार और भारती भूषण के साथ। यूनिसेफ, भोपाल द्वारा प्रायोजित उनकी **एमडीजी रिपोर्ट फार मध्य प्रदेश**, एन.आर. भानुमूर्ति, सुकन्या बोस, परमा देवी

अधिकारी और अरकाज्योति जाना के साथ, प्रगति पर है।

डा. अमर नाथ ने, सह–लेखक के रूप में एक पुस्तक "अनस्पेन्ट बेलेंसिज एण्ड फण्ड फ्लो मेकेनिज्म अण्डर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस)" प्रकाशित की, एनआईपीएफपी बुक पब्लिकेशन, 2014 में।

डा. मुकेश कुमार आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर ने "इंकम सपोर्ट टू एल्डर्ली इन इंडिया : ए परपोजिव असेसमेंट आफ कवरेज, फंडिंग एण्ड बेनिफिट्स" पर एक पत्र प्रस्तुत किया तथा **"पेपर्स इन पब्लिक इकोनामिक्स एण्ड पॉलिसी" (पीआईपीईपी)** पर सम्मेलन में एक चर्चाकार के रूप में योगदान किया, एनआईपीएफपी में, 12 मार्च 2014।

डा. आनंद ने "डीजल प्राइसिंग इन इण्डिया : एनटेंग्ल्ड इन ए पॉलिसी मेज", "रिफोर्मिंग फोसिल फ्युल प्राइसिज इन इण्डिया : डिलेमा आफ ए डवलपिंग इकोनामी" और "सोशल सिक्युरिटी : रिफोर्म्स फार ए सस्टेनेबिल पेंशन सिस्टम" जैसे विषयों पर एनआईपीएफपी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान भी व्याख्यान दिए।

डा. आनंद को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित "टेक्सेशन प्रेक्टिसिज फार फाइनेंशियल इंस्ट्रुमेन्ट्स इन इण्डिया" पर कार्य दल के लिए एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

डा. मनीष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ने, आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान "फाइनेंसिंग फार इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट" पर "जी–20 प्रोजेक्ट" पूरी की, जिसका वित्त पोषण आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। उन्होंने, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा वित्त पोषित "स्टडी आन इंटरगवर्नमेंटल फाइनेंस इन एमर्जिंग मार्केट इकोनामीज" भी पूरा किया। उनकी चल रही परियोजना में "ट्रेनिंग एण्ड असिस्टेंस प्रोग्राम फार कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल (सीएजी)" सम्मिलित है (नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्व ारा वित्त पोषित)। डा. गुप्ता ने **"पब्लिक डेट मेनेजमेंट अण्डर दि ट्रेनिंग एण्ड असिस्टेंस प्रोग्राम फार दि आफिसर्स आफ दि कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया"** में एक दो दिन का कार्यक्रम भी आयोजित किया, 29–30 सितंबर 2014।

डा. गुप्ता ने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान दिए और सेमिनारों व सम्मेलनों में भाग लिया। उन्होंने, **"ट्रेनिंग प्रोग्राम आन "मोनेटरी एण्ड फिस्कल पॉलिसी फार आफीसर ट्रेनीज आफ इण्डियन स्टेटिस्टिकल सर्विस" में 'सेंट्रल एण्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन्स"** पर एक व्याखान दिया, 20 जून 2014 ; "एफआरबीएमएक्ट : फिस्कल टार्गेट्स एण्ड प्रिंसिपल्स" पर, **"ट्रेनिंग एण्ड असिस्टेन्स प्रोग्राम इन "फिस्कल रेस्पोंसिबिलिटी एण्ड बजट मेनेजमेंट एक्ट" (एफआरबीएम एक्ट)** फार दि आफीसर्स आफ दि कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल आफ इण्डिया" पर 11 सितंबर 2014 ; "**ट्रेनिंग एण्ड असिस्टेंस प्रोग्राम्स इन "पब्लिक डेट मैनेजमेंट" फार दि आफीसर्स आफ दि कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया" में "चेंजिंग कम्पोजीशन आफ पब्लिक डेट : इंटरनल एण्ड एक्टर्नल डेट एण्ड अदर लाएबिलिटीज"** पर 29 सितंबर, 2014।

डा. गुप्ता ने, **"कोर्स आन पब्लिक फाइनेंस" में फार आफीसर ट्रेनीज आफ इण्डियन आडिट एण्ड एकाउन्ट्स सर्विस"** पर "ट्रेण्ड्स इन पब्लिक डेट" और "स्टेट फाइनेंस कमीशन" पर व्याख्यान दिए, 4 फरवरी 2014, "इश्यूज इन लोकल बाडी फाइनेंसिज" एट दि

ट्रेनिंग प्रोग्राम आन "मोनेटरी एण्ड फिस्कल पॉलिसी", भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारी प्रशिक्षार्थियों के लिए, 25 मार्च 2015 और "ट्रेनिंग प्रोग्राम आन पब्लिक फाइनेंस एण्ड बजट्स फार ओडिशा गवर्नमेंट" पर जिंदल स्कूल आफ गवर्नमेंट एण्ड पब्लिक पॉलिसी, ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, 27 जनवरी 2015। उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के अधिकारियों के लिए "पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी" पर एमडीपी में दो व्याख्यान दिए, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद में, 10 जुलाई 2014, (क) एक्सटरनलिटीज, एनवायरनमेंट एण्ड टेक्सिज ; और (ख) लोकल बाडी फाइनेंसिज : यूएलबी और पीआरआई।

डा. गुप्ता ने **"एशिया–पेसिफिक रीजनल टेक्नीकल वर्कशाप** आन क्लाइमेंट रेस्पोसिंव बजटिंग" में भाग लिया जिसका आयोजन यूएनडीपी द्वारा 5–7 नवंबर 2014 को बैंगकाक, थाइलेण्ड में किया गया था। उन्होंने, दो दिवसीय **कन्फरेंस आन पेपर्स इन पब्लिक इकोनामिक्स एण्ड पॉलिसी** में चर्चाकार के रूप में भाग लिया, एनआईपीएफपी द्वारा आयोजित, 12–13 मार्च 2015।

डा. गुप्ता के प्रकाशित कार्यों में सम्मिलित हैं, "एनर्जी सेविंग्स पोटेंशियल एण्ड पॉलिसी फार एनर्जी कन्जर्वेशन इन सिलेक्टिड इण्डियन मेन्युफेक्चरिंग इंडस्ट्रीज", "रीव्यु आफ मार्केट इन्टेग्रेशन" एण्ड "फाइनेंसिंग–फार इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन जी–20 कन्ट्रीज", एनआईपीएफपी कार्य पत्र श्रृंखला में प्रकाशित।

डा. रूद्राणी भट्टाचार्य, सहायक प्रोफेसर ने "एग्रीकल्चरल मार्केट रिफोर्म एण्ड फूड इन्फ्लेशन : इनसाइट्स फ्राम ए डीएसजीई मॉडल फार इण्डिया : एस्टीमेटिंग दि प्रोपेगेशन आफ मेकअप शॉक इन होलसेल एण्ड रीटेल मार्केटिंग टू फूड इन्फ्लेशन वेरिएशन इन इण्डिया : आइडेंटिफाइंग ड्राइवर्स आफ सीपीआई फूड इन्फ्लेशन इन इण्डिया"।

डा. भट्टाचार्य ने, "इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन मेथडोलोजी इन जी–20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग" में हुई चर्चा/विचार–विमर्श का रिकार्ड तैयार किया, बैठक 23 मार्च 2015 को वित्त मंत्रालय के लिए आयोजित की गई थी तथा वित्त मंत्रालय के लिए "इण्डियाज कमेन्ट्स आन इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन्स मेथ्डोलाजी आफ इम्पेक्ट एनेलिसिस आफ जी–20 पॉलिसी एक्शन्स फार ग्रोथ रिवाइवल" पर एक पेजर तैयार किया।

डा. भट्टाचार्य ने इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई में "क्रेडिट कन्सट्रेन्ट्स, प्राडक्टिविटी शाक्स एण्ड कन्जम्पशन वोलटलिटी इन एमर्जिंग इकोनामीज" पर एक सेमिनार दिया, 11 अप्रैल 2014, एनसीएईआर **रीसर्च वर्कशाप** में "डायनेमिक स्टाकास्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडलिंग फार एमर्जिंग मार्केट्स एण्ड डवलपिंग इकोनामीज" पर, 22 सितंबर, 2014 को एनसीएईआर, नई दिल्ली में आयोजित। प्रस्तुतिकरण का शीर्षक था : "एग्रीकल्चरल मार्केट रिफोर्म एण्ड फूड इन्फ्लेशन : इनसाइट्स फ्राम ए डीएसजीई मॉडल फार इण्डिया"। उन्होंने "जी–20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग" में भी भाग लिया, 23–24 मार्च, 2015, केरल में।

डा. भट्टाचार्य ने, एनआईपीएफपी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में चार व्याख्यान दिए। उन्होंने, आईएसएस परिवीक्षार्थियों के लिए "फूड इन्फ्लेशन इन इण्डिया : सोर्सिज कन्सीक्युएंसिज एण्ड पॉलिसी इम्प्लीकेशन्स इन इण्डिया" पर एक व्याख्यान दिया, 19 जून, 2014 ; "प्राबलम्स विद प्राइस इनडाइसिज इन इण्डिया" पर एक व्याख्यान दिया, 11 फरवरी 2015, **"ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पब्लिक फाइनेंस फार आफिसर्स आफ इण्डियन आडिट एण्ड एकाउंट्स सर्विस (आईए एण्ड एएस)"**, "अण्डरस्टेंडिंग फूड

इन्फ्लेशन इन इण्डिया'' पर एक व्याख्यान दिया, 11 फरवरी 2015 को, **''ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पब्लिक फाइनेंस फार आफिसर ट्रेनीज आफ इण्डियन आडिट एण्ड एकाउन्ट्स सर्विस (आईए एण्ड एएस)** तथा ''मोनेटरी पॉलिसी एनेलिसिस इन एन इन्फ्लेशन टार्गेटिंग फ्रेमवर्क इन एमर्जिंग इकोनामीज'', 26 मार्च, 2015, **''ट्रेनिज प्रोग्राम फार आफिसर ट्रेनीज आफ इण्डियन स्टेटिस्टिकल सर्विस''।**

डा. भट्टाचार्य ने कार्य पत्र सं. 26, ''अण्डरस्टेंडिंग फूड इन्फ्लेशन इन इण्डिया'' लिखा (सह–लेखक : अभिजीत सेन गुप्ता और नरहरी राव), मई 2014, एडीबी साउथ एशिया। उन्होंने, ''जनरल आफ एशियन इकोनामिक्स ; मार्जिन ; दि जरनल आफ एप्लाइड इकोनामिक रीसर्च ; इकोनामिक मॉडलिंग'' तथा ''इण्डियाज फिस्कल पॉलिसी ; प्रेस्क्रीप्शन्स, प्रेगमेटिक्स एण्ड प्रेक्टिस'' नामक पुस्तक के कुछेक चेप्टरों की समीक्षा की, कैम्ब्रज यूनिवर्सिटी प्रैस। उन्होंने ''व्हाई फूड इन्फ्लेशन हेज बीन हाई इन इण्डिया'' पर एकेडेमिक ब्लॉग भी लिखा (अप्रैल 2014), ''आइडियाज फार इण्डिया, आईजीसी (http:ideasforindia.in article.aspx?article_id=278)

डा. सीमन्ती बंधोपाध्याय, सहायक प्रोफेसर को 31.3.2015 को पद से कार्यमुक्त कर दिया गया। सितंबर 2014 के बाद से वह बिहार के राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्तपोषित **''स्टेट फाइनेंसिज इन बिहार''** पर परियोजना से जुड़ी थी। डा. बंधोपाध्याय, को **''कानक्लेव आन फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इण्डिया''** में ''लेंडिंग फार डेवलपमेंट आफ पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर'' पर सत्र के लिए एक पैनलकार के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसका आयोजन राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे द्वारा 18 अक्तूबर 2014 को किया गया था।

डा. बंधोपाध्याय के आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान प्रकाशित कार्यों में सम्मिलित थे : दो कार्य पत्र और दो पत्रिका लेख। उनका लेख ''म्युनिसिपल फाइनेंस इन इण्डिया : सम क्लिनिकल इश्यूज'' और ''सम न्यू थाट्स आन परफोर्मेन्स इवेल्युएशन आफ गवर्नमेन्ट्स : एन एप्लीकेशन टू इण्डियन सिटीज'' इंटरनेशनल सेंटर फार पब्लिक पॉलिसी, एन्ड्रु यंग स्कूल आफ पॉलिसी स्टडीज, जोर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, एटलांटा, यूएसए में कार्यपत्र श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया गया। ''इम्पेक्ट आफ एरिया–बेस्ड वैल्युएशन्स इन प्रापर्टी टेक्सेशन : ए टेल आफ टू इण्डियन सिटीज'' पर उनका लेख ''जरनल आफ प्रापर्टी टैक्स असेस्मेंट एण्ड एडमिनिस्ट्रु यंग स्कूल आफ पॉलिसी स्टडीज'', जोर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, एटलांटा, यूएसए में कार्यपत्र श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया गया। ''इम्पेक्ट आफ एरिया–बेस्ड वैल्युएशन्स इन प्रापर्टी टेक्सेशन : ए टेल आफ टू इण्डियन सिटीज'' पर उनका लेख ''जरनल आफ प्रापर्टी टैक्स असेस्मेंट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कनाडा और यूएस में प्रकाशित किया गया। उन्होंने अपना एक लेख ''क्रिटिकल इश्यूज इन म्युनिसिपल फाइनेंस : ए समरी फार इण्डिया'' अमेरिकन इंटरनेशनल जरनल आफ सोशल साइंस'' में सम्मिलित किया, जिसे सेंटर फार प्रोमोटिंग आइडियाज (सीपीआई) यूएसए द्वारा प्रकाशित किया गया।

डा. भारती भूषण दाश, असिस्टेंट प्रोफेसर ने आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान अपनी परियोजना **''एक्सपीरिएन्स आफ इंटरगवर्नमेंटल फिस्कल अरेंजमेंट्स इन एमर्जिंग मार्केट इकोनोमीज** पूरी की (तपस के. सेन, सुधांशु कुमार, मनीष गुप्ता और एच. के. अमरनाथ के साथ), जिसे चौदहवें वित्त आयोग द्वारा प्रायोजित किया गया था। उन्होंने प्रोजेक्ट **''व्हाट इज दि क्वालिटी आफ गवर्नेस एक्रास इण्डियन स्टेट्स**

एण्ड डज इट मैटर ? पर कार्य जारी रखा (स्टानली एल. विनेर, जे. स्टीफन फेरिस, रथिन रॉय और पिनाकी चक्रवर्ती के साथ), जिसे ''सोशल साइंसिज एण्ड ह्युमैनीटीज रीसर्च काउंसिल (एसएसएचआरसी), कनाडा द्वारा प्रायोजित किया गया था।

डा. दाश, एक विजिटिंग विद्वान (अनुसंधान) के रूप में, सितंबर 2014 से दिसंबर 2014 तक ''स्कूल आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड कनाडा–इण्डिया सेंटर'', कारलेटन विश्वविद्यालय, ओटावा से सम्बद्ध थे। उन्होंने ''दि पॉलिटिकल इकोनामी आफ फिस्कल पॉलिसी : एन एनेलिसिस आफ दि इण्डियन स्टेट्स'' पर विजिटिंग विद्वान का व्याख्यान दिया, कनाडा–इण्डिया सेंटर, कारलेटन विश्वविद्यालय, ओटावा, 4 दिसंबर 2014।

डा. दाश ने दो पत्रिका लेख भी प्रकाशित किए : एक ''रीजनल इंकम डिसपैरिटी एण्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इण्डिया : एवीडेंस फ्राम सब–नेशनल डेटा'', ''साउथ एशियन इकोनामिक जरनल'' में प्रकाशित तथा अन्य ''पालिटिकल कम्पीटीशन एण्ड ह्युमन डेवलपमेंट : एवीडेंस फ्राम दि इण्डिया स्टेट्स'' ''जरनल आफ डेवलपमेंट स्टडीज में प्रकाशित (सह–लेखक : सच्चिदानन्द मुखर्जी)।

डा. सुधांशु कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, ने दो एनआईपीएफपी परियोजनाओं में अनुसंधान टीम के एक सदस्य के रूप में योगदान किया – **स्टडी आन डेवलपमेंट आफ एन एनेलिटिकल मॉडल फार वाइडनिंग आफ दि टेक्सपेयर्स बेस''**, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित तथा **''एक्सपीरिएन्स आफ इंटर–गवर्नमेंटल फिस्कल अरेंजमेंट्स इन एमर्जिंग मार्केट इकोनामीज''** चौदहवें वित्त आयोग द्वारा प्रायोजित।

डा. कुमार ने, ''टेरी'' विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में अक्तूबर–नवंबर 2014 के दौरान एम.ए. (अंतिम वर्ष छात्र) को ''मल्टीवेरीएट टाइम सीरीज इकोनामीट्रिक्स'' पर अतिथि व्याख्यान दिए। उन्होंने ''दि वेरिंग इंटरेस्ट इलास्टिसिटी एण्ड दि कोस्ट आफ इन्फ्लेशन इन इंडिया'' नामक अपने लेख के साथ ''एप्लाइड इकोनामिक्स लैटर्स'' के खण्ड 21 के लिए योगदान दिया, अंक 7, 2014।

डा. कुमार, इंडियन सांख्यिकीय सेवा परिवीक्षार्थियों के लिए ''फिस्कल एण्ड मोनेटरी पॉलिसी'' पर एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम समन्वयकर्त्ता थे, 16 से 20 जून 2014, एनआईपीएफपी। उन्होंने एक ''इन्नोवेशन प्रोजेक्ट'' का पर्यवेक्षण किया, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित, शीर्ष, ''चैलेंजिज इन वैल्युइंग इनटलेक्चुअल प्रापर्टी : एन एम्पीरिकल स्टडी आफ इण्डियन एमएसएमई''।

डा. सुकन्या बोस, असिस्टेंट प्रोफेसर, ने दो अनुसंधान प्रोजेक्ट्स पूरी की–**मेक्रोइकोनामिक पॉलिसी सिमुलेशन्स फार दि फोर्टीन्थ फाइनेंस कमीशन**, अनुसंधान टीम के एक भाग के रूप में 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रायोजित जिसमें एन आर. भानुमूर्ति और परमा देवी अधिकारी भी सम्मिलित थे तथा एन.आर. भानुमूर्ति के साथ **''मेक्रोइकोनामिक पॉलिसी माडल''** के आधार पर बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मध्यावधि मूल्यांकन के लिए योजना आयोग को अनुसंधान इनपुट उपलब्ध कराए। उन्होंने अपनी चल रही परियोजना **एमजीडी रिपोर्ट फार मध्य प्रदेश** पर अपना कार्य जारी रखा, जिसे यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित किया गया था, एन.आर. भानुमूर्ति, एच.के. अमरनाथ, परमा देवी अधिकारी और अर्काज्योति जाना के साथ अपनी अनुसंधान टीम के साथ।

डा. बोस ने, आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान अनेक सेमिनारों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। अभिषेक कुमार के सहयोग से उन्होंने "इंटर–सेक्टोरल रीलेशन्स इन पर्सपेक्टिव ' इण्डियन इकोनामी सिंस दि मिड 1990" नामक एक पत्र प्रस्तुत किया, "इम्पीरिअलिज्म–ओल्ड एण्ड न्यू" पर दो दिन का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इण्डिया इंटरनेशनल सेंटर में, जिसका आयोजन एकेडेमी आफ इंटरनेशनल स्टडीज, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था (9–10 फरवरी, 2015)। उन्होंने **एनआईपीएफपी सम्मेलन में** शिक्षा के क्षेत्र में दो पत्रों के चर्चाकार के रूप में भाग लिया – **पेपर्स इन पब्लिक इकोनामिक्स एण्ड पॉलिसी"** 12–13 मार्च 2015।

डा. बोस ने, "इश्यूज आफ ग्लोबल फाइनेंस" पर व्यवसाय अर्थशास्त्र विभाग में व्यवसाय अर्थशास्त्र मास्टर्स (अंतिम वर्ष) छात्रों के लिए अनेक व्याख्यान दिए (अप्रैल–मई 2014)। उन्होंने भारतीय सांख्यिकीय सेवा परिवीक्षार्थियों को "फिस्कल मल्टीप्लायर : दि हिस्टोरिकल एण्ड कन्टेम्पोरेरी डिबेट्स" का शिक्षण दिया, एनआईपीएफपी में (जून, 2014)। उन्होंने, भारतीय लेखा–परीक्षा और लेखा सेवा परिवीक्षार्थियों के लिए "पब्लिक पॉलिसी आन एलिमेंट्री एज्युकेशन" पर एक व्याख्यान दिया, एनआईपीएफपी (फरवरी 2015)। उन्होंने भारतीय सांख्यिकीय सेवा परिवीक्षार्थियों के लिए "इन्ट्राडक्शन टू इकोनामिक पॉलिसी" का शिक्षण प्रदान किया, एनआईपीएफपी (मार्च 2015)।

डा. बोस ने, पार्वतीबाई चौगुले कला और विज्ञान कालेज, गोआ के छात्रों के लिए "फंडामेन्टल्स आफ बजट" पर एक कार्यशाला आयोजित की, एनआईपीएफपी (18 दिसंबर, 2015)। उन्होंने भारतीय सांख्यिकीय सेवा परिवीक्षार्थियों के लिए **"मोनेटरी एण्ड फिस्कल पॉलिसी"** पर एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम–समन्वयकर्त्ता के रूप में जिम्मेदारी संभाली, एनआईपीएफपी (मार्च 2015)।

डा. बोस द्वारा आलोच्य वर्ष में प्रकाशित कार्यों में सम्मिलित थे : "मॉडलिंग इण्डियाज एक्सटर्नल सेक्टर : रीव्यु एण्ड सम एम्पीरिक्स" (सह–लेखक : एन.आर. भानुमूर्ति और स्वयंसिद्धा पाण्डा), "मार्जिन : दि जरनल आफ एप्लाइड इकोनामिक रीसर्च" और "फाइनेंशियल लिट्रेसी इन रूरल बैंकिंग : प्रोपोजल फार एन आल्टर्नेटिव अप्रोच" में प्रकाशित (सह–लेखक : अरविन्द सरदाना), "इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली" में प्रकाशित।

दीवान चंद, वरि. अनुसंधान अधिकारी, एनआईपीएफपी और अनुसंधान अधिकारी, डेटा बैंक, 2014–15 के दौरान "क्लासिफाइंग पब्लिक एक्सपेंडीचर फार इण्डियाज नेशनल हैल्थ एकाउंट्स" परियोजना में सम्मिलित थे, जिसका प्रायोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था, मीता चौधरी के साथ। उन्होंने, **"पब्लिक फाइनेंस इन्फोर्मेशन सिस्टम"** परियोजना के अंतर्गत राज्य वित्त पर डेटाबेस को अद्यतन बनाने का काम भी जारी रखा।

गीता भटनागर, अनुसंधान एसोसिएट ने आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान एक चल रही परियोजना **"पब्लिक फाइनेंस इन्फोर्मेशन सिस्टम"** के अंतर्गत राज्य वित्त पर डेटा को अद्यतन बनाने का काम जारी रखा। उन्होंने, केंद्रीय और राज्य सरकारों के वित्त लेखों और बजटों से बजटीय डेटा को अद्यतन बनाया। उन्होंने केंद्रीय सरकार और भारत के 29 राज्यों के संबंध में समय–श्रृंखला डेटा भी तैयार किया।

सतादु सिकदर, अनुसंधान एसोसिएट ने आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान, डा. प्रताप रंजन जेना के सहयोग से **मीडियम–टर्म–फिस्कल पॉलिसी 2014–15**

परियोजना को पूरा करने में योगदान किया। उनकी चल रही परियोजनाओं में सम्मिलित हैं : **गवर्नेन्स एज सर्विस डेलिवरी : परफोर्मेन्स आफ इण्डियन स्टेट्स** (सुदीप्तो मंडल के नेतृत्व में और समिक चौधरी के योगदान से) तथा ''लेवल एण्ड कम्पोजीशन आफ सब्सिडीज इन इण्डिया : 1987–88 टू 2011–12 (सुदीप्तो मंडल और एच.के. अमरनाथ के साथ)। उन्होंने **''दि रीव्यु आफ कम्प्लाएन्स टू सिक्किम एफआरबीएम एक्ट, 2012–13 एण्ड मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी 2014–15 के लिए भी योगदान किया** (प्रताप रंजन जेना के साथ)।

श्री सिकदर ने **''एमडीजी रिपोर्ट फार मध्य प्रदेश''** – परियोजनाओं के लिए अनुसंधान सहायता प्रदान की (''पावर्टी एस्टीमेशन'' खण्ड के लिए–प्रोफेसर एन.आर. भानुमूर्ति के लिए) तथा **''फेक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अनइनकारपोरेटिड एंटरप्राइजिज टू रजिस्टर अण्डर वैल्यु एडिड टैक्स (वाट) : एन एनेलिसिस विद एंटरप्राइजिज सर्वे डेटा (एन एस एस)** के यूनिट लेवल डेटा के निष्कर्षण और तालिकाकरण के लिए – अनकोरपोरेटिड एंटरप्राइजिज सर्वे–डा. सच्चिदानन्द मुखर्जी के लिए)। उन्होंने **''रीव्यु आफ एफआरबीएम एक्ट इन ओडिशा''** अध्ययन के लिए डा. प्रताप रंजन जेना को सांख्यिकी सहायता भी प्रदान की।

वर्ष के दौरान, श्री सिकदर ने एनआईपीएफपी कार्य पत्र श्रृंखला में एक पत्र ''थ्री डिकेड्स आफ ह्युमन डेवलपमेंट एक्रास इण्डियन स्टेट्स : इनक्लुजिव ग्रोथ फार परपीच्यचुअल डिस्पेरिटी ?'' भी प्रकाशित किया (सच्चिदानन्द मुखर्जी, देवासिस चक्रवर्ती के साथ)।

डा. राधिका पाण्डेय, कन्सलटेंट, ने आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान ''मेजरमेंट आफ आउटपुट एण्ड इन्फ्लेशन'' पर एक व्याख्यान दिया, 13 अक्तूबर 2014 और ''ग्रोथ एण्ड फ्लक्च्युएशन्स'' पर, 14 अक्तूबर 2014, एलबीएसएनएए मसूरी, अधिकारी प्रशिक्षार्थियों के लिए।

डा. पाण्डेय ने, ''मोटिवेशन्स फार कैपिटल कन्ट्रोल्स एण्ड देअर इफेक्टिवनैस'', बैंक आफ कनाडा कार्य पत्र 2015–5, फरवरी 2015 (सह–लेखक : गुरनैन के. पसरीचा, इला पटनायक और अजय शाह)।

सुरांजली टंडन, कन्सलटेंट ने **''विंटर स्कूल 2014''** में ''इफेक्टिवनैस आफ पॉलिसी इन दि प्रेजेन्स आफ हवाला मार्केट : ए थ्योरिटिकल एनेलिसिस (सह–लेखक), जिसका आयोजन विकास अर्थशास्त्र केंद्र और अर्थशास्त्र विभाग, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल, द्वारा किया गया था। उन्होंने ''आईडीईएस द्वारा'' डायवर्स रीजनल रेस्पोन्सिज टू दि ग्लोबल क्राइसिस : इम्प्लीकेशन्स फार फाइनेंस एण्ड दि रिअल इकोनामी'' पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लिया, 24–26 जनवरी 2015, मुत्तुकाडु, चेन्नई। उन्होंने ''इम्पेक्ट आफ गवर्नमेंट डेट आन इकोनामिक ग्रोथ इन पंजाब'' नामक राजा चेलैय्या स्मारक व्याख्यान के लिए एक चर्चाकार के रूप में योगदान किया, मार्च 2015।

सुश्री टंडन ने, आलोच्य वर्ष 2014–15 के दौरान ''ट्रेड बेलेन्स एण्ड दि रिअल एक्सचेंज रेट : एन एम्पीरिकल एनेलिसिस आफ मल्टीलेटरल एण्ड बाइलेटरल रिलेशनसिप'', ''फारेन ट्रेड रिव्यु'', मई 2014, अंक सं. 49, पृ. 117–139 का प्रकाशन किया। ''डिजाइनिंग पॉलिसीज इन दि प्रेजेन्स आफ हवाला मार्केट्स'' का प्रकाशन एनआईपीएफपी कार्य पत्र श्रृंखला में किया गया।

पायल डे, कन्सलटेंट, एनआईपीएफपी में मेक्रो/ फाइनेंस टीम के साथ, एलएसई में ''रेगुलेटरी कंट्रोल आफ फारेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट्स : ए केस आफ फार्मास्युटीकल

सेक्टर इन इण्डिया'' नामक अपने मास्टर्स शोध निबंध पर कार्य किया, जो ''जरनल आफ गवर्नेन्स एण्ड पब्लिक पॉलिसी, खण्ड 5, अंक 1, जनवरी – जून 2015, लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद में प्रकाशित हुआ था।

(http:www.ipeindia.orgmainuploadsIPEJGPPJGPP_5_1_7.pdf)

संलग्नक

संलग्नक– I

अध्ययनों की सूची 2014–2015

पूरे हो गए अध्ययन

शीर्षक	प्रायोजक एजेंसी/संस्थान का अनुसंधान यूनिट	लेखक/अनुसंधान टीम
टेक्स पॉलिसी एण्ड एनटरप्राइज डेवलपमेंट इन साउथ–एशिया	गवर्नेन्स इंस्टीट्यूट नेटवर्क इंटरनेशनल, इस्लामाबाद	आर. कविता राव, अमर ज्योति महन्ता, कौशिक भद्रा
एनआईपीएफपी–यूआईडीएआई स्टडी आन प्राइसिंग दि यूआईडीएआई आथनटिकेशन एण्ड ईकेवाईसी सर्विसिज	योजना आयोग	अजय शाह, सुयश राय, शुभो रॉय
कनसल्टेशन प्रोजेक्ट फार यूआईडीएआई : डेवलपिंग वेरियस मॉडल्स आफ बिजनिस प्लान फार कन्टीन्युयस एनरोलमेंट, अपडेट एण्ड अदर सर्विसिज आफर्ड/टू बी आफर्ड बाई यूआईडीएआई	एनआईपीएफपी– यूआईडीएआई	अजय शाह, सुयश राय, शुभो रॉय, संहिता सेपाटनेकर, स्मृति शर्मा
फाइनेंसिंग फार इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मल्टीलेटरल इन जी–20 कन्ट्रीज	रिलेशंस प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	रामप्रसाद सेन गुप्ता, सच्चिदानन्द मुखर्जी, मनीष गुप्ता
मेक्रोइकोनामिक पॉलिसी सिमुलेशन्स फार दि फोर्टीन्थ फाइनेंस कमीशन	फोर्टीन्थ फाइनेंस कमीशन	एन. आर. भानुमूर्ति, सुकन्या बोस, परमा देवी अधिकारी, अभिषेक कुमार
मिड–टर्म एप्राइजल फार दि ट्वेल्थ प्लान पीरियड	योजना आयोग	एन. आर. भानुमूर्ति, सुकन्या बोस
दि रिव्यु आफ कम्प्लाएन्स आफ दि गवर्नमेंट आफ ओडिशा टू दि एफआरबीएम एक्ट, 2012–13	ओडिशा सरकार	तपस सेन, प्रताप रंजन जेना

इन्टर–गवर्नमेंटल फाइनेंस इन फाइव एमर्जिंग मार्केट इकोनामीज	फोर्टीन्थ फाइनेंस कमीशन	तपस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मनीष गुप्ता, सुधांशु कुमार, भारती भूषण दाश
अण्डरस्टेंडिंग हाई अनस्पेंट बेलेंसिज एण्ड फण्ड फ्लो मैकेनिज्म इन मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स	ग्रामीण विकास मंत्रालय	एन. आर. भानुमूर्ति, एच. के. अमरनाथ, अखिलेश वर्मा, आदर्श गुप्ता

चल रहे अध्ययन

शीर्षक	प्रायोजक एजेंसी/संस्थान का अनुसंधान यूनिट	लेखक/अनुसंधान टीम
स्टडी आन डेवलपमेंट आफ एन एनेलिटिकल मॉडल फार वाइडनिंग आफ दि टेक्सपेयर्स बेस	सीबीडीटी	आर. कविता राव, सच्चिदानन्द मुखर्जी, सुधांशु कुमार, डी.पी. सेनगुप्ता, सुरांजली टंडन, देबोऋषि ब्रह्मचारी
एस्टीमेटिंग आरएनआर फार जीएसटी फार दि ईअर 2013–14	एनआईपीएफपी	आर. कविता राव, पिनाकी चक्रवर्ती, कौशिक भद्रा
फोर्थ एनआईपीएफपी–डीईए अनुसंधान कार्यक्रम	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	अजय शाह, अनिरूद्ध बर्मन, अतुल कुमार सिंह, कुशाग्र प्रियादर्शी, नीना जैकब, प्रमोद सिंहा, प्रतीक दत्ता, पारू जारेवाल, राधिका पाण्डेय शेखर हरी कुमार, शुभो राय, सुयश रॉय, रचना शर्मा,
		सहाना राय चौधरी, अरविन्द इलामारन, मोहित देसाई, ललित कान्ट्रेक्टर, आशिष अग्रवाल, मेहताब सिंह हंस, मयंक मिश्रा, भार्गवी झावेरी, पायल डे, संहिता सपटनेकर, स्मृति शर्मा, समीराज इल्लापावुलुरी, शेफाली मल्होत्रा, अपूर्व गुप्ता

रिसर्च आन बिजनिस साइकिल्स	इण्डिया वैल्यु एडिड एसोसिएट्स	अजय शाह, इला पटनायक, रूद्राणी भट्टाचार्य, राधिका पाण्डेय
फारेन बोरोइंग बाई इण्डियन फर्म्स : इम्प्लीकेशन्स फार ग्रोथ एण्ड मेक्रोइकोनामिक स्टेबिलिटी	इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर, लंदन अर्थशास्त्र स्कूल और राजनीतिक विज्ञान, यू.के.	अजय शाह, अपूर्वा गुप्ता
लेवल एण्ड कम्पोजीशन आफ सब्सिडीज इन इण्डिया : 1987–88 टू 2011–12	एनआईपीएफपी	सुदीप्तो मंडल, एच.के. अमरनाथ, सताद्रु सिकदर
मेक्रोइकोनामिक पॉलिसी सिमुलेशन्स मॉडल	एनआईपीएफपी और नीति आयोग	सुदीप्तो मंडल, एन.आर. भानुमूर्ति, सुकन्या बोस, परमा देवी अधिकारी
गवर्नेन्स एज सर्विस डेलिवरी : परफोर्मेन्स आफ इण्डियन स्टेट्स	एनआईपीएफपी	सुदीप्तो मंडल, सताद्रु सिकदर, समिक चौधरी
एमडीजी रिपोर्ट फार मध्य प्रदेश	यूनिसेफ, भोपाल	एन.आर. भानुमूर्ति, एच.के. अमरनाथ, सुकन्या बोस, परमा देवी अधिकारी, अर्काज्योति जाना
मीडियम–टर्म फिस्कल पॉलिसी ऑफ गोआ फार 2015–16	गोआ सरकार	प्रताप रंजन जेना, सताद्रु सिकदर
दि रिव्यु आफ कम्प्लाएंस आफ दि गवर्नमेंट आफ सिक्किम टू दि एफआरबीएम एक्ट 2012–13	सिक्किम सरकार	प्रताप रंजन जेना, सताद्रु सिकदर
मीडियम टर्म फिस्कल प्लान अण्डर एफआरबीएम एक्ट आफ सिक्किम 2015–16	सिक्किम सरकार	प्रताप रंजन जेना
व्हाट इज दि क्वालिटी आफ गवर्नेन्स अक्रास इण्डियन स्टेट्स एण्ड डज इट मैटर ?	सोशल साइंसिज एण्ड ह्युमनिटीज रीसर्च काउंसिल, कनाडा	रथिन रॉय, स्टानली एल. विनेर, जे स्टीफन फैरिस, पिनाकी चक्रवर्ती, भारती भूषण दाश
स्टडी आन बिहार स्टेट फाइनेंसिज : पॉलिसी आप्शन्स फार टेक्स राशनलाइजेशन एण्ड मोबिलाइजेशन आफ रेवेन्यु	बिहार सरकार	तपस कुमार सेन, आर. कविता राव, सच्चिदानन्द मुखर्जी

हेव न्युली–क्रिएटिड इण्डियन स्टेट्स प्रोमोटिड इनक्लुजिव डेवलपमेंट ? कम्पेरीजन आफ झारखण्ड एण्ड छत्तीसगढ़	यूनिवर्सिटी आफ ईस्ट अंगलिया, यू.के.	रथिन रॉय, मीता चौधरी
फिस्कल रीसर्च आन माइनिंग इन न्युली क्रिएटिड स्टेट्स–झारखण्ड एण्ड छत्तीसगढ़	ईएसआईडी और यूनिवर्सिटी आफ ईस्ट अंगलिया, यू.के.	रथिन रॉय, लेखा चक्रवर्ती
अवार्ड आफ दि असाइनमेंट परटेनिंग टू असेस्मेंट आफ दि रिस्कीनैस आफ दि एयरपोर्ट सेक्टर एण्ड एस्टीमेटिंग फेयर रेट आफ रीटर्न आफ इक्विटी (आरओई)	एयरपोर्ट्स इकोनामिक रेगुलेटरी अथोरिटी आफ इण्डिया	अजय शाह, सुयश राय, अपूर्व गुप्ता
अंडरस्टेंडिंग हाई अनस्पेंन्ट बेलेंसिज एण्ड फण्ड फ्लो मेकेनिज्म इन मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स	ग्रामीण विकास मंत्रालय	एन. आर. भानुमूर्ति, एच.के. अमरनाथ, अखिलेश वर्मा, आदर्श गुप्ता
स्ट्रेंग्थनिंग रीसर्च एण्ड केपेसिटी डेवलपमेंट इन दि डिपार्टमेंट	आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार	रथिन रॉय
ट्रेनिंग एण्ड असिस्टेन्स प्रोग्राम फार दि कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल (सीएजी) आफ इण्डिया	सीएजी, इण्डिया	रथिन रॉय, प्रताप रंजन जेना, मनीष गुप्ता, श्रुति त्रिपाठी
मेक्रोइकोनामिक पॉलिसी फार माइनिंग सेक्टर इन इण्डिया	एनआईपीएफपी	लेखा चक्रवर्ती
25 कंट्री स्टडी आन जेण्डर बजटिंग इन एशिया पेसिफिक	आईएमएफ, वाशिंगटन, डीसी	लेखा चक्रवर्ती

शुरू की गई नई परियोजनाएं

- बायोडायवर्सिटी फाइनेंस इनीशिएटिव इन इण्डिया : क्वालीफाइंग दि बायोडायवर्सिटी फाइनेंस गेप एण्ड डवलपिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजीज
- एनआईपीएफपी–ईएमसी पॉलिसी रीसर्च प्रोग्राम
- अपडेटिंग दि क्लासिफिकेशन आफ पब्लिक एक्सपेंडीचर फार इण्डिया नेशनल हैल्थ एकाउंन्ट्स एज पर एसएचए 2011–एनएचएसआरसी–एनआईपीएफपी

एनआईपीएफपी आधार पत्र श्रृंखला

डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इंडेक्स फार हिल स्टेट्स इन इण्डिया (अंक 134, अप्रैल 2014)	रीता पाण्डेय, पुरनमिता दासगुप्ता
रूम एट दि टाप : एन ओवरव्यु आफ फिस्कल स्पेस, फिस्कल पॉलिसी एण्ड इन्क्लुजिव ग्रोथ इन डवलपिंग एशिया (अंक 135, अप्रैल 2014)	रथिन रॉय
एक्सप्लोरिंग पॉलिसी आप्शन्स टू इनक्लूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एण्ड इलेक्ट्रिसिटी अण्डर दि प्रोपोस्ड गुड्स एण्ड सर्विसिज टेक्स (जीएसटी) रेजीम इन इण्डिया (अंक 136, मार्च 2014)	सच्चिदानन्द मुखर्जी, आर. कविता राव
डीपेन्डेन्स आफ स्टेट्स आन सेंट्रल ट्रांसफर्स : स्टेट–वाइज एनेलिसिस (अंक 137, मई 2014)	सी. भुजंग राव, डी.के. श्रीवास्तव
मॉडलिंग इण्डियाज एक्सटर्नल सेक्टर : रीव्यू एण्ड सम एम्पीरिक्स (अंक 138, मई 2014)	एन. आर. भानुमूर्ति, सुकन्या बोस, स्वयंसिद्धा पाण्डा
थ्री डिकेड्स आफ ह्युमन डेवलपमेंट अक्रास इण्डियन स्टेट्स : इनक्लुजिव ग्रोथ आर परपिच्युअल डिस्पेरिटी ? (अंक 139, जून 2014)	सच्चिदानन्द मुखर्जी, देवाशीस चक्रवर्ती, सताद्रु सिकदर
ग्राउण्ड वाटर इरीगेशन इन पंजाब : सम इश्यूज एण्ड वे फार्वर्ड (अंक 140, अगस्त 2014)	रीता पाण्डेय
फाइनेंस कमीशन आफ इण्डियाज असेस्मेंट्स : ए. पॉलिटिकल इकोनामी कन्टेंशन बिटविन एक्सपेक्टेशन्स एण्ड आउटकम्स (अंक 141, सितंबर 2014)	नीतिन के., रथिन रॉय
डिजाइनिंग पॉलिसीज इन दि प्रेजेन्स आफ हवाला मार्केट्स (अंक 142, जनवरी, 2015)	आर. कविता राव, सुरांजली टंडन
फाइनेंशियल एक्सेस – मेजरमेंट एण्ड डीटरमीनेन्ट्स : ए केस स्टडी आफ अनआर्गनाइज्ड मेन्युफेक्चरिंग एंटरप्राइजिज इन इण्डिया (अंक 143, जनवरी, 2015)	टी.ए. भवानी, एन. आर. भानुमूर्ति
फाइनेंसिंग फार इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट इन जी–20 कन्ट्रीज (अंक 144, फरवरी, 2015)	रामप्रसाद सेनगुप्ता, सच्चिदानन्द मुखर्जी, मनीष गुप्ता

आंतरिक सेमिनार श्रृंखला

दिन और तारीख	सेमिनार	विषय
मंगलवार, 27 मई, 2014	गौतम भारद्वाज, इनवेस्ट इण्डिया माइक्रो पेंशन सर्विसिज	**कैशलेस एण्ड पेपरलैस फील्ड एनरोलमेन्ट्स बाई लो–इनकम इंडीविड्युअल्स**
बुधवार, 11 जून, 2014	सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, संकाय, आईआईटी, खडगपुर	**इन्फ्लेशन टारगेट एट दि जीरो लोवर राउण्ड**
सोमवार, 16 जून, 2014	लियु झोंगयी, अनुसंधान फैलो, शंघाई इंस्टीट्यूट आफ इंटरनेशनल स्टडीज	**चाइना–इण्डिया रीलेशन्स एण्ड इकोनामिक कोआपरेशन इन मोदी इरा**
सेमवार, 16 जून, 2014	लेंट प्रिटचेट, प्रोफेसर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय	**किंकी डेवलपमेंट : फंड, बट नाट प्राडक्टिव**
मंगलवार, 22 जुलाई, 2014	सरगिओ शमुकलेर प्रमुख अर्थशास्त्री विकास अनुसंधान समूह दि वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन	**कैपिटल मार्केट फाइनेंसिंग, फर्म, ग्रोथ एण्ड फर्म साइज डिस्ट्रिब्युशन : एवीडेंस फ्राम चाइना–इण्डिया एण्ड दि रेस्ट आफ वर्ल्ड**
मंगलवार, 9 दिसंबर, 2014	रिचार्ड हेमिंग, विजिटिंग प्रोफेसर, ड्यूक सेंटर फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट	**फिस्कल स्पेस एण्ड बजट मेनेजमेंट**
बृहस्पतिवार, 29 जनवरी, 2015	एस. नुमुरा, प्रोफेसर, ओसाका स्कूल आफ इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी, ओसाका विश्वविद्यालय	**दि इफेक्ट आफ प्राइवेटाइजेशन आन इकोनामिक परफोर्मेन्स इन ट्रांसजीशनल इकोनोमीज**

31.3.2015 की स्थिति के अनुसार शासी निकाय के सदस्यों की सूची

डा. विजय केलकर, **अध्यक्ष**
अध्यक्ष रा.लो.वि.नी.सं.
134/4–6, अशोक नगर, आफ रेंज हिल रोड,
भौसले नगर, शिवाजी नगर,
पुणे–411007

नियम 7 (ख) (i) के अधीन वित्त मंत्रालय के तीन प्रतिनिधि

श्री शक्तिकांता दास, सदस्य
राजस्व सचिव,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार,
कमरा नं. 128ए, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली–110001

श्री राजीव मेहऋषि, सदस्य
सचिव (आर्थिक मामले),
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली–110001

श्री अरविन्द सुब्रमण्यन, सदस्य
मुख्य आर्थिक सलाहकार,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार,
कमरा नं. 167डी, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली–110001

नियम 7 (ख) (ii) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक का एक प्रतिनिधि

श्रीमती बलबीर कौर सदस्य
सलाहकार,
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग,
भारतीय रिजर्व बैंक,
सैंट्रल ऑफिस बिल्डिंग,
शहीद भगत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली–400 001

नियम 7 (ख) (iii) के अधीन योजना आयोग का एक प्रतिनिधि

श्रीमती सिंधुश्री खुल्लर, सदस्य
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नीति आयोग,
संसद मार्ग,
नई दिल्ली–110001

नियम 7 (ख) (iv) के अधीन प्रायोजक राज्य सरकारों के तीन प्रतिनिधि

डा. जे.एन. सिंह सदस्य
अपर मुख्य सचिव (वित्त),
गुजरात सरकार,
सचिवालय,
गांधीनगर–382010

श्री के. शनमुगम, आईएएस सदस्य
प्रधान सचिव,
वित्त विभाग,
तमिलनाडु सरकार,
सचिवालय,
चेन्नई–600009

श्री उपेन्द्रनाथ बेहेडा, आईएएस — सदस्य
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,
ओडिशा सरकार,
सचिवालय,
भुवनेश्वर–751001

नियम 7 (ख) (vi) के अधीन आईसीआईसीआई बैंक का एक प्रतिनिधि

श्री राकेश झा, — सदस्य
उप मुख्य वित्तीय अधिकारी,
आईसीआईसीआई बैंक,
आईसीआईसीआई बैंक टावर्स,
बांद्रा–कुरला कॉम्प्लैक्स, बांद्रा पूर्व,
मुंबई–400 051

नियम 7 (ख) (vii) के अधीन संस्थानों के दो प्रतिनिधि

डा. राणा कपूर, — सदस्य
अध्यक्ष,
भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग एसोसिएटिड चैम्बर्स
5, सरदार पटेल मार्ग,
चाणक्य पुरी (होटल डिप्लोमेट के निकट),
नई दिल्ली–110021

डा. ज्योत्सना सूरी, — सदस्य
अध्यक्ष,
भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चैम्बर्स संघ,
फेडरेशन हाउस,
तानसेन मार्ग,
नई दिल्ली–110001

नियम 7 (ख) (viii) के अधीन तीन प्रख्यात अर्थशास्त्री :

प्रोफेसर पुलिन बी. नायक, — सदस्य
दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल,
दिल्ली विश्वविद्यालय
सुधीर बोस मार्ग,
नई दिल्ली–110007

डा. डी.के. श्रीवास्तव, — सदस्य
मुख्य नीति सलाहकार,
अर्नस्ट एण्ड यंग,
गुड़गांव (हरियाणा)

डा. सुदीप्तो मंडल, — सदस्य
एमेरिटस प्रोफेसर,
एनआईपीएफपी,
नई दिल्ली–110067

नियम 7 (ख) (ix) के अधीन सहयोगी संस्थानों के तीन प्रतिनिधि

डा. शेखर शाह — सदस्य
महानिदेशक, एनसीएईआर,
11, परिसिला भवन, आईपी एस्टेट,
रिंग रोड,
नई दिल्ली–110002

डा. रवि कांत, — सदस्य
महानिदेशक,
भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज,
राजभवन रोड, बेला विस्ता,
हैदराबाद–500082

डा. प्रताप भानु मेहता, — सदस्य
प्रधान और मुख्य कार्यकारी,
नीति अनुसंधान केंद्र,
धर्म मार्ग, चाणक्य पुरी,
नई दिल्ली–110 021

नियम 7 (ख) (ग) के अधीन
शासी निकाय द्वारा सहयोजित एक सदस्य :

श्री मनोज फड़निस, सदस्य
प्रधान,
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान,
आईसीएआई भवन,
इंद्रप्रस्थ मार्ग, आईटीओ,
नई दिल्ली–110002

नियम 7 (ख) (xi) के अधीन
संस्थान का निदेशक (पदेन) :

डॉ. रथिन रॉय, सदस्य–
निदेशक, सचिव
राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान,
नई दिल्ली

नियम 7 (ख) (xii) के अधीन
संस्थान का एक प्रोफेसर – बारी–बारी से :

डा. रीता पाण्डेय, सदस्य
प्रोफेसर, रा.लो.वि.नि.सं.,
नई दिल्ली

विशेष आमंत्रित

सुश्री अनीता कपूर,
अध्यक्ष,
सीबीडीटी,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार,
कमरा नं. 150ए, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली–110001

श्री कौशल श्रीवास्तव,
अध्यक्ष, सीबीईसी,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार,
कमरा नं. 156ए, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली–110001

समूल्य प्रकाशनों की सूची

1. **इंसीडेंस आफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया 1973–74,** आर.जे. चैलेय्या और आर एन लाल (1978), रु. 10 ।
2. **इंसीडेंस आफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया 1973–74,** आर.जे. चैलेय्या और आर एन लाल (हिंदी रूपांतर) (1981), रु. 20 ।
3. **ट्रेण्ड्स एंड इश्यूज इन इंडियन फेडरल फाइनेंस,** आर.जे. चैलेय्या एंड एसोसिएट्स (एलाइड पब्लिशर्स) (1981), रु. 60 ।
4. **सेल्स टैक्स सिस्टम इन बिहार,** आर.जे. चैलेय्या और एम.सी. पुरोहित (सोमैय्या पब्लिकेशंस) (1981), रु. 80 ।
5. **मेजरमेंट आफ टैक्स एफर्ट आफ स्टेट गवर्नमेंट्स, 1973–76**, आर.जे. चैलेय्या और एन. सिंहा (सोमैय्या पब्लिकेशंस) (1982), रु. 60 ।
6. **इम्पैक्ट आफ द पर्सनल इनकम टैक्स,** अनुपम गुप्ता और पवन के. अग्रवाल (1982), रु. 35 ।
7. **रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन द प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर,** विनय डी. लाल, श्रीनिवास मधुर और के.के. अत्री (1982), रु. 50 ।
8. **फिस्कल इन्सेंटिव्ज एंड कॉरपोरेट टैक्स सेविंग,** विनय डी. लाल (1983), रु. 40 ।
9. **टैक्स ट्रीटमेंट आफ प्राइवेट ट्रस्ट्स**, के. श्रीनिवासन (1983), रु. 140 ।
10. **सैंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडीचर : ग्रोथ, स्ट्रक्चर एंड इम्पेक्ट (1950–51 टू 1978–79)**, के.एन. रेड्डी, जेवीएम शर्मा और एन. सिंहा (1983), रु. 80 ।
11. **एन्ट्री टैक्स एज एन आल्टर्नेटिव टू ऑक्ट्राय**, एम.जी. राव (1984), रु. 80 (पेपरबैक) और रु. 80, (हार्डकवर) ।
12. **इन्फोर्मेशन सिस्टम एंड इवेजन आफ सेल्स टैक्स इन तमिलनाडु**, आर.जे. चैलेय्या और एम.सी. पुरोहित (1984), रु. 50 ।
13. **इवेजन आफ एक्साइज ड्यूटीज इन इण्डिया : स्टडीज आफ कॉपर, प्लास्टिक्स एंड कॉटन टैक्सटाइल फैब्रिक्स,** ए. बागची तथा अन्य (1986), रु. 180 ।
14. **एस्पेक्ट्स आफ ब्लैक इकोनोमी इन इंडिया** (ब्लैक मनी रिपोर्ट के नाम से भी ज्ञात), शंकर एन. आचार्य एंड एसोसिएट्स, आर.जे. चैलेय्या द्वारा योगदान से (1986), पुनमर्फ्रद्रित संस्करण, रु. 270 ।
15. **इन्फ्लेशन एकांउंटिंग एंड कॉरपोरेट टैक्सेशन,** तपस कुमार सेन (1987), रु. 90 ।
16. **सेल्स टैक्स सिस्टम इन वेस्ट बंगाल,** ए. बागची औश्र एस.के. दास (1987), रु. 90 ।
17. **रूरल डेवलपमेंट एलाउंस (सेक्शन 35सीसी आफ द इंकम टैक्स एक्ट, 1961) : ए रिव्यू,** एच.के. सौंधी और जे.वी.एम. शर्मा (1988), रु. 40 ।

18. **सेल्स टैक्स सिस्टम इन दिल्ली,** आर.जे. चैलेय्या और के.एन. रेड्डी (1988), रु. 240 ।
19. **इन्वेस्टमेंट एलाउंस (सेक्शन 32–ए आफ द इंकम टैक्स एक्ट, 1961) : ए स्टडी**, जे.वी. एम. शर्मा और एच.के. सौंधी (1989), रु. 75 पेपरबैक और रु. 100 हार्डकवर ।
20. **स्टिमुलेटिव इफेक्ट्स आफ टैक्स इन्सेंटिव फॉर चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस : ए स्टडी आफ इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर,** पवन के. अग्रवाल (1989), रु. 100 ।
21. **प्राइसिंग आफ पोस्टल सर्विसिज इन इंडिया,** राघवेंद्र झा, एम.एन. मूर्ति और सत्यपाल (1990), रु.100 ।
22. **डोमेस्टिक सेंविंग्स इन इंडिया–ट्रैंड्स एंड इश्यूज',** उमा दत्ता राय चौधरी और अमरेश बागची (सं.) (1990), रु. 240 ।
23. **सेल्स टैक्सेशन इन मध्य प्रदेश,**एम. गोविंद राव, के.एन. बालसुब्रमण्यन और वी.बी. लुलसीधर (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991), रु. 125 ।
24. **द ऑपरेशन आफ मॉडवाट**, ए.वी.एल. नारायण, अमरेश बागची और आर.सी. गुप्ता (विकास पब्लिशिंग हाउस), (1991), रु. 250 ।
25. **फिस्कल इनसेंटिव्ज एंड बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट : एन इवेल्युएशन आफ सेक्शन 80एचएचरु,** पवन के. अग्रवाल और एच.के. सौंधी (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1991), रु. 195 ।
26. **डायरेक्ट टैक्सिज इन सिलेक्टिड कंट्रीज : ए प्रोफाइल**, (खंड 1 और 2), रु. 100 ।
27. **इफेक्टिव इनसेंटिव्ज फॉर एलुमिनियम इंडस्ट्री इन इंडिया,** मोनोग्राफ श्रृंखला–1, विश्वनाथ गोल्डर (1991), रु. 100 ।
28. **सर्वे आफ रिसर्च ऑन फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया,** विनिबंध श्रृंखला–2, एम. गोविंद राव और आर.जे. चैलेय्या (1991), रु. 100 ।
29. **रेवेन्यु एंड एक्सपेंडीचर प्रोजेक्शंस : इवेल्युएशन एंड मेथडालॉजी,** वी.जी. राव, अतुल शर्मा द्वारा संशोधित और संपादित, (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1992), रु. 195 ।
30. **सेल्स टैक्स सिस्टम इन इंडिया : ए प्रोफाइल** (1991), रु. 150 ।
31. **स्टेट फाइनेंसिज इन इंडिया, अमरेश बागची,** जे.एल. बजाज और विलियम ए. बिर्ड (सं.) (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1992), रु. 450 ।
32. **फिस्कल पॉलिसी फॉर द नेशनल कैपिटल रीजन**, महेश सी. पुरोहित, सी. साई कुमार, गोपीनाथ प्रधान और ओ.पी. वोहरा (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1992), रु. 225 ।
33. **इम्पोर्ट सब्टीट्यूशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर,** विनिबंध श्रृंखला–3, हाशिम एन. सलीम (1992), रु. 150 ।
34. **सेल्स टैक्स सिस्टम इन इंडिया : ए प्रोफाइल** (1993), रु. 150 ।
35. **द नाइन्थ फाइनेंस कमीशन : इश्यूज एंड रिकमन्डेशंस** (पत्रों का संकलन) (1993), रु. 490 ।
36. **डायरेक्ट टैक्सिज इन सिलेक्टिड कंट्रीज : ए प्रोफाइल** (खंड–3) के. कन्नन और ममता शंकर द्व ारा संकलित (1993), रु. 80 ।
37. **इंटरस्टेट एंड इंट्रा–स्टेट वेरिएशंस इन इकोनोमिक डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड आफ लिविंग,** (विनिबंध श्रृंखला–4) (1993), उमा दत्त राय चौधरी, रु. 200 ।

38. **टैक्स पॉलिसी एंड प्लानिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज'**, अमरेश बागची और निकोलस स्टर्न (सं.) (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस), रु. 435 ।
39. **रिफोर्म आफ डोमेस्टिक ट्रेड टैक्सिज इन इंडिया : इश्यूज एंड ऑप्शंस**, स्टडी टीम (1994), रु. 250 ।
40. **प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर : जेनेरेशन एंड रि–जेनेरेशन आफ वैल्थ**रु, उमा दत्ता राय चौधरी (विकास पब्लिशिंग हाउस) (1996), रु. 395 ।
41. **कंट्रोलिंग पाल्युशन : इन्सेंटिव्ज एंड रेगुलेशंस**, शेखर मेहता, सुदीप्तो मंडल और यू. शंकर (सेज पब्लिकेशंस) (1997), रु. 250 ।
42. **इंडिया : टैक्स पॉलिसी फॉर द नाइंथ ईयर प्लान (1997–98 टू 2001–02)**रु, (वित्तीय संसाधन संबंधी संचालन समूह के कर नीति विषयक कार्य दल की रिपोर्ट–अध्यक्ष–पार्थासारथी शोम) (सेनटेक्स पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि.) (1997), रु. 350 ।
43. **वैल्यू एडिड टैक्स इन इंडिया : ए प्रोग्रेस रिपोर्ट**रु, पार्थासारथी शोम (सं.) (सेनटेक्स पब्लिकेशंस प्रा.लि.) (1997), रु. 250 ।
44. **फिस्कल पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस**रु, पार्थासारथी शोम (सं.) (सेनटेक्स पब्लिकेशंस प्रा.लि.) (1997), रु. 400 ।
45. **गवर्नमेंट सब्सिडीज इन इंडिया**, डी.के. श्रीवास्तव और तपस के. सेन (1997), रु. 285 ।
46. **इकोनोमिक इन्स्ट्रूमेंट्स फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी**, यू. शंकर और ओम प्रकाश माथुर (1998), रु. 150 ।
47. **इंडिया : द चैलेंज आफ अर्बन गवर्नेंस''**, ओम प्रकाश माथुर (सं.) (1999) रु. 400 ।
48. **स्टेट फिस्कल स्टडीज–असम**, डी.के. श्रीवास्तव, सौमन चट्टोपाध्याय और टी.एस. रंगामन्नार (1999), रु. 200 ।
49. **स्टेट फिस्कल स्टडीज–पंजाब**, इंदिरा राजारमन, एच. मुखोपाध्याय और एच.के. अमरनाथ (1999), रु. 200 ।
50. **स्टेट फिस्कल स्टडीज–केरल**, डी.के. श्रीवास्तव, सौमन चट्टोपाध्याय और प्रताप रंजन जेना (1999), रु. 200 ।
51. **दिल्ली फिस्कल स्टडी**, ओम प्रकाश माथुर और टी.एस. रंगामन्नार (2000), रु. 250 ।
52. **फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया कंटेम्पोरेरी चैलेंजिज : इश्यूज बिफोर द इलेविंथ फाइनेंस कमीशन**रु, डी.के. वास्तव (सं.) हर–आनंद पब्लिकेशंस प्रा. लि. (2000), रु. 200 ।
53. **स्टेट फिस्कल स्टडीज–हरियाणा**, तपस के. सेन, आर. कविता राव (2000), रु. 200 ।
54. **कंट्रोल आफ पब्लिक मनी : द फिस्कल मशीनरी इन डवलपिंग कंट्रीज'**, ए. प्रेमचंद (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस) (2000), रु. 745 ।
55. **प्राइमर ऑन वैल्यू एडिड टैक्स'**, आर.जे. चैलेय्या, पवन के. अग्रवाल, महेश सी. पुरोहित और आर. कविता राव, (हर–आनंद पब्लिकेशंस प्रा. लि.) (2001), रु. 195 ।
56. **सैंट्रल बजटरी सब्सिसिडीज इन इंडिया**, डी. के. श्रीवास्तव और एच.के. अमरनाथ (2001), रु. 170 ।
57. **अप्रोच टू स्टेट–म्युनिसिपल फिस्कल रिलेशंस : ऑप्संस एंड पर्सपेक्टिव्ज**, ओम प्रकाश माथुर (2001), रु. 200 ।

58. **ट्रेड एंड इंडस्ट्री : एसेज बाई एनआईपीएफपी–फोर्ड फाउंडेशन फेलोज**रु, अशोक गुहा, के.एल. कृष्णा और अशोक के. लोहिड़ी (विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि.) (2001), रु. 450 ।

59. **ट्रांसफर प्राइसिंग एंड रेगुलेशंस फॉर इंडिया : अप्रूवल्स एंड आल्टर्नेटिव्ज**रु, एस.पी. सिंह, अमरेश बागची, आर.के. बजाज द्वारा योगदान के साथ (यूबीएस पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.) (2002), रु. 395 ।

60. **डिस्क्रीमिनेटरी टैक्स ट्रीटमेंट आफ डोमेस्टिक विस–ए–विस फॉरेन प्रॉडक्ट्स : एन असेसमेंट**, पवन के. अग्रवाल और वी. सेल्वाराजु (2000) रु. 200 ।

61. **द प्रैक्टिस एंड पॉलिटिक्स आफ रेगुलेशन : रेगुलेटरी गवर्नेंस इन इंडियन इलैक्ट्रिसिटी** – नवरोज के. दुबांश और डी. नरसिंहा राव (2007), रु. 290 ।

62. **टैकलिंग पावर्टी कंसट्रेट ऑन ह्युमन डेवलपमेंट : फोनेसिंग स्ट्रेटेजीज इन मध्य प्रदेश** (मानव विकास वित्त पोषण विनिबंध श्रृंखला) – तपस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और अनित एन. मुखर्जी (2007), रु. 150 ।

63. **फाइनैंसिंग ह्युमन डेवलपमेंट इन तमिलनाडु : कंसोलिडेटिंग एंड बिल्डिंग अपोन एचीवमेंट**, (मानव विकास वित्तपोषण विनिबंध श्रृंखला)–तपस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और अनित एन. मुखर्जी (2008), रु. 150 ।

64. **इंटर–स्टेट इक्वलाइजेशन आफ हैल्थ एक्सपेंडीचर इन इंडियन यूनियन** – एम. गोविंद राव और मीता चौधरी (2008), रु. 75 ।

65. **ट्रैप्ड इन द कम्फर्ट जोन आफ डिनायल : 50 ईअर्स आफ एक्सपेंडीचर मैनेजमेंट इन इण्डिया**, ए. प्रेमचंद (2008), रु. 150 ।

66. **फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन एण्ड जेण्डर बजटिंग,** एम. गोविंद राव, लेखा एस. चक्रवर्ती और अमरेश बागची (2008), रु. 250 ।

67. **फिस्कल रिफोर्म्स, परसिस्टेंट पावर्टी एंड ह्युमन डेवलपमेंट : द केस आफ उड़ीसा,** (फाइनेंसिंग ह्युमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरीज)–तपस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और प्रोविता कुन्डु (2008), रु. 150 ।

68. **डीलिंग विद फिस्कल कंस्ट्रेंट्स ऑन पब्लिक फाइनेंसिंग आफ ह्युमन डेवलपमेंट इन वेस्ट बंगाल,** (फाइनेंसिंग ह्युमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरीज)–तपस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और प्रोविता कुन्डु (2008), रु. 150 ।

69. **पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एचीविंग लो कार्बन एंड हाई ग्रोथ इन इंडिया,** यू. शंकर (2010), रु. 150 ।

70. **प्रोस्पेक्ट्स एण्ड पॉलिसीज फॉर लो कार्बन इकोनामिक ग्रोथ इन इंडिया,** रामप्रसाद सेन गुप्ता (2010), रु. 150 ।

71. **राजस्थान : फोस्टरिंग इकोनामिक ह्युमन डेवलपमेंट कनकरंटली**, (फाइनेंसिंग ह्युमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरीज)–तपस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और सुरजीत दास (2010), रु.150 ।

72. **रिसोर्सिज फॉर सस्टेनिंग ह्युमन डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश,** (फाइनेंसिंग ह्युमन डेवलपमेंट

मोनोग्राफ सीरीज)–तपस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और सुरजीत दास (2010), रु.150 ।

73. **रैपिड ट्रांजिशन आफ ए यंग स्टेट टू मैचुरिटी : रिसोर्सिज फार ह्युमन डेवलपमेंट इन छत्तीसगढ़,** (फाइनेंसिंग ह्युमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरीज)–तपस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और सुरजीत दास (2010), रु. 150 ।

74. **इंडिया : पब्लिक एक्सपेंडीचर एंड फाइनेंशियल अकांउंटेबिलिटी – पीएफएम परफोर्मेंस मैनेजमेंट असेसमेंट रिपोर्ट** – प्रताप रंजन जेना (2010), रु. 150 ।

75. **मैचिंग ह्युमन डेवलपमेंट अक्रॉस महाराष्ट्र विद इट्स इकोनामिक डेवलपमेंट,** (फाइनेंसिंग ह्युमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरीज))–तपस के. सेन, एच.के. अमरनाथ, मीता चौधरी और सुरजीत दास (2010), रु. 150 ।

76. **फाइनेंसिंग ह्युमन डेवलपमेंट इन केरल : इश्यूज एण्ड चैलेंजिज,** (फाइनेंसिंग ह्युमन डेवलपमेंट मोनोग्राफ सीरीज))–पिनाकी चक्रवर्ती, लेखा चक्रवर्ती, एच.के. अमरनाथ, और सोना मित्रा (2010), रु. 150 ।

77. **अनस्पेंट बेलेंसिज एण्ड फण्ड फ्लो मेकेनिज्म अण्डर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम (एमजीएनआर ईजीएस),** एन.आर. भानुमूर्ति, एच.के. अमरनाथ, अखिलेश वर्मा और आदर्श गुप्ता (2014), रु. 200 ।

*संबंधित प्रकाशक के पास उपलब्ध ।

#सह प्रकाशित ।

**केवल फोटो कॉपी पुस्तक पुस्तकालय में उपलब्ध ।

प्रकाशन, ड्राफ्ट/पे–आर्डर पर ही भेजे जाते हैं ।

टिप्पणी : क्रम संख्या 1 से 58 प्रकाशन अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है ।

एनआईपीएफपी संकाय की प्रकाशित सामग्री

एम. गोविन्दा राव

(सह–लेखक : पनगढिया, अरविन्द और पिनाकी चक्रवर्ती), 2014, ''स्टेट लेवल रिफोर्म्स, ग्रोथ एण्ड डेवलपमेंट इन इण्डियन स्टेट्स'', न्यूयार्क : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस ।

(सह लेखक : बर्ड, रिचार्ड), 2014, ''गवर्नेन्स एण्ड फिस्कल फेडरलिज्म'', आहलुवालिया ईश्र जज, रवि कुमार और पी. के. मोहंती (सं.),'', अर्बनाइजेशन इन इण्डिया : चेलेंजिज, अपोरच्युनिटीज एण्ड वे फोर्वर्ड'', नई दिल्ली : सेज पब्लिशर्स

––––––, 2014, ''फाइनेंसिस अर्बन सर्विसिज : यूजर चार्जिज एण्ड लोकल टेक्सेशन'', रामचन्द्रन एम. (सं.) ''इण्डियाज अर्बन कन्फ्युजन : चेलेंजिज एण्ड स्ट्रेटजीज'', नई दिल्ली : कोपल पब्लिशिंग ग्रुप, पृ. 206–223 ।

––––––––, 2014, ''पब्लिक फाइनेंस : डेवलपमेंट इक्विटी एण्ड पॉलिटिकल इकोनामी'', जालान बिमल और पुलाप्रे बालकृष्ण (सं.)'' पॉलिटिक्स इम्प्स इकोनामिक्स : एन इंटरफेस आफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनामिक्स इन कानटेम्पोरेरी इण्डिया'', नई दिल्ली : रेनलाइट / रूपा पब्लिकेशन्स, पृ. 170–187

––––––––, 2015, ''पॉलिटिकल इकोनामी आफ गवर्नमेंट फाइनेंस इन इण्डिया'', इण्डिया रीव्यु, 14 (1) : 58–72

––––––––, 2015, ''रोल एण्ड फंक्शन्स आफ नीति आयोग'', इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, एल (1) ; 13–16

––––––––, 2015, ''फिस्कल फेडरलिज्म : अपोरच्युनिटीज एण्ड चेलेंजिज फार नेपाल'', इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, एल (10); 30–35

सुदीप्तो मंडल

––––––––––, 2015, ''मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स : हाऊ इज इण्डिया डूइंग ? जानकीरमनएस. ; एल. वेंकटाचलम और आर. एम. सालेथ (सं.), ''इण्डियन इकोनामी इन ट्रांजीशन : एसेज इन आनर आफ सी.टी. कुरियन'' में सागे इण्डिया (जनवरी)

तपस के. सेन

––––––––––, 2014, ''फिस्कल फेडरलिज्म इन आपरेशन : केस आफ इण्डिया'', लोबो, लेंसी, मृत्युंजय साहू और जयेश शाह (सं.) ''फेडरलिज्म इन इण्डिया : टूवर्ड्स ए फ्रेश बेलेंस आफ पावर'' में जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स ।

रीता पाण्डेय

––––––––––, 2014, ''दि नेशनल क्लीन एनर्जी एण्ड फण्ड आफ इण्डिया : ए फ्रेमवर्क फार प्रोमोटिंग इफेक्टिव यूटीलाइजेशन'', ''एनर्जी पॉलिसी ब्रीफ सीरीज'' में स्प्रिंगेर, यूएसए

(सह लेखक : दासगुप्ता पुरनमिता), 2014, ''डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी इंडेक्स फार हिल स्टेट्स इन इण्डिया'', कार्य पत्र सं. 134, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली

––––––––––, 2014, ''ग्राउंटवाटर इरीगेशन इन पंजाब : सम इश्यूज एण्ड वे फार्वर्ड'', का.प. सं. 2014–140, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली

आर. कविता राव

(सह लेखक : मुखर्जी सच्चिदानन्द), 2014, "एक्सप्लोरिंग पॉलिसी आप्शन्स टू इन्क्लुड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एण्ड इलेक्ट्रिसिटी अण्डर दि गुड्स एण्ड सर्विसिज टैक्स (जीएसटी) रेजीम इन इण्डिया", कार्य पत्र सं. 136, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली

————————, 2014, "इंकम टैक्स चेंजिज : व्हाट इज दि ओबजेक्टिव एण्ड व्हाट आर दि इम्प्लीकेशन्स ?", "इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, ग्स्प्र (32), (अगस्त) ।

(सह लेखक : टंडन सुरन्जिली), 2015, "डिजाइनिंग पॉलिसीज इन दि प्रेजेन्स आफ हवाला मार्केट्स", का. प. सं. 142, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली ।

(सह–लेखक : मुखर्जी सच्चिदानन्द), 2015, "पालिसी आशन्स फार इन्क्लुडिंग पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एण्ड इलेक्ट्रिसिटी इन दि गुड्स एण्ड सर्विसिज टैक्स", "इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 50 (9) ; 98–107 ।

———————— 2015, "कारपोरेट टेक्सिज एण्ड एग्जम्पशन्स : व्हाट डज दि प्रोपोज्ड एजेण्डा मीन ?", इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली", एल (12) (मार्च) ।

इला पटनायक

(सह–लेखक : पाण्डे राधिका, गुरनैन के. पसरीचा और अजय शाह), 2015, "मोटिवेशन्स फार कैपिटल कन्ट्रोल्स एण्ड देअर इफेक्टिवनैस", बैंक आफ कनाडा, का. पत्र (फरवरी) ।

(सह–लेखक : शाह अजय), 2015, "फंडामेंटल रीडिजाइन आफ फाइनेंशियल लॉ : दि इण्डियन अप्रोच", इण्डियन रीव्यू", 14 (1) : 91–110 (मार्च) ।

अजय शाह

(सह–लेखक : पाण्डे राधिका, गुरनैन के. पसरीचा और इला पटनायक), 2015, "मोटिवेशन्स फार केपिटल कन्ट्रोल्स एण्ड देअर इफेक्टिवनैस", बैंक आफ कनाडा, कार्य पत्र (फरवरी)
(सह–लेखक : पटनायक इला), 2015, "फंडामेंटल रीडिजाइन आफ फाइनेंशियल लॉ : दि इण्डियन अप्रोच", इण्डिया रीव्यू, 14 (1) : 91–110 (मार्च) ।

एन.आर. भानुमूर्ति

(सह–लेखक : अमरनाथ एच.के., अखिलेश वर्मा, और आदर्श गुप्ता), 2014, "अनस्पेन्ट बेलेंसिज एण्ड फण्ड फ्लो मेकेनिज्म अण्डर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) एनआईपीएफपी, नई दिल्ली ।

————————, 2014, "रीसेन्ट डाउनटर्न इन एमर्जिंग इकोनामिक मेक्रोइकोनामिक इम्प्लीकेशन्स फार दि सस्टेनेबिल डेवलपमेंट : ए को स्टडी फार इण्डिया", यू एन–डीईएसए का. पत्र 137, न्यूयार्क ।

————————, 2014, "दि यूरोजोन क्राइसिस एण्ड इट्स कन्टेजिअन इफेक्ट्स आन दि यूरोपियन स्टाक मार्मेट्स", "स्टडीज इन इकोनामिक्स एण्ड फाइनेंस, 31 (3) ।

————————, 2014, "एक्टर्नल शॉक्स एण्ड दि इण्डियन इकोनामी : एनेलाइजिंग थ्रू ए स्माल, स्ट्रक्चरल क्वार्टरली मेक्रोइकोनामीट्रिक मॉडल", कामैय्या बी., एस.वी. सेशैय्या और जी.आर.के. मूर्ति (सं.) "सिलेक्ट इश्यूज इन मेक्रोइकोनामिक्स : ए क्वानटीटेटिव अप्रोच : ए फेस्ट क्रिफ्ट इन आनर आफ दिलीप नचाने, आईयूपी पब्लिकेशन्स ।

(सह–लेखक : दास सुरजीत और सुकन्या बोस), 2014, "आयल प्राइस शॉक, पास थ्रू पॉलिसी एण्ड इट्स इम्पेक्ट आन दि

इण्डियन इकोनामी'', खसनाबिस रत्न और इन्द्राणी चक्रवर्ती (सं.)'', मार्केट, रेगुलेशन्स एण्ड फाइनेंस : ग्लोबल मेल्टडाउन एण्ड दि इण्डियन इकोनामी, पृ. 231–253, स्प्रिंगेर (मई) ।

(सह–लेखक : बोस सुकन्या और स्वयंसिद्ध पाण्डा), 2014, ''मॉडलिंग इण्डियाज एक्सटर्नल सेक्टर : रीव्यू एण्ड सम एम्पीरिक्स'', मार्जिन–दि जरनल आफ एप्लाइड इकोनामिक रीसर्च 8 (4), एनसीएई आर ।

(सह–लेखक : शर्मा चंदन), 2014, ''डज वीक रूपी मैटर फार इण्डियाज एक्सपोर्ट्स ?''कन्नन ग्लुमलाई, आर.एस. देशपाण्डे, गुओ झिओमिंग और युई झाओमिन (सं.), ''इकोनामिक ग्रोथ, ट्रेड एण्ड पावर्टी : ए कम्पेरेटिव एनेलिसिस आफ इण्डिया एण्ड चाइना, कोणार्क पब्लिशर्स ।

(सह–लेखक : अहमद, वसीम और संजय सहगल), 2015, ''रेजीम डीपेन्डेंट डायनेमिक्स एण्ड यूरोपियन स्टाक मार्किट्स : इज असेट अलोकेशन रीअली पॉसिबिल ?'' एम्पीरिका ; जरनल आफ यूरोपियन इकोनामिक्स, 42 : 77–107 (फरवरी) ।

(सह–लेखक : भवानी टी.ए.), 2015, ''फाइनेंशियल एक्सेस–मेजरमेंट एण्ड डीटरमीनेन्ट्स : ए केस स्टडी आफ अनआर्गनाइज्ड मेन्युफैक्चरिंग एन्टरप्राइजिज इन इण्डिया'', एनआईपीएफपी कार्य पत्र सं. 143, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली ।

(सह–लेखक : अमरनाथ एच.के.) 2015, ''यूनियन बजट 2015–16 : ए ग्रोथ ओरिएंटिड बजट'', योजना, 59 ; 10–12 (मार्च) ।

पिनाकी चक्रवर्ती

(सह–लेखक : पनगढिया, अरविन्द और एम. गोविंदा राव), 2014, ''स्टेट लेवल रिफोर्म्स, ग्रोथ एण्ड डेवलपमेंट इन इण्डियन स्टेट्स, न्यूयार्क : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस ।

अंजन मुखर्जी

——— , 2014, ''व्हेन इज कम्पीटीटिव बिहेवियर ए बेस्ट रेस्पोंस ?'', मार्जित एस और एम. राजीव (सं.), ''एमर्जिंग इश्यूज इन इकोनामिक डेवलपमेंट : ए कान्टेम्पोरेरी थ्योरिटीकल पर्सपेक्टिव, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस ।

प्रताप रंजन जेना

———— 2014, ''कनवेंशनल बजट होल्ड्स होप्स फार दि फ्युचर : मेक्रो–इकोनामि व्यु'', दि चार्टर्ड एकाउंटेंट जरनल, 63 (2) (अगस्त) ।

———— 2014, ''रिफोर्म इनीशिएटिव्ज इन दि बजटिंग सिस्टम इन इण्डिया'', पब्लिक बजटिंग एण्ड फाइनेंस'', विले ब्लैकवैल (भावी) ।

लेखा चक्रवर्ती

———— 2014, ''इन्टेग्रेटिंग टाइम यूज इन पब्लिक पॉलिसी वन पेजर'', एनआईपीएफपी कार्य पत्र सं. 127 पर आधारित, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली ।

————, 2014, ''पब्लिक पॉलिसी आन नान–टैक्स रेवेन्यु : एनेलाइजिंग दि इम्पेक्ट आफ माइनिंग रायल्टी आन कम्पीटीटिवनैस'', वन पेजर 007, एनआईपीएफपी कार्य पत्र सं. 129, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली ।

———— 2014, ''मेक्रोइकोनामिक पॉलिसी फार फेरस सेक्टर : एनेलाइजिंग माइनिंग टेक्सेशन रेजीम'', पॉलिसी रीसर्च इनपुट्स फार एमएमडीआर 2014, टाटा स्टील लि. (दिसंबर) ।

————, 2014, ''मेक्रोइकोनामिक वोलेटलिटी एण्ड रीजनल फिस्कल एण्ड मोनेटरी पॉलिसीज इन लैटिन अमेरीका,

कैरिबियन, एशिया एण्ड पेसिफिक'', सिनथेसिस ड्राफ्ट पेपर, ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क (जीडीएन) ।

———————— 2014, ''मेक्रोइकोनामिक्स आफ यूनियन बजट, 2014, योजना, भारत सरकार ।

(सह–लेखक : खगोत्र साहिल), 2015, ''इकोनामिक पॉलिसी रीवाइवल फार माइनिंग'', ''सोशल साइंसिज'' (फरवरी) ।

———————— 2015, ''मेक्रोइकोनामिक पॉलिसी रीवाइवल इन माइनिंग एण्ड एनवायरनमेंट फेडरलिज्म : ग्लिम्सज फ्राम मोदी बजट 2015–16, योजना, भारत सरकार (मार्च) ।

सच्चिदानन्द मुखर्जी

(सह–लेखक : चक्रवर्ती देवाशिष), 2013, ''डू फारेन ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट लीड टू हायर सी ओ 2 एमीशन्स ? एवीडेंस फ्राम क्रास–कन्ट्री एम्पीरिकल एस्टीमेट्स'', ''रीव्यु आफ मार्केट इन्टेग्रेशन, 5 (3), 329–361 (अक्तूबर 2014) ।

(सह–लेखक : चक्रवर्ती देवाशीष), 2014, ''रीलेशनशिप बिटविन फिस्कल सब्सिडीज एण्ड सीओ 2 एमीशन्स : एवीडेंस फ्राम क्रास –कन्ट्री एम्पीरिकल एस्टीमेट्स'', ''इकोनामिक्स रीसर्च इंटरनेशनल'', खण्ड 2014, आर्टिकिल आईडी, 346139 ।

(सह–लेखक : चक्रवर्ती देवाशीष), 2014, ''ट्रांजीशन आफ ह्युमन डेवलपमेंट परफोर्मेन्स : कन्सीडरेशन फार उत्तर प्रदेश इन दि इण्डियन कनवास'' कुमार, राजीव और अमीर–उल्लाह खान (सं.) ''एज्युकेशन एण्ड हैल्थ : दि चेलेन्जिज इन यू.पी. सहारनपुर, उ.प्र. : दि ग्लोबल प्रैस ।

(सह–लेखक : चक्रवर्ती डी. और एस. सिकदर), 2014, ''थ्री डिकेड्स आफ ह्युमन डेवलपमेंट अक्रास इण्डियन स्टेट्स : इन्क्लुजिव ग्रोथ ऑर परपीच्युअल डिस्पेरिटी,'' का. प. सं. 139, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली ।

(सह–लेखक : राव, आर. कविता), 2014, ''एक्सप्लोरिंग पॉलिसी आप्शन्स टू इन्क्लुड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एण्ड इलेक्ट्रिसिटी अण्डर दि गुड्स एण्ड सर्विसिज टेक्स (जीएसटी) रेजीम इन इण्डिया'', का. प. सं. 136, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली ।

(सह–लेखक : चक्रवर्ती, डी. और जे. चैसी), 2014, ''इन्फ्लुएन्स आफ सब्सिडीज आान एक्सपोर्ट्स : एम्पीरिकल एस्टीमेट्स, पॉलिसी एवीडेंसिज एण्ड रेगुलेटरी प्रास्पेक्ट्स'', आईआईएफटी कार्य पत्र सं. ई सी 14–22, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली ।

(सह–लेखक : चक्रवर्ती, डी.), 2015, ''एनवायरनमेंटल चेलेंजिज एण्ड गवर्नेन्स : डायवर्स पर्सपेक्टिव्ज फ्राम एशिया, राउतलेज, यू.के. ।

(सह–लेखक : चक्रवर्ती डी. और जे. चैसी), 2015, ''करटेलिंग सब्सिडी वार्स इन ग्लोबल ट्रेड : रीविजिटिंग दि इकोनामिक्स आफ वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन लॉ आन सब्सिडीज'', रिरायूज जरनल आफ इंटरनेशनल लॉ एण्ड कॉमर्स'', 14 (1) ; 1–36 ।

(सह–लेखक : दाश बी.बी.), 2015, ''पॉलिटिकल कम्पीटीशन एण्ड ह्युमन डेवलपमेंट : एवीडेंस फ्राम दि इण्डियन स्टेट्स'', दि जरनल आफ डेवलपमेंट स्टडीज, 51 (1) ; 1–14 ।

(सह–लेखक : राव कविता आर.), 2015, ''पॉलिसी आप्शन्स फार इन्क्लुडिंग पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एण्ड इलेक्ट्रिसिटी इन दि गुड्स एण्ड सर्विसिज टैक्स'', ''इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली'' 50 (9) ; 98–107 ।

(सह–लेखक : चक्रवर्ती डी.), 2015, ''वाकिंग ए थिन लाइन बिटवीन ग्रोथ एण्ड डेवलपमेंट कन्सर्स ? एनवायरनमेंटल गवर्नेन्स इन इण्डिया'', मुखर्जी एस. और डी. चक्रवर्ती (सं.), ''एनवायरनमेंटल चेलेंजिज एण्ड गवर्नेन्स : डायवर्स पर्सपेक्टिव्ज फ्राम एशिया'', राउतलेज, यू.के. ।

(सह–लेखक : सेनगुप्ता, रामप्रसाद और मनीष गुप्ता), 2015, ''फाइनेंसिंग फार इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट इन जी–20, कन्ट्रीज'', का. पत्र सं. 144, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली ।

सी. भुजंग राव

(सह–लेखक : श्रीवास्तव, डी.के. और के.एस. कवि कुमार), 2014, ''एनवायरनमेंटल टेक्स रिफोर्म्स : इंटरनेशनल एक्सपीरिएन्स'', श्रीवास्तव डी.के. और के.एस. कविकुमार (सं.) ''एनवायरनमेंट एण्ड फिस्कल रिफोर्म्स इन इण्डिया'', चेप्टर 2, 26–83 और ''रोल आफ एनवायरनमेंटल सब्सिडीज इन इण्डिया'', चेप्टर 5; 183–237, नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन्स ।

(सह–लेखक : श्रीवास्तव डी.के.), 2014, 'डीपेन्डेन्स आफ स्टेट्स आन सेंट्रल ट्रांसफर्स : स्टेट–वाइज एनेलिसिस बिजनिस रिव्यु 15 (4) : 695–717 ।

(सह–लेखक : श्रीवास्तव डी.के.), 2014, ''डीपेन्डेंस आफ स्टेट्स आन सेंट्रल ट्रांसफर्स : स्टेट–वाइज एनेलिसिस, एनआईपीएफपी का.प. सं. 137, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली (मई)।

एच.के. अमरनाथ

(सह–लेखक : एन.आर. भानुमूर्ति, अखिलेश शर्मा और आदर्श गुप्ता), 2014, ''अनस्पेंट बेलेसिज एण्ड फंड फ्लो मेकेनिज्म अण्डर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), एनआईपीएफपी, नई दिल्ली ।

मनीष गुप्ता

(सह–लेखक : सेनगुप्ता रामप्रसाद), 2014, ''एनर्जी सेविंग्स पोटेंशियल एण्ड पॉलिसी फार एनर्जी कन्वर्जेशन इन सिलेक्टिड इण्डियन मेन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज'', रीव्यु आफ मार्केट इंटेग्रेशन, 5 (3) : 363–388 ।

(सह–लेखक : सेनगुप्ता रामप्रसाद और सच्चिदानन्द मुखर्जी), 2015, ''फाइनेंसिंग फार इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट इन जी–20 कन्ट्रीज, ''का.प. सं. 144, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली ।

रूद्राणी भट्टाचार्य

(सह–लेखक : गुप्ता, अभिजीत सेन और नरहरी राव), 2014 ''अण्डरस्टेंडिंग फूड इन्फ्लेशन इन इण्डिया'', एडीबी साउथ एशिया, का. पत्र सं. 26 ।

सुकन्या बोस

(सह–लेखक : भानुमूर्ति एन.आर. और सुरजीत दास), 2014, ''आयल प्राइस शॉक, पास थ्रू पॉलिसी एण्ड इट्स इम्पेक्ट आन दि इण्डियन इकोनामी'', खसनबिस रत्न और इन्द्राणी चक्रवर्ती (सं.), ''मार्केट, रेगुलेशन एण्ड फाइनेंस : ग्लोबल मेल्टडाउन एण्ड दि इण्डियन इकोनामी पृ. 231–253, स्प्रिंगेर (मई)।

(सह–लेखक : भानुमूर्ति एन.आर., सुकन्या बोस और स्वयंसिद्धा पाण्डा), 2014, ''मॉडलिंग इण्डियाज एक्सटर्नल सेक्टर : रीव्यु एण्ड सम एम्पीटिक्स'', मार्जिन–दि जरनल आफ एप्लाइड इकोनामिक रीसर्च (4), एनआईपीएफपी, नई दिल्ली ।

(सह–लेखक : सरदाना अरविन्द), 2014, ''फाइनेंशियल लिट्रेसी इन रूरल बैंकिंग : प्रोपोजल फार एन आल्टर्नेटिव अप्रोच'', ''इकोनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली'', ग्स्प (26–27) ; 80–85 ।

सताद्रु सिकदर

(सह–लेखक : मुखर्जी, सच्चिदानन्द और डी. चक्रवर्ती), 2014, ''थ्री डिकेड्स आफ ह्युमन डेवलपमेंट अक्रास इण्डियन स्टेट्स : इन्क्लुजिव ग्रोथ आर पर पीच्युअल डिस्पेरिटी'', का. प. सं. 139, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली ।

(सह–लेखक : झा प्रवीण और पूजा पार्वती), ''चेलेन्जिज टू इन्क्लुजन : हाऊ आर इण्डियाज स्कूलिंग फेअरिंग ?'' यूनिवर्सिटी आफ एज्युकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन (एनयूईपीए), नई दिल्ली (भावी) ।

(सह–लेखक : झा, प्रवीण, पी. गीता रानी और पूजा पार्वती), ''शिफ्टिंग टराई आफ पब्लिक पॉलिसी डिस्कोर्सिज फार फाइनेंसिंग आफ एज्युकेशन : एन ओवरव्यु'', प्रवीण झा और पी. गीता रानी (सं.), ''रिसोर्सिज इंस्टीट्यूशन्स एण्ड दि राइट टू एज्युकेशन : इण्डियाज कंटीन्युइंग लॉग वाक, राउतलेज (भावी)।

(सह–लेखक : झा, प्रवीण, स्वयंसिद्धा पाण्डा), ''एसोसिएशनल पावर आफ वर्कर्स इन न्योलिब्रल इण्डियाः एन एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रीलिमिनरी एक्सप्लेनेशन'', प्रोफेसर टी.एस. पपोला के सम्मान में खण्ड, आर.पीकृममगैन और प्रीत रस्तगी द्वारा संपादित (भावी)।

राधिका पाण्डेय

(सह–लेखक : गुरनैन के. पसरीचा, इला पटनायक और अजय शाह), 2015, ''मोटिवेशन्स फार कैपिटल कन्ट्रोल्स एण्ड रेअर इफेक्टिवनैस'', बैंक आफ कनाडा आधार पत्र 2015–5 (फरवरी)।

सुरांजली टंडन

———— 2014, ''ट्रेड बेलेन्स एण्ड दि रिअल एक्सचेंज रेट : एन एम्पीरिकल एनेलिसिस आफ मल्टीलेटरल एण्ड बाइलेटरल रीलेशनशिप'', फारेन ट्रेड रीव्यु, 49, 117–139 (मई)।

(सह–लेखक : आर. कविता राव), 2015, ''डिजाइनिंग पॉलिसीज इन रिप्रेजेन्स आफ हवाला मार्केट्स'' का.प. सं. 142, एनआईपीएफपी, नई दिल्ली।

पायल डे

———— 2015, ''रेगुलेटरी कंट्रोल आफ फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स : एक केस आफ फार्मास्युटीकल सेक्टर इन इण्डिया'', जरनल आफ गवर्नेन्स एण्ड पब्लिक पॉलिसी 5 (1) (जन.–जून)।

मोहम्मद आसिफ खान

———— 2014, ''यूज आफ क्लाउड कम्प्युटिंग टेक्नोलाजी : एज एन एप्लीकेशन इन लायब्रेरीज'', कुमार संजीव (सं.), ''प्रोसीडिंग्स आफ दि इंटरनेशनल कन्फरेंस ''आईसीएलएएम 2014'', ''आन कनवर्जेन्स आफ लायब्रेरीज, आर्काइव्ज एण्ड म्युजियम्स : इन्नोवेटिव आइडियाज, टेक्नोलॉजीज एण्ड सर्विसिज, पृ. 40–45।

———— 2015, ''इश्यूज आफ कापीराइट प्रोटेशन इन दि डिजिटल एटा'', राय प्रिया (सं.) ''प्रोसीडिंग्स आफ दि ट्रांसफोर्मिंग डायमेंशन आफ आईपीआर : चेलेंजिज फार न्यू एज लायब्रेरीज'' पृ. 134–138।

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार स्टाफ सदस्यों की सूची

स्थायी स्टाफ

अकादमिक

1. डा. सी. रंगाराजन	अध्यक्ष (31.10.2014 को कार्यावधि समाप्त)
2. डा. विजय केलकर	अध्यक्ष (1.11.2014 को कार्यभार संभाला)
3. डा. रथिन रॉय	निदेशक
4. डा. सुदीप्तो मण्डल	पूर्व प्रोफेसर
5. डा. एम. गोविन्दा राव	पूर्व प्रोफेसर (10.11.2014 को कार्यभार संभाला)
6. डा. तपस कुमार सेन	प्रोफेसर
7. डा. (श्रीमती) रीता पाण्डेय	प्रोफेसर
8. डा. (श्रीमती) आर. कविता राव	प्रोफेसर
9. डा. (श्रीमती) इला पटनायक	प्रोफेसर (भा.रि. बैंक पीठ) 2 वर्ष के लिए (1.5.2014 से 30.4.2016 तक वेतनरहित छुट्टी)
10. डा. अजय शाह	प्रोफेसर
11. डा. पिनाकी चक्रवर्ती	प्रोफेसर (1.1.2015 को कार्यभार संभाला)
12. डा. एन.आर. भानुमूर्ति	प्रोफेसर
13. डा. पी.आर. जेना	एसोसिएट प्रोफेसर
14. डा. (श्रीमती) लेखा एस. चक्रवर्ती	एसोसिएट प्रोफेसर
15. डा. (श्रीमती) मीता चौधरी	एसोसिएट प्रोफेसर
16. डा. सच्चिदानन्द मुखर्जी	एसोसिएट प्रोफेसर
17. डा. सी. भुजंग राव	असिसटेंट प्रोफेसर
18. डा. मुकेश कुमार आनंद	असिसटेंट प्रोफेसर
19. डा. एच.के. अमरनाथ	असिसटेंट प्रोफेसर
20. डा. मनीष गुप्ता	असिसटेंट प्रोफेसर
21. डा. (श्रीमती) सिमंती बंधोपाध्याय	असिसटेंट प्रोफेसर (13.3.2015 को कार्यमुक्त)
22. डा. दीवान चंद	वरि. अनुसंधान अधिकारी (डेटा बैंक)
23. डा. रूद्राणी भट्टाचार्य	असिसटेंट प्रोफेसर

24. डा. सुधांशु कुमार	असिसटेंट प्रोफेसर
25. डा. भारती भूषण दाश	असिसटेंट प्रोफेसर
26. डा. सुकन्या बोस	असिसटेंट प्रोफेसर
27. डा. श्रुति त्रिपाठी	अर्थशास्त्री (30.4.2014 को कार्यभार संभाला)
28. श्री ए.के. हलेन	कनिष्ठ अर्थशास्त्री (31.7.2014 को कार्यभार मुक्त)
29. सुश्री गीता भटनागर	अनुसंधान एसोसिएट
30. श्री सताद्रु सिकदर	अनुसंधान एसोसिएट

प्रशासनिक स्टाफ

1. श्रीमती अल्का मट्टा	सचिव
2. श्री नवीन भल्ला	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
3. श्री सतीश प्रभु	संपदा अधिकारी
4. श्रीमती रोमाशा मिश्रा	लेखा अधिकारी (9.8.2012–30.4.2014)
5. श्री मनीष अग्रवाल	लेखा अधिकारी (26.11.2014 को कार्यभार संभाला और 4.3.2015 को कार्यभार मुक्त)
6. श्रीमती रीता वाधवा	संपादक (31.7.2014 को अधिवर्षिता प्राप्त की)
7. श्री एस.सी. शर्मा	लेखा कार्यपालक
8. श्री भाष्कर मुखर्जी	कार्यपालक अधिकारी (प्रशासन)
9. श्री आर.एस. त्यागी	निजी सचिव
10. श्री प्रवीण कुमार	निजी सचिव
11. श्री विक्रम सिंह चौहान	निजी सचिव
12. श्री परविन्द्र कपूर	आशुलिपिक ग्रेड–1
13. श्रीमती प्रोमिला राजवंशी	आशुलिपिक ग्रेड–1 (प्रतिनियुक्ति पर)
14. श्रीमती कविता इस्सर	आशुलिपिक ग्रेड–1
15. श्री बी.एस. रावत	लेखा कार्यपालक
16. श्री एस.एन. शर्मा	सहायक (31.8.2014 को अधिवर्षिता प्राप्त)
17. श्रीमती इन्द्रा हसीजा	सहायक
18. श्री जे. एस. रावत	सहायक
19. श्री अनुरोध शर्मा	आशुलिपिक ग्रेड–।।
20. श्री दर्शन सिंह पंवार	आशुलिपिक ग्रेड–।।

21. श्रीमती अमिता मनहास	आशुलिपिक ग्रेड–।।
22. श्री कपिल कुमार आहूजा	आशुलिपिक ग्रेड–।।
23. श्रीमती ऊषा माथुर	स्टेनो–टाईपिस्ट
24. श्री आर. सुरेंद्रन	स्टेनो–टाईपिस्ट
25. श्री वसिम अहमद	स्टेनो–टाईपिस्ट
26. श्रीमती रूचि आनंद	सहायक
27. श्री सर्वेश कुमार शर्मा	क्लर्क (लेखा)
28. श्रीमती दीपिका राय	क्लर्क (लेखा)
29. श्री राजू	ड्राइवर
30. श्री परशु राम तिवारी	ड्राइवर
31. श्री मोहन सिंह	फोटोकॉपी ऑपरेटर
32. श्री किशन सिंह	होस्टल परिचर
33. श्री शिव बहादुर	माली
34. श्री शिव प्रताप	माली
35. श्री रमेश कुमार	माली
36. श्रीमती कमला तिवारी	संदेशवाहक
37. श्री राजन ढाका	संदेशवाहक
38. श्री अजय कुमार	संदेशवाहक
39. श्री मुकेश	संदेशवाहक
40. श्री हरीश चन्द	संदेशवाहक
41. श्री राजेंद्र कुमार	संदेशवाहक
42. श्री बिशंबर पांडे	चौकीदार
43. श्री के.एन. मिश्रा	होस्टल परिचर
44. श्री सुरेंद्र सिंह यादव	चौकीदार

कंप्यूटर यूनिट

1. श्री एन.के. सिंह	ईडीपी प्रबंधक
2. श्री जगदीश आर्य	अनुसंधान अधिकारी (संचार)
3. श्री अनिल कुमार शर्मा	अधीक्षक (कंप्यूटर)

पुस्तकालय स्टाफ

1.	श्री शिव चिदम्बरम	वरिष्ठ पुस्तकालय तथा सूचना अधिकारी (27.12.2013 से प्रतिनियुक्ति पर)
2.	श्री मोहम्मद आसिफ मुस्तफा खान	वरि. पुस्तकालय तथा सूचना अधिकारी (31.10.2014 को कार्यभार संभाला)
3.	श्रीमती सारिका गौर	सहायक पुस्तकालय तथा सूचना अधिकारी
4.	श्री पी.सी. उपाध्याय	सहायक पुस्तकालय तथा सूचना अधिकारी
5.	श्रीमती मंजू ठाकुर	वरिष्ठ पुस्तकालय तथा सूचना सहायक
6.	श्रीमती आजाद कौर	वरिष्ठ पुस्तकालय तथा सूचना सहायक
7.	श्री धर्मवीर	वरिष्ठ पुस्तकालय परिचर
8.	श्री नदीम अली	कनिष्ठ पुस्तकालय परिचर
9.	श्री पूरन सिंह	संदेशवाहक

अस्थाई स्टाफ

शैक्षिक

विजिटिंग प्रोफेसर, अवै. सलाहकार, वरिष्ठ परामर्शदाता/परामर्शदाता

1.	श्री डी.पी. सेनगुप्ता	प्रधान परामर्शदाता
2.	डा. अंजन मुखर्जी	विजिटिंग प्रोफेसर
3.	श्री एम.एस. साहू	विजिटिंग प्रोफेसर (7.10.2014–6.4.2015)
4.	श्री सुयश राय	वरिष्ठ परामर्शदाता
5.	श्री शुभो रॉय	विधिक परामर्शदाता
6.	श्रीमती अपूर्वा गुप्ता	परामर्शदाता
7.	श्री पुरू जरेवाल	परामर्शदाता
8.	डा. राधिका पांडे	परामर्शदाता
9.	श्री अतुल कुमार सिंह	परामर्शदाता
10.	श्री प्रमोद सिन्हा	परामर्शदाता
11.	श्री अनिरूद्ध बर्मन	परामर्शदाता
12.	श्री प्रतीक दत्ता	परामर्शदाता
13.	श्री राजीव कुमार	ड्रुपल प्रोग्रामर (17.10.14 को कार्यमुक्त)

14. श्री शेखर हरीकुमार	परामर्शदाता
15. श्री देवोऋषि ब्रह्मचारी	परामर्शदाता
16. सुश्री सुरांजली टंडन	परामर्शदाता
17. श्री कुशाग्र प्रियादर्शी	परामर्शदाता (1.4.2014 को कार्यभार संभाला)
18. श्री राजीव प्रसाद	परामर्शदाता (4.7.2014 को कार्यभार मुक्त)
19. सुश्री सीमा मल्होत्रा	परामर्शदाता (1.10.2014–31.5.2014)
20. सुश्री संहिता सप्तनेकर	परामर्शदाता (5.5.2014 को कार्यभार संभाला)
21. सुश्री सुमंती चन्द्रशेखरन	परामर्शदाता (30.4.2014 को कार्यभार मुक्त)
22. श्री विक्रम बहुरे	परामर्शदाता (13.6.2014 को कार्यभार मुक्त)
23. सुश्री वंदिता सहाय	परामर्शदाता (23.1.2015 को कार्यभार मुक्त)
24. श्री अभिषेक कुमार वर्मा	परामर्शदाता (17.7.2014 को कार्यभार मुक्त)
25. श्री अजफ्रन राजगोपाल	विधि परामर्शदाता (31.7.2014 को कार्यभार मुक्त)
26. डा. सुस्मिता मित्रा	परामर्शदाता (12.6.2014 को कार्यभार मुक्त)
27. श्री अरविंद इलामारन	परामर्शदाता (2.6.2014 को कार्यभार संभाला)
28. डा. सहाना राय चौधरी	परामर्शदाता (10.6.2014 को कार्यभार संभाला)
29. सुश्री रचना शर्मा	परामर्शदाता (9.6.2014 को कार्यभार संभाला)
30. सुश्री स्मृति शर्मा	परामर्शदाता (16.6.2014 को कार्यभार संभाला)
31. श्री ललित कांट्रेक्टर	परामर्शदाता (23.6.2014 को कार्यभार संभाला)
32. श्री मोहित देसाई	परामर्शदाता (27.6.2014 को कार्यभार संभाला)
33. सुश्री चेतना चौधरी	परामर्शदाता (28.4.2014–22.10.2014)
34. सुश्री अंकिता श्रीवास्तव	विधिक परामर्शदाता (12.5.2014–28.11.2014)
35. सुश्री शिल्पी एस. कुमार	परामर्शदाता (16.6.2014–12.9.2014)
36. सुश्री अनन्य कोटिआ	परामर्शदाता (15.7.2014–1.10.2014)
37. श्री मयंक मिश्रा	परामर्शदाता (1.9.2014 को कार्यभार संभाला)
38. श्री अनीस मन्नावा	परामर्शदाता (1.9.2014–1.10.2014)
39. श्री मेहताब सिंह हंस	परामर्शदाता (1.9.2014 को कार्यभार संभाला)
40. श्री गुरप्रीत सिंह	परामर्शदाता (1.9.2014–20.11.2014)
41. सुश्री भार्गवी झावेरी	विधि परामर्शदाता (13.10.2014 को कार्यभार संभाला)
42. श्री अखिल दुआ	परामर्शदाता (15.10.2014 को कार्यभार मुक्त)

43. श्री सतीश कोशल	परामर्शदाता (22.10.2014 को कार्यभार संभाला)
44. सुश्री पायल डे	परामर्शदाता (2.2.2015 को कार्यभार संभाला)
45. सुश्री आकृति माथुर	परामर्शदाता (22.10.2014–30.1.2015)
46. सुश्री लता बालसुब्रमण्यम	कार्यक्रम सहायक (16.2.2015 को कार्यभार संभाला)
47. श्री समीराज इल्लापावुलुरी	परामर्शदाता (16.2.2015 को कार्यभार संभाला)
48. श्री विंस सेबेस्तियन	परामर्शदाता (2.3.2015 को कार्यभार संभाला)
49. श्री आशीष अग्रवाल	परामर्शदाता (9.3.2015 को कार्यभार संभाला)
50. सुश्री शेफाली मल्होत्रा	विधि परामर्शदाता (23.3.2015 को कार्यभार संभाला)
51. सुश्री सुहासिनी प्रसाद	कार्यक्रम सहायक (10.1.2015 को मृत्यु हो गई)
52. सुश्री दिव्या जे. अथूपल्लील	परामर्शदाता
53. श्री अंकित भाटिया	परामर्शदाता (13.1.2015 को कार्यभार मुक्त)
54. सुश्री संयुक्ता बासु	परामर्शदाता (2.6.2014–30.1.2015)

प्रोजेक्ट एसोसिएट

1. सुश्री स्वयंसिद्ध पाण्डा	प्रोजेक्ट एसोसिएट (16.6.2014 को कार्यभार मुक्त)
2. सुश्री शियुली वनजा	प्रोजेक्ट एसोसिएट (16.6.2014 को कार्यभार मुक्त)
3. श्री आदर्श कुमार गुप्ता	प्रोजेक्ट एसोसिएट (7.8.2014 को कार्यभार मुक्त)
4. श्री रोहिन नौटियाल	प्रोजेक्ट एसोसिएट (16.5.2014 को कार्यभार मुक्त)
5. श्री राजीव प्रसाद	प्रोजेक्ट एसोसिएट (4.7.2014 को कार्यभार मुक्त)
6. सुश्री श्रेया कश्यप	प्रोजेक्ट एसोसिएट (1.7.2014 को कार्यभार मुक्त)
7. सुश्री परमा देवी अधिकारी	प्रोजेक्ट एसोसिएट (1.5.2014 को कार्यभार संभाला)
8. श्री अभिषेक कुमार	प्रोजेक्ट एसोसिएट (12.5.2014–25.7.2014)
9. श्री अर्का ज्योति जाना	प्रोजेक्ट एसोसिएट (15.9.2014–13.2.2014)
10. श्री अभिषेक	प्रोजेक्ट एसोसिएट (3.11.2014 को कार्यभार संभाला)
11. श्री साहिल रवगोत्रा	प्रोजेक्ट एसोसिएट (1.12.2014 को कार्यभार संभाला)

प्रशासनिक स्टाफ

1.	सुश्री नीना जैकब	प्रोग्राम प्रबंधक
2.	श्री आर मणि	परामर्शदाता (प्रशासन)
3.	श्री रोबी थॉमस	आईटी सिस्टम्स प्रशासक
4.	श्री मोहम्मद इश्तियाक	मल्टी टास्क स्टाफ (17.10.2014 को कार्यभार मुक्त)
5.	श्री राज कमल	संदेशवाहक–सह–ड्राइवर (30.1.2015 को कार्यभार मुक्त)

31.03.2015 को प्रायोजक, कॉरपोरेट, स्थायी और साधारण सदस्यों की सूची

क. प्रायोजक सदस्य

राज्य

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. गुजरात
4. कर्नाटक
5. केरल
6. महाराष्ट्र
7. उड़ीसा
8. पंजाब
9. राजस्थान
10. तमिलनाडु
11. उत्तर प्रदेश
12. पश्चिम बंगाल

अन्य

1. एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया
2. फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
3. भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड

ख. स्थायी सदस्य–राज्य/संघ शासित क्षेत्र

1. अरूणाचल प्रदेश
2. गोवा, दमन और दीव
3. हिमाचल प्रदेश
4. मध्य प्रदेश
5. मेघालय
6. मणिपुर
7. नागालैण्ड

ग. साधारण सदस्य–राज्य/संघ शासित क्षेत्र

1. हरियाणा
2. त्रिपुरा सरकार

अन्य

1. मैसर्स हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड
2. मैसर्स ट्वेन्टियथ सेंचुरी फाइनेंस कॉरपोरेशन
3. मैसर्स गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड
4. मैसर्स आईसीआरए लिमिटेड

वित्त एवं लेखें

सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

8, भूतल, कृष्णा मार्किट, कालकाजी, नई दिल्ली–110019
दूरभाष : 32500444, टेलीफैक्स : 40590344 ; ई–मेल : aksaca@airtelmail.in

स्वतंत्र लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

सेवा में,

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान की साधारण सभा के सदस्यगण,

वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली की, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक सोसायटी है, वित्तीय स्थिति के संलग्न विवरण की लेखा–परीक्षा की है और इसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उसके संलग्न आय और व्यय विवरण की भी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश व अन्य व्याख्यात्मक सूचना की लेखा–परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है जो भारत में सामान्यतः स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सोसायटी की वित्तीय निष्पादन की सही और उचित स्थिति दर्शाते हैं। उनकी इस जिम्मेदारी के अंतर्गत, वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन तैयार, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना सम्मिलित है जो एक सच्ची और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा किसी सारवान गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा किसी गलती के कारण हो।

लेखा–परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में मत व्यक्त करने की है। हमने अपनी लेखा–परीक्षा भारत के चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा–परीक्षा के संबंध में मानकों के अनुसार आयोजित की है। उन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखा–परीक्षा का निष्पादन योजना और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण किसी सारवान गलत बयानी से मुक्त हैं।

लेखा–परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटनों के बारे में लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा–परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय

विवरणों की सारवान गलत बयानी का जोखिम का आंकलन सम्मिलित है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण अथवा त्रुटि के कारण है। ये जोखिम मूल्यांकन करने में लेखा–परीक्षक, सोसायटी के वित्तीय विवरण तैयार और उचित रूप में प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हैं ताकि ऐसी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के अंतर्गत उपयुक्त हों। लेखा–परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित है।

हमारा विश्वास है कि लेखा–परीक्षा साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है पर्याप्त और हमारे लेखा–परीक्षा मत का आधार उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त हैं।

लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट और हम

i. हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

ii. हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा–परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;

iii. हमारी राय में, जहां तक बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, सोसायटी द्वारा उपर्युक्त लेखा बहियां कानून के अंतर्गत अपेक्षानुसार रखी गई हैं ;

iv. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन–पत्र और आय तथा व्यय विवरण लेखा बहियों के साथ मेल खाते हैं ;

v. हमारी राय में, इस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत वित्तीय स्थिति का विवरण और आय तथा व्यय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार तय किए गए हैं ; और

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकार किए जाने वाले लेखा पद्धति सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाते हैं :

(क) 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार सोसायटी के मामलों की वित्तीय स्थिति के तुलन–पत्र के मामले में ; और

(ख) उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में संस्थान के आय और व्यय लेखे और अधिशेष के मामले में।

सिंह कृष्णा एसोसिएट्स की ओर से

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 008714सी

(कृष्ण कुमार सिंह)

भागीदार

सदस्यता सं. 077494

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16 अक्तूबर 2015

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च, 2015 को वित्तीय स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

धनराशि रूपए में

	अनुसूची #	31.3.2015 की स्थिति	31.3.2014 की स्थिति
कोरप्स/पूंजी निधि तथा देनदारियां			
कोरप्स/पूंजी निधि	1	117,560,167	115,056,162
आरक्षित तथा अधिशेष	2	131,310,714	123,810,714
आस्थगित आय	3	19,619,827	19,176,702
धर्मादा/विनिश्चित निधियां	4	243,324,062	226,115,222
वर्तमान देनदारियां तथा प्रावधान	5	87,095,988	77,299,217
जोड़		**598,910,759**	**561,458,017**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां–पूंजीगत कार्य–प्रगति पर सहित	6	66,587,747	67,432,364
निवेश–धर्मादा/विनिश्चित निधियां	7	221,119,201	206,443,391
निवेश–अन्य	8	215,291,792	202,352,518
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	9	95,912,019	85,229,744
जोड़		**598,910,759**	**561,458,017**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखों के संबंध में टिप्पणियां	18		

अनुसूची 1 से 18 लेखों का अभिन्न अंग हैं ।

अल्का मट्टा सचिव | **डा. रथिन रॉय** निदेशक | **डा. विजय केलकर** अध्यक्ष

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

सिंह कृष्णा एसोसिएट्स की ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 008714–सी

कृष्ण कुमार सिंह
भागीदार
एम. नं. 077494

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.10.2015

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान
31 मार्च, 2015 को वित्तीय स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

धनराशि रूपए में

	अनुसूची #	31.3.2015 की स्थिति	31.3.2014 की स्थिति
आय			
केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान	10	80,055,954	73,902,469
अकादमिक कार्यकलापों से आय	11	67,687,370	52,119,074
अर्जित ब्याज	12	19,468,909	16,890,585
अन्य आय	13	12,221,964	10,697,709
प्रकाशन स्टाक में वृद्धि		19,376	—
जोड़		**179,453,573**	**153,609,837**
व्यय			
स्थापना व्यय	14	75,110,784	68,636,612
अकादमिक कार्यकलापों पर व्यय	15	53,911,904	45,055,556
प्रशासनिक व्यय	16	33,461,915	26,817,027
प्रकाशन स्टाक में कमी		—	40,330
मूल्यह्रास	6	6,989,601	6,632,106
जोड़		**169,474,204**	**147,181,631**
शेष वर्ष के संबंध में व्यय की तुलना में आय की अधिकता		9,979,369	6,428,206
घटा : पिछली अवधि की मदें		(24,637)	49,128
पीएफ ट्रस्ट को हानि के लिए क्षतिपूर्ति		—	5,343,370
शेष : वर्ष के अंत में व्यय की तुलना में आय की अधिकता		10,004,006	1,035,708
घटा : अतिरिक्त देनदारी के लिए आरक्षित निधि को अंतरित राशि		7,500,000	—
सामान्य रिजर्व को अंतरित राशि			
कोरप्स/पूंजी निधि में ले जाया गया अधिशेष के नाते शेष		2,504,006	1,035,708
महत्वपूर्ण रेखांकन नीतियां	17		
लेखों के संबंध में टिप्पणियां	18		

अनुसूची 1 से 18 लेखों का अभिन्न अंग हैं ।

अल्का मट्टा
सचिव

डा. रथिन रॉय
निदेशक

डा. विजय केलकर
अध्यक्ष

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

सिंह कृष्णा एसोसिएट्स की ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 008714–सी

कृष्ण कुमार सिंह
भागीदार
एम. नं. 077494

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.10.2015

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

धनराशि रूपए में

		31.3.2015 की स्थिति		31.3.2014 की स्थिति
अनुसूची 1. कोरप्स/पूंजी निधि				
जमा : परियोजना अनुदानों से अंतरित यूएनडीपी निधि	115,056,161		114,020,454	
जमा : आय और व्यय खाते से अंतरित अधिशेष	2,504,006		1,035,708	
		117,560,167		115,056,162
जोड़		**117,560,167**		**115,056,162**
अनुसूची–2 : रिजर्व और अधिशेष				
क. अतिरिक्त देनदारी के लिए रिजर्व				
पिछले खाते के अनुसार	35,689,863		35,689,863	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	7,500,000		—	
		43,189,863		35,689,863
ख. सामान्य रिजर्व				
पिछले खाते के अनुसार	88,120,851		88,120,851	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	—		—	
		88,120,851		88,120,851
जोड़		**131,310,714**		**123,810,714**
अनुसूची–3 : आस्थगित आय				
अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए इमारत के निर्माण के लिए केंद्रीय सरकार से अनुदान				
पिछले खाते के अनुसार	18,758,157		19,239,135	
घटा : ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के समकक्ष राशि आय और व्यय खाते को अंतरित	468,954		480,978	
		18,289,203		18,758,157
पूंजी परिसंपत्तियों के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रायोजकों से अनुदान				
पिछले खाते के अनुसार	418,545		685,271	
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1,445,182		25,514	
घटा : आय और व्यय खाते को अंतरित ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के समकख राशि	533,103		292,240	
		1,330,624		418,545
जोड़		**19,619,827**		**19,176,702**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान
31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन–पत्र का भाग है

अनुसूची–4 : विनिश्चित/धर्मादा निधियां

धनराशि रूपयों में

विवरण	फोर्ड फाउंडेशन धर्मादा निधि	सरकारी धर्मादा निधि	भारतीय रिजर्व बैंक धर्मादा निधि	वैज्ञानिक अनुसंधान निधि	आजीवन सदस्यता निधि	बिमल बागची अवार्ड निधि	जोखन मौर्य निधि	सरकारी कोरप्स निधि	राजा चेलैय्या वार्षिक व्याख्यान माला और भ्रमणकारी प्रोफेसरशिप निधि	जोड़
प्रारंभिक निधि	6,177,924	10,000,000	40,000,000	727,406	420,000	50,000	29,300	120,000,000	20,000,000	
क– निधियों का प्रारंभ में शेष	15,620,204	10,000,000	42,337,671	1,675,149	964,178	82,713	47,832	131,003,735	24,383,739	226,115,222
ख–निधि में अभिवृद्धियां										
I–अनुदान										
II–निवेशों से आय	1,065,824	863,003	3,804,057	139,019	77,365	6,902	4,663	12,151,511	1,819,830	19,932,175
जोड. –क+ख	16,686,029	10,863,003	46,141,728	1,814,168	1,041,544	89,615	52,495	143,155,246	26,203,569	246,047,397
ग–निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय	557,120	863,003	166,567	-	-	-	-	-	1,136,645	2,723,335
जोड. – ग	557,120	863,003	166,567	-	-	-	-	-	1,136,645	2,723,335
वर्ष के अंत में निवल शेष										
वर्ष का – क+ख+ग	16,128,909	10,000,000	45,975,161	1,814,168	1,041,543	89,615	52,495	143,155,246	25,066,924	243,324,062

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन–पत्र का भाग है

धनराशि रूपयों में

		31.3.2015 की स्थिति	31.3.2014 की स्थिति
अनुसूची–5 : वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान			
क. वर्तमान देयताएं			
1	वस्तुओं और सेवाओं के लिए विविध लेनदार	4,614,390	5,985,409
2	बयाना, राशि, प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि	2,105,364	2,351,135
3	परियोजना अनुदान –देखें अनुसूची 5–क	12,773,805	3,343,407
4	केंद्रीय सरकार से अप्रयुक्त अनुदान –देखें अनुसूची 5–ख	29,244,046	26,097,531
5	सांविधिक देय	2,494,572	2,813,062
6	अन्य वर्तमान देयताएं	9,901,925	14,427,769
	जोड़	**61,134,102**	**55,018,313**
ख. प्रावधान			
1	छुट्टी नकदीकरण	25,961,887	22,280,904
	जोड़	**25,961,887**	**22,280,904**
	कुल जोड़	**87,095,989**	**77,299,217**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान
31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन–पत्र का भाग है

अनुसूची–5 –क–परियोजना अनुदान

धनराशि रूपयों में

	1 अप्रैल, 2014 को अप्रयुक्त निधि	1 अप्रैल 2015 को वसूली योग्य	वर्ष के दौरान प्राप्ति	जोड़	प्रयुक्त/लाभ उठाया और आय और व्यय/ खाते में केडिट	प्रयुक्त/लाभ उठाया और आस्थगित आय में केडिट	जोड़	31 मार्च, 2014 को वसूली योग्य	31 मार्च 2015 तक अप्रयुक्त
1 मिजोरम के लिए राज्य विकास रिपोर्ट तैयार करना–योजना आयोग, भारत सरकार	–	1,640,800	–	(1,640,800)	–	–	–	संदर्भ के लिए नीचे नोट–1 देखें	–
2 वृहद–आर्थिक नीति अनुकरण मॉडल–योजना आयोग भारत सरकार	–	481,529	3,057,992	2,576,463	103,150	–	103,150	–	2,473,313
3 आउटपुट और आउटकम बजट पद्धति के विशेष संदर्भ में दक्षिण एशिया में बजटीय सुधार–भा.सा.वि.अ.प.	12,363	–		12,363	–	–	–	–	12,363
4 गहराते पूंजी खाता खुलेपन की प्रकिया में नीति विश्लेषण–ब्रिटिश उच्चायोग	–	1,697,278	1,697,278	–	–	–	–		–
5 प्रतियोगी बाजार मूल्य और संसाधनों के आंतरिक विभाजन पर कार्य करने के लिए 2 वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय फेलोशिप	8,266	–	–	8,266	–	–	–	–	8,266
6 रा.लो.वि.नी.सं.–आ.का.वि. अनुसंधान कार्यक्रम–पुराना–आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	436,712	–	–	436,712	–	–	–	–	436,712
7 आर्थिक सिद्धांत और नीति पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार–भा.सा.वि.अ.प./भा.रि.बैंक	–	12,500	–	(12,500)	–	–	–	12,500	–
8 दक्षिण एशिया, जीआईएनआई, पाकिस्तान में कर नीति और उद्यम विकास	–	13	304,853	304,839	405,572	–	405,572	100,732	–
9 भारतीय राज्यों–एसएसएचआरसी, कनाडा के बीच अधिशासन की कोटि	–	23,072		(23,072)	214,613	–	214,613	237,685	–
10 भारतीय फर्मों द्वारा विदेशी उधार : विकास के लिए निहितार्थ और मेक्रो–आर्थिक स्थिरता–एलएसई	–	122,151	1,992,819	1,870,668.00	1,463,927	–	1,463,927	–	406,741
11 डीईए में जी–20, "ब्रिक्स" के लिए अनुसंधान और क्षमता विकास का सुदृढ़ीकरण	753,585	–	898,567	1,652,152.00	1,652,152	–	1,652,152	–	–
12 साहू समिति फेज–।। – आर्थिक मामले विभाग	2,132,481	–	–	2,132,481.00	329,255	–	329,255	–	1,803,226
13 एनआईपीएफपी–चौथा डीईए अनुसंधान कार्यक्रम–आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	–	–	37,579,920	37,579,920.00	34,533,711	1,445,182	35,978,893	–	1,601,027
14 एनआईपीएफपी–चौथा डीईए अनुसंधान कार्यक्रम– कार्य दल, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	–	–	11,391,954	11,391,954.00	5,463,363	–	5,463,363	–	5,928,591
15 म.प्र. राज्य एमडीजी रिपोर्ट 2014–15, यूनिसेफ के लिए लघु वित्त पोषण करार प्रलेखों में भागीदारी	–	–	1,162,000	1,162,000.00	1,058,434	–	1,058,434	–	103,566
जोड	**3,343,407**	**3,977,343**	**58,085,383**	**57,451,446.05**	**45,224,177**	**1,445,182**	**46,669,359**	**350,917**	**12,773,805**

टिप्पणी 1: 1640800 रूपए का वसूली योग्य अनुदान बट्टे खाते डाला गया ।

टिप्पणी 2: वर्ष के दौरान प्राप्तियां, सेवा कर को घटाकर है, जहां कहीं सेवा कर लागू है ।

अनुसूची 5–ख–केंद्रीय सरकार से अप्रयुक्त अनुदान

	As at 31-Mar-15	As at 31-Mar-14
अप्रयुक्त अनुदानों का प्रारंभिक शेष	26,097,531	16,706,854
जमा : वेतन एवं भत्तों के लिए प्रयुक्त अनुदान	63,802,469	65,207,146
आवर्ती व्यय क`लिए वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	18,000,000	16,386,000
	107,900,000	98,300,000
घटा : वेतन और भत्तों के लिए प्रयुक्त अनुदान–आय और व्यय खाते में अंतरित	60,655,954	55,816,469
आवर्ती व्यय के लिए प्रयुक्त अनुदान – आय और व्यय खाते में अंतरित	18,000,000	16,386,000
अप्रयुक्त अनुदान	29,244,046	26,097,531

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान
31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन–पत्र का भाग है

अनुसूची 6 – अचल परिसंपत्तियां

धनराशि रूपयों में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 14 को	अभिवृद्धियां	बिकी/ समायोजन	1 मार्च 15 को	1 अप्रैल, 14 तक	वर्ष के लिए	बिकी/ समायोजन	31 मार्च 15 तक	31 मार्च, 15 को	1 अप्रैल, 14 को
स्वयं की निधियों में से खरीदी गई अचल परिसंपत्तियां										
1 लीजहोल्ड भूमि	18,809,202	-	-	18,809,202	-	-	-	-	18,809,202	18,809,202
2 भवन	30,846,703	226,356	-	31,073,059	9,046,722	550,656	-	9,597,378	21,475,681	21,799,981
3 आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	22,466,595	3,475,229	-	25,941,824	20,660,044	2,177,457	-	22,837,501	3,104,323	1,806,551
4 कार्यालय उपस्कर	79,90,518	656,331	-	8,646,849	7,139,404	755,981	-	7,895,385	751,464	851,114
5 फर्नीचर और सज्जा	10,046,165	256,883	131,592	10,171,456	8,178,130	1,028,621	131,592	9,075,159	1,096,297	1,868,035
6 होस्टल, पुस्तकालय, कंप्यूटर तथा सेमिनार कक्ष	3,651,894		-	3,651,894	3,651,894	-	-	3,651,894	-	-
7 एयर कंडीशनर और वाटर कूलर	5,574,004	65,650	16,080	5,623,574	4,842,953	418,993	16,080	5,245,866	377,708	731,051
8 विद्युत संस्थापन	6,360,034		-	6,360,034	4,470,297	799,389	-	5,269,686	1,090,348	1,889,737
9 वाहन	1,205,374		-	1,205,374	705,383	249,996	-	955,379	249,995	499,991
10 बागवानी उपस्कार	93,927	19,353	-	113,280	93,927	6,451	-	100,378	12,902	-
जोड़	**107,044,416**	**4,699,802**	**147,672**	**111,596,546**	**58,788,754**	**5,987,544**	**147,672**	**64,628,626**	**46,967,920**	**48,255,662**
केंद्रीय सरकार से अनुदान में से अधिप्राप्त अचल परिसंपत्तियां आकावि, वित्त मंत्रालय										
1 इमारत अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र	21,289,579	-	-	21,289,579	2,531,422	468,954	-	3,000,376	18,289,203	18,758,157
2 विद्युतीय, अग्नि–शमन और एचपीएसी कार्य–अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र	8,804,350	-	-	8,804,350	8,804,350	-	-	8,804,350	-	-
	30,093,929	**-**	**-**	**30,093,929**	**11,335,772**	**468,954**	**-**	**11,804,726**	**18,289,203**	**18,758,157**

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 14 को	अभिवृद्धियां	बिकी/ समायोजन	1 मार्च 15 को	1 अप्रैल, 14 तक	वर्ष के लिए	बिकी/ समायोजन	31 मार्च 15 तक	31 मार्च, 15 को	1 अप्रैल, 14 को
केंद्रीय सरकार से अनुदान में से अधिप्राप्त अचल संपत्तियां										
1 आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	1,516,068	1,382,102	-	2,898,170	1,113,973	511,623	-	1,625,596	1,272,574	402,095
2 कार्यालय उपस्कर	32,900	63,080	-	95,980	16,450	21,480	-	37,930	58,050	16,450
	1,548,968	**1,445,182**	**-**	**2,994,150**	**1,130,423**	**533,103**	**-**	**1,663,526**	**1,330,624**	**418,545**
विदेशी अंशदान निधियों में से प्राप्त अचल परिसंपत्तियां										
1 आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	9,880	-	-	9,880	9,880	-	-	9,880	-	-
2 फर्नीचर और सज्जा	1,523,860	-	-	1,523,860	1,523,860	-	-	1,523,860	-	-
3 बागवानी उपस्कर	624,980	-	-	624,980	624,980	-	-	624,980	-	-
जोड़	**2,158,720**	**-**	**-**	**2,158,720**	**2,158,720**	**-**	**-**	**2,158,720**	**-**	**-**
कुल जोड़	**140,846,033**	**6,144,984**	**147,672**	**146,843,345**	**73,413,669**	**6,989,601**	**147,672**	**80,255,598**	**66,587,747**	**67,432,364**
पिछला वर्ष	**134,054,745**	**16,799,552**	**10,008,264**	**140,846,033**	**68,069,323**	**6,632,106**	**1,287,760**	**73,413,669**	**67,432,364**	**-**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान
31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो तुलन–पत्र का भाग है

धनराशि रूपयों में

		31 मार्च 15 को		31 मार्च 14 को
अनुसूची–7 : निवेश–धर्मादा/विनिश्चित निधियां				
सरकारी प्रतिभूतियों में		52,417,962		44,851,000
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		168,701,239		161,592,391
जोड़		**221,119,201**		**206,443,391**
अनुसूची–8 : निवेश – अन्य				
सरकारी प्रतिभूतियों में		36,076,000		13,646,000
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		179,161,246		188,706,518
प्रतिभूति जमा के विरूद्ध अनुसूचित बैंक के पास अचल जमा		54,546		-
जोड़		**215,291,792**		**202,352,518**
अनुसूची–9 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि				
क. वर्तमान परिसंपत्तियां :				
1. इनवेंटरीज				
प्रकाशनों का भंडार		161,396		142,020
2. विविध देनदार		374,985		991,499
3. हाथ में नकद शेष –चेक/अप्रदाय सहित		47,502		7,274
4. बैंक शेष				
बचत खाता–अनुसूचित बैंकों के पास				
केनरा बैंक, जीत सिंह मार्ग, खाता संख्या 1484101001555	35,962,762		26,783,938	
केनरा बैंक, जीत सिंह मार्ग, खाता संख्या 1484106026094	4,966		4,966	
स्टेट बैंक आफ इंडिया, जेएनयू, यूएनडीपी खाता सं. 10596549875	15,134		14,555	
अनुसूचित बैंकों के पास–चालू खाता				
स्टेट बैंक आफ इंडिया, जेएनयू, यूएनडीपी खाता सं. 10596547368	8,252,283		5,892,552	
स्टेट बैंक आफ इंडिया, जेएनयू चालू खाता सं. 10596547335	46,516		46,707	
		44,281,661		32,742,718
ख. ऋण, अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां,				
1. अग्रिम व अन्य राशि–नकद अथवा समान अथवा प्राप्त होने वाली कीमत के रूप में वसूली योग्यः				
क. स्टाफ को उत्सव अग्रिम	31,350		22,200	
ख. पूर्वप्रदत्त व्यय	9,636,951		9,353,728	
ग. व्यय के लिए स्टाफ को अग्रिम	327,435		130,472	
घ. प्रतिभूति जमा	583,023		580,623	
ड. "सेनवाट" क्रेडिट–आस्थगित	33,643		60,758	
च. "सेनवाट" क्रेडिट	-		483,902	
		10,612,402		10,631,683
2. उपार्जित आय				
क. विनिश्चित/धर्मादा निधियों में निवेशों पर आय	2,124,253		5,754,649	
ख. निवेशों पर – अन्य	6,350,946		3,556,633	
ग. प्रतिभूति जमा पर आय	-		4,284	
घ. राज्य सरकार अनुदान	-		200,000	
ड. पाठ्यक्रम कार्यक्रम और परियोजना आय	9,616,518		11,628,985	
च. परियोजना अनुदान –अनुसूची 5–क देखें	350,917		3,977,343	
		18,442,634		25,121,894
3. प्राप्ति योग्य दावे				
आय कर वसूली योग्य		21,948,289		12,092,656
अन्य वूसली योग्य		43,150		3,500,000
जोड़		**95,912,019**		**85,229,744**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान
31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां, जो आय और व्यय खाते का भाग हैं

धनराशि रूपयों में

	31 मार्च, 2015 की स्थिति	31 मार्च, 2014 की स्थिति
अनुसूची–10 : केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान		
क. केंद्रीय सरकार से अनुदान		
वेतन अनुदान – देखें अनुसूची 5–ख	60,655,954	55,816,469
आवर्ती अनुदान–देखें अनुसूची 5–ख	18,000,000	16,386,000
जोड़–क	**78,655,954**	**72,202,469**
ख. राज्य सरकारों से अनुदान		
सामान्य सहायता अनुदान		
कर्नाटक सरकार	-	300,000
उड़ीसा सरकार	500,000	500,000
महाराष्ट्र सरकार	100,000	100,000
तमिलनाडु सरकार	100,000	100,000
नागालैण्ड सरकार	200,000	400,000
गुजरात सरकार	500,000	300,000
जोड़–ख	**1,400,000**	**1,700,000**
कुल जोड़–क+ख	**80,055,954**	**73,902,469**
अनुसूची–11 : अकादमिक कार्यकलापों से आय		
कोर्स, कार्यक्रम और परियोजना आय	21,018,011	27,241,109
प्रयुक्त सीमा तक परियोजना अनुदान – सदंर्भ अनुसूची 5–क	46,669,359	24,877,965
जोड़	**67,687,370**	**52,119,074**
अनुसूची–12 : अर्जित ब्याज		
बैंको/वित्तीय संस्थाओं से अर्जित ब्याज		
अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमा	6,267,174	7,021,661
अनुसूचित बैंकों के पास बचत खातों पर	721,505	682,673
सरकारी व अन्य प्रतिभूतियों पर	12,475,949	8,983,807
आयकर वापसी पर ब्याज	-	198,160
अन्य ब्याज	4,281	4,284
जोड़	**19,468,909**	**16,890,585**
अनुसूची–13 : अन्य आय		
प्रकाशनों की बिक्री	4,010	2,700
वसूलियां	8,466,806	6,106,102
परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ	42,485	274,508
विविध आय	495,432	1,063,774
मकान किराया वसूलियां	145,101	112,628
रा.जो.वि.नी.सं. स्टाफ से प्राप्त परामर्श फीस	472,229	143,501
देनदारियां बट्टे खाते डाली गई	887,692	214,814
साधारण सदस्यता फीस	-	5,000
विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ	706,152	1,998,587
आस्थगित आय से अंतरित राशि–अनुसूची 3 देखें ।	1,002,057	773,218
बट्टे खाते डाले गए अप्रयुक्त अनुदान–अनुसूची 5–क देखें ।	-	2,877
ज्वजंस	**12,221,964**	**10,697,709**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान
31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अनसूचियां, जो आय और व्यय खाते का भाग हैं

धनराशि रूपयों में

	31 मार्च, 2015 की स्थिति	31 मार्च, 2014 की स्थिति
अनुसूची–14 : स्थापना व्यय		
वेतन और भत्ते	55,750,904	51,780,734
बोनस	139,024	129,525
पीएफ व पेंशन निधि के लिए अंशदान	5,603,805	5,181,567
उपदान	3,550,321	3,277,223
छुट्टी वेतन	5,154,439	4,397,742
स्टाफ लाभ तथा कल्याण	3,692,378	2,579,980
ईडीएलआई तथा प्रशासनिक प्रभार	140,078	115,059
परामर्श फीस	1,674,235	1,252,016
	75,705,184	**68,713,846**
घटा : अकादमिक कार्यकलापों को प्रभारित	594,400	77,234
जोड़	**75,110,784**	**68,636,612**
अनुसूची–15 : अकादमिक कार्यकलापों पर व्यय		
पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और परियोजना खर्च	7,242,545	20,177,591
परियोजना अनुदान का उपयोग–अनुसूची 5–क देखें	46,669,359	24,877,965
	53,911,904	**45,055,556**
अनुसूची–16 : प्रशासनिक व्यय		
यात्रा और सवारी	1,513,465	606,908
दरें और कर	2,380,379	970,970
विद्युत प्रभार	5,665,417	5,026,140
जल प्रभार	391,043	381,658
मुद्रण और लेखन सामग्री	887,388	583,761
टेलीफोन और डाकखर्च	1,018,780	1,249,270
मरम्मत और अनुरक्षण	7,917,145	8,066,788
कार संचालन और अनुरक्षण	402,700	399,096
आडिट फीस	212,700	131,462
आडिट फीस–पीएफ ट्रस्ट	12,000	12,000
आडिट फीस–उपदान ट्रस्ट	14,450	14,700
विविध व्यय	158,962	433,303
विधिक व्यय	727,580	800,533
विज्ञापन पर व्यय	254,409	141,574
25वीं वर्षगांठ पर व्यय	-	60,000
पीएफ की परिपक्वता/उपदान न्यास निवेश पर हानि	51,050	3,000
पीएफ ट्रस्ट की–ब्याज आय में कमी व अन्य हानियां	-	92,074
पुस्तकें तथा पत्रिकाएं	8,671,221	7,610,864
प्रकाशनों की लागत	516,239	500,214
बैठक और सेमिनार	394,004	219,247
साधारण/शासी निकाय बैठक	155,199	40,609
बीमा व्यय	62,984	49,578
वसूली योग्य–बट्टे खाते डाला गया	2,792,704	159,954
व्यावसायिक फीस	125,099	131,651
	34,324,918	27,685,354
घटा : धर्मादा/विनिश्चित निधियों पर प्रभारित	863,003	868,327
जोड़	**33,461,915**	**26,817,027**

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान
नई दिल्ली

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के संबंध में अनुसूचियां, जो लेखों का भाग हैं

अनुसूची–17 : लेखा–पद्धति नीतियां :

1. वित्तीय विवरण, प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के अंतर्गत चल रही कन्सर्न आधार पर, और भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुसार, तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो। साधारण सदस्यता फीस को नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
2. दीर्घावधिक निवेश, ऐसे निवेशों के मूल्य में स्थायी ह्रास के लिए किए गए प्रावधानों को काटने के बाद लागत पर उल्लिखित किया जाता है।
3. प्रकाशनों की माल सूची, लागत पर अथवा निवल वसूली योग्य लागत पर, जो भी कम हो, मूल्यांकित की गई है। लागत, एफआईपीओ आधार पर निर्धारित की जाती है। दस वर्ष से अधिक पुराने प्रकाशनों को और परियोजना अनुदानों से वित्त पोषित प्रकाशनों को शून्य पर मूल्यांकित किया गया है।
4. अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख, अधिप्राप्ति की लागत पर और अधिग्रहण से संबंधित प्रासंगिक और प्रत्यक्ष व्यय सहित, किया गया है। अचल परिसंपत्तियों को संचयित मूल्यह्रास को कम करके लागत पर आंका गया है।
5. लीजहोल्ड भूमि और इमारत को छोड़कर सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास तीन वर्ष की अवधि के दौरान सीधे आधार पर प्रभारित किया जाता है। लीज़होल्ड भूमि पर मूल्यह्रास "शून्य" दर पर और भवन पर घटे मूल्य आधार पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर प्रभारित किया गया है। 1 अक्तूबर को अथवा उसके बाद खरीदी तथा इस्तेमाल की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उस वर्ष के संबंध में ऊपर बताई गई दरों के आधे पर प्रभारित किया जाता है।
6. प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से यह आकलन किया जाता है कि क्या इस बात का कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। ऐसे किसी संकेत के मामलों में प्रबंधन परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाता है। यदि किसी परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि उसकी वाहक राशि से कम है तो परिसंपत्ति की वाहक राशि उसकी वसूलीयोग्य राशि तक कम कर दी जाती है और अंतर को क्षति नुकसान के रूप में माना जाता है।
7. पुस्तकालय के लिए खरीदी गई पुस्तकों और पत्रिकाओं को खरीद वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

8. अल्पावधि कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के आय और व्यय खाते से बगैर बट्टे वाली राशि में से खर्च के रूप में माना जाता है, जिस वर्ष में संबंधित सेवा की गई है।

9. रोजगार पश्चात और अन्य दीर्घावधिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के आय और व्यय खाते में खर्च के रूप में माना जाता है, जिस वर्ष में कर्मचारी ने सेवा की है। खर्च को देय राशि के वर्तमान मूल्य पर माना जाता है, जिसे बीमांकिक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके तय किया जाता है। रोजगार पश्चात् और अन्य दीर्घावधिक लाभों के संबंध में बीमांकिक लाभ और हानियों को राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. सभी विदेशी मुद्रा लेन–देनों को सामान्यतः लेखा बहियों में लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर हिसाब में लिया जाता है।

11. विनिश्चित/धर्मादा निधियों से निवेश पर आय का उपयोग निधियों के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है। अप्रयुक्त रहती आय की शेष राशि, यदि कोई हो, संबंधित विनिश्चित/धर्मादा निधियों में रखी जाती है।

12. विशिष्ट प्रयोजना के लिए प्राप्त अनुदानों/अंशदानों को प्रारंभ में देनदारी के रूप में समझा और उसी वर्ष के दौरान उपयोगिता के अनुसार समायोजित किया जाता है। मूल्यह्रास–योग्य परिसंपत्तियों के लिए प्रयुक्त सीमा तक अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में समझा जाता है और आय तथा व्यय खाते में एक व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर माना जाता है। सामान्यतः राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त सीमा तक परियोजना अनुदानों को वर्ष की आय के रूप में समझा जाता है, सिवाय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से वेतन और आवर्ती व्यय को, जिन्हें वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सहमति ज्ञापन के अनुसार उस वर्ष की आय के रूप में समझा जाता है।

13. प्रावधानों को तब मान्यता प्रदान की जाती है जबकि पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है जिनके संबंध में संभावना है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता है और विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रावधान की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और दायित्व के वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को परिलक्षित करने के लिए आवश्यक होने पर, उनका समायोजन किया जाता है।

14. आकस्मिक देनदारी का प्रकटन तब किया जाता है जबकि संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्व होता है किंतु जिसके लिए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता नहीं होगी। उस वर्तमान दायित्व के संबंध में भी प्रकटन किया जाता है जिसके लिए संभवतः संसाधनों के बाह्य प्रवाहों की आवश्यकता होती है, जहां सम्बद्ध बाह्य प्रवाह का विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव नहीं होता।

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान
नई दिल्ली

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के संबंध में अनुसूचियां, जो लेखों का भाग हैं

अनुसूची–18 : लेखों के संबंध में टिप्पणियां

1. आकस्मिक देनदारी

संस्थान के विरूद्ध दायर और संस्थान द्वारा दायर न्यायालय मामलों के संबंध में देनदारी : (राशि) तय नहीं हुई है, सिवाय निम्नलिखित मामलों के :

(क) संस्थान और उसके कामगारों के बीच सन् 1997 के औद्योगिक विवाद संख्या 215 में, अधिकरण ने अपने दिनांक 12.04.2002 के अवार्ड में यह मत व्यक्त किया था कि संस्थान के सहायक और आशुलिपिक 1.1.1986 से 1400–2300/– के ग्रेड की बजाय 1640–2900/– के ग्रेड में फिटमेंट और संशोधित डी.ए. के हकदार हैं। संस्थान ने डब्ल्यूपी (सी) संख्या 6349/2002 के अनुसार दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में अवार्ड के विरूद्ध अपील की और 1.1.1986 से वेतन और भत्तों के बकाया की अदायगी नहीं की।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1.8.2012 के आदेश के अनुसार अधिकरण के निर्णय को उचित ठहराया है और वेतन के बकाया की अदायगी चार महीने के अंदर करने का निर्देश दिया। मामला, इस संबंध में सलाह और आगे की कार्रवाई के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। मंत्रालय ने अपने दिनांक 16.10.2012 के पत्र के अनुसार, संस्थान को दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष एक "लेटर्स पेटेन्ट अपील (एलपीए) फाइल करने की सलाह दी। संस्थान ने दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9.11.2012 को एलपीए फाइल की। एलपीए को स्वीकार कर लिया गया है और बकायों के संबंध में देनदारी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख) संस्थान लीजहोल्ड भूमि के लिए वर्षानुवर्ष आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को ग्राउंड किराए की अदायगी करता है। संस्थान के रिकार्ड के अनुसर ग्राउंड किराए की नियमित रूप से अदायगी की गई है, ग्राउण्ड किराए के संबंध में कोई बकाया देनदारी नहीं है। तथापि, डीडीए रिकार्ड के अनुसार, कुछेक पिछले वर्षों के संबंध में ग्राउंड किराया बाकी रहता है। डीडीए ने समय–समय पर बकाया ग्राउंड किराए और उस पर ब्याज की मागं की है। संस्थान ने मांग का विरोध किया है और पिछले सभी वर्षों के संबंध में ग्राउंड किराए की अदायगी का ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया है। मामले का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है और डीडीए ने पिछली बार अपने दिनांक 18.06.2014 के पत्र के अनुसार 3,16,077/–रुपए की मांग की है,

जिसका विरोध किया गया है तथा इस संबंध में खाता बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2. पूंजी वचनबद्धताएं : शून्य रुपए (पिछला वर्ष – शून्य रुपए)।
3. उपलब्ध सूचना के अनुसार, कोई राशि देय नहीं है जिसकी माइक्रो लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम 2006 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटन/व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
4. संस्थान प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का वसूली मूल्य सामान्यतः व्यवसाय वसूली मूल्य सामान्यतः व्यवसाय वसूली पर होने वाला मूल्य है जो कम से कम उस राशि के बराबर है जिस पर उनका उल्लेख तुलन–पत्र में किया गया है तथा सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान वित्तीय विवरण में किया गया है।
5. धर्मादा/निश्चित निधियों के निवेशों में 4,12,44,042/–रुपए के कोटिड निवेश सम्मिलित हैं। उन कोटिड निवेशों का बाज़ार मूल्य 4,29,93,600/– रु. है। अन्य निधियों के निवेश में 1,00,00,000/– रुपए के कोटिड निवेश सम्मिलित हैं। उन कोटिड निवेशों का बाजार मूल्य 1,01,65,000/–रुपए है।
6. निश्चित अंशदान योजना के लिए अंशदान के लिए खर्च के रूप में समझा जाने वाला अंशदान निम्न प्रकार है :

भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान : 48,70,063 रुपए (पिछले वर्ष 47,46,303 रुपए)।

पेंशन स्कीम के लिए नियोक्ता का अंशदान : 7,33,742 रुपए (पिछले वर्ष 4,35,264 रुपए)।

कर्मचारी उपदान निधि स्कीम, जिसका प्रबंध ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, एक निश्चित लाभ योजना है। दायित्व का वर्तमान मूल्य, प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाता है, जिसके अंतर्गत सेवा की प्रत्येक अवधि के लिए अंतिम दायित्व तय करने के लिए प्रत्येक यूनिट के संबंध में अलग–अलग कर्मचारी लाभ हकदारी और उपायों को अतिरिक्त यूनिट के रूप में सेवा की प्रत्येक अवधि को स्वीकार किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में दायित्व को भी उसी ढंग से उपदान के रूप में माना जाता है।

तुलन–पत्र की तारीख को प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक धारणाएं निम्न प्रकार हैं :

(क) आर्थिक धारणाएं

प्रमुख धारणाएं हैं : (1) डिस्काउंट दर, और (2) वेतन वृद्धि। डिस्काउंट दर सामान्यतः लेखांकन की तारीख पर, एक ऐसी अवधि के साथ जो देनदारियों से मेल खाए, सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार प्रतिफलों पर आधारित है तथा वेतन वृद्धि के अंतर्गत, मुद्रास्फीति, वरीयता, पदोन्नति व अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है किंतु अयोग्यता के लिए किसी प्रत्यक्ष छूट का उपयोग नहीं किया जाता है :

	31 मार्च, 2015	31 मार्च 2014
डिस्काउंटिग दर	8.00% प्रति वर्ष	9.00% प्रति वर्ष
भावी वेतन वृद्धि	8.50% प्रति वर्ष	8.50% प्रति वर्ष
उपदान के लिए योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर (वित्तपोषित)	8.00% प्रति वर्ष	8.00% प्रति वर्ष

(ख) जनांकिकीय धारणा

	31 मार्च, 2015	31 मार्च 2014
सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम (2006–08) अन्ततः	आईएएलएफ (2006–08) अन्ततः
वापसी दर (प्रतिवर्ष)	2.00%	2.00%

7. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पुनः तैयार, पुनः समूहकृत, पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

अनुसूची 1 से 18 तक के हस्ताक्षरकर्ता

(अल्का मट्टा)
सचिव

(डा. रथिन रॉय)
निदेशक

(डा. विजय केलकर)
अध्यक्ष

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

सिंह कृष्णा एसोसिएट्स की ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 008714सी

(कृष्ण कुमार सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 077494

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16/10/2015